हरिभूमि

मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा व दिल्ली से एक साथ प्रकाशित

समाचार ही नहीं, विचार भी

लोकसभा चुनाव 2024

किस राज्य में कितनी सीटें?

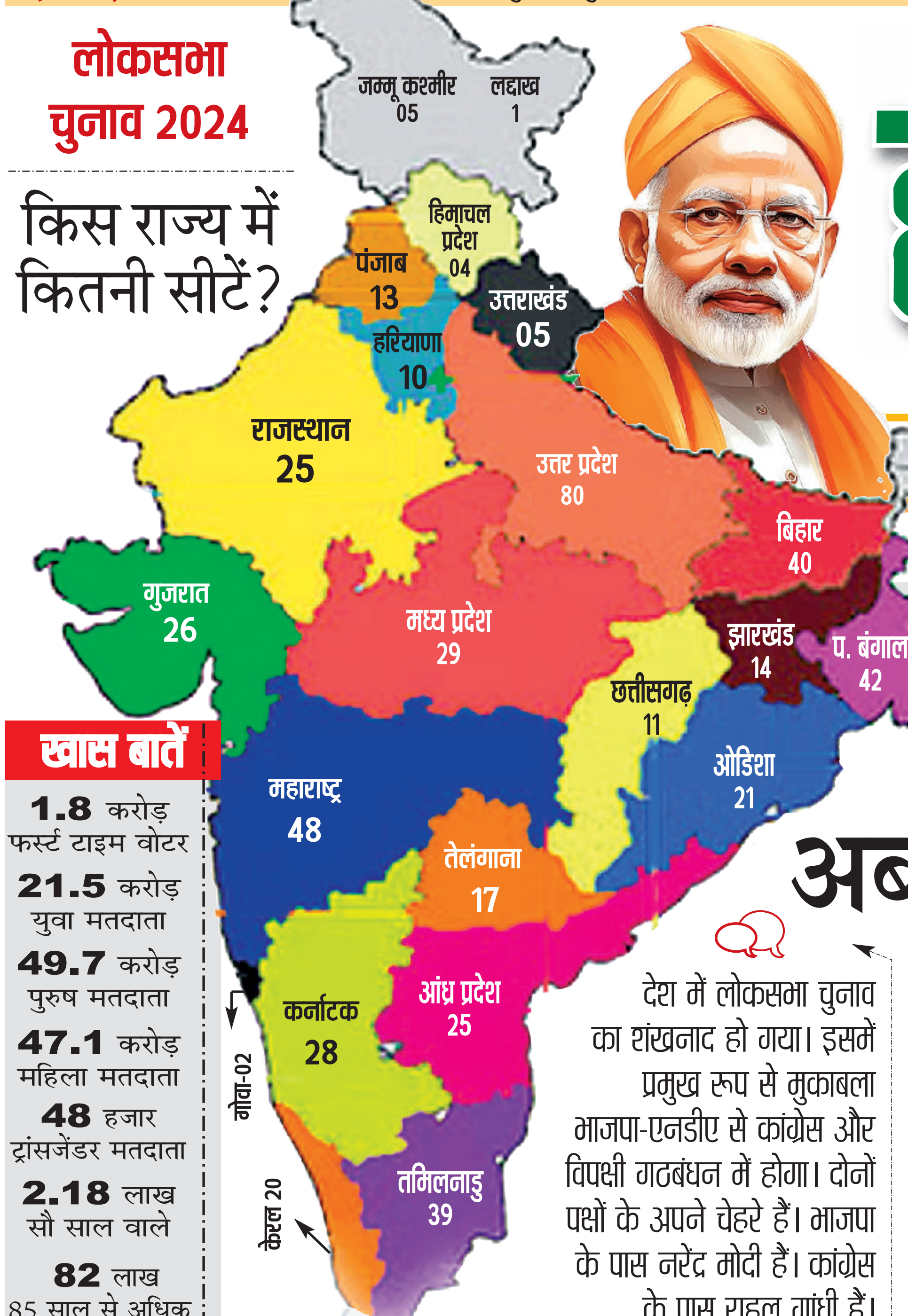

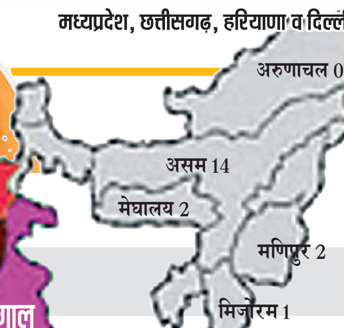

लोकसभा 7 चरण	अप्रैल	अप्रैल	मई	मई	मई	मई	जून
	19	26	07	13	20	25	01
	सीटें 102	सीटें 89	सीटें 94	सीटें 96	सीटें 49	सीटें 57	सीटें 57

परिणामः 04 जून 2024

7 चरण की 'जंग' लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान

19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में होंगे चुनाव और परिणाम 4 जून को, 97 करोड़ मतदाता करेंगे फैसला

अब 'जय' बोलो 'जन-मन' की

देश में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू, सरकार ऐसा कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकेगी, जो मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर सके

देश में 10.5 लाख से अधिक मतदान केंद्र होंगे और 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल होगा

देश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया। इसमें प्रमुख रूप से मुकाबला भाजपा-एनडीए से कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन में होगा। दोनों पक्षों के अपने चेहरे हैं। भाजपा के पास नरेंद्र मोदी हैं। कांग्रेस के पास राहुल गांधी हैं।

खास बातें

- **1.8** करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर
- **21.5** करोड़ युवा मतदाता
- **49.7** करोड़ पुरुष मतदाता
- **47.1** करोड़ महिला मतदाता
- **48** हजार ट्रांसजेंडर मतदाता
- **2.18** लाख सौ साल वाले
- **82** लाख 85 साल से अधिक
- **88.5** लाख दिव्यांग वोटर

दिल्ली की 7 सीटों पर एक साथ 25 मई को, 1 सीट के लिए लक्षदीप व पुडुचेरी में 19 अप्रैल, लद्दाख में 20 मई, चंड़ीगढ़ में 1 जून को चुनाव होंगे।

मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और नई लोकसभा का गठन उससे पहले होना है

बोले पीएम मोदी...

लोकसभा चुनाव के साथ होंगे 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी

लोकसभा चुनाव के साथ अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव होंगे। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही इन चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। ओडिशा में चार चरणों में वोटिंग होगी। पहला चरण-13 मई। दूसरा चरण-20 मई। ▶▶ शेष पेज 5 पर

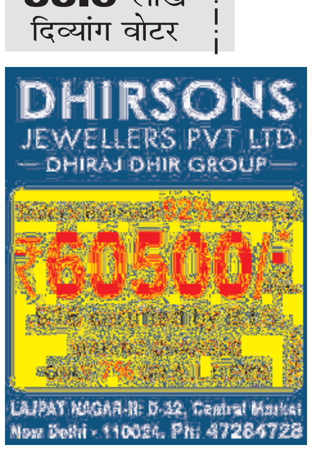

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

भारत के निर्वाचन आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों की घोषणा कर दी। इस बार चुनाव 19 अप्रैल से एक जून के बीच सात चरणों में होंगे और मतगणना चार जून को होगी। यानी, 4 जून को ही नतीजे आ जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही देश में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके ▶▶ शेष पेज 5 पर

भारत समृद्ध- आत्मनिर्भर बन सकता है, हम इसी भावना को आगे बढ़ाएंगे

चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आ गया है। हम, भाजपा-एनडीए, चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दस साल पहले हमारे सत्ता संभालने से पहले भारत के लोग दयनीय शासन के कारण ठगा हुआ और निराश महसूस कर रहे थे। कोई भी क्षेत्र घोटालों और नीतिगत पंगुता से अछूता नहीं रहा। विश्व ने भारत का साथ छोड़ दिया था। वहां से यह एक शानदार बदलाव रहा है। 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति के चलते हमारा देश विकास के नए रिकॉर्ड बना रहा है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। हमारी योजनाएं भारत के सभी हिस्सों तक पहुंची हैं और अच्छे परिणाम मिले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे तीसरे कार्यकाल में बहुत काम किया जाना बाकी ▶▶ शेष पेज 5 पर

किस चरण में कितने राज्य

प्रथम चरण - 21 राज्य

19 अप्रैलः 102 सीट

अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी की कुल 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।

दूसरा चरण-13 राज्य

26 अप्रैल : 89 सीट

असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर।

तीसरा चरण-12 राज्य

07 मई : 94 सीट

असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर नागर हवेली और दमन दीव।

चौथा चरण-10 राज्य

13 मई : 96 सीट

आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर।

पांचवां चरण -8 राज्य

20 मई : 49 सीट

छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रेदश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख।

छठा चरण-7 राज्य

25 मई : 57 सीट

बिहार, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की कुल 57 सीटों पर मतदान होगा।

सातवां चरण-8 राज्य

01 जून : 57 सीट

बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़।

दिल्ली यातायात पुलिस ने आज मैराथन को लेकर एक परामर्श जारी किया

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली यातायात पुलिस ने यहां रविवार को जवाहर लाल नेहरू (जेएलएन) स्टेडियम में आयोजित होने वाली मैराथन को लेकर एक परामर्श जारी किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक रविवार को जेएलएन स्टेडियम में 'रन फॉर गुड हैपनिंग' मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मैराथन में दिल्ली के सभी हिस्सों से लगभग 2,000 लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। दिल्ली की यातायात पुलिस की ओर से जारी परामर्श के मुताबिक रविवार को सुबह छह बजे से 8.30 बजे तक भीष्म पितामह मार्ग, कोटला रेड लाइट, लोधी रोड, जोर बाग रोड, दयाल सिंह/सीजीओ रोड आदि पर आवश्यकता के अनुसार यातायात को विनियमित/परिवर्तित किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि यात्रियों से सहयोग करने और सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो सेवाओं का अधिकतम उपयोग करने का अनुरोध किया जाता है। परामर्श में कहा गया है कि अंतरराज्यीय बस अड्डा (आईएसबीटी), रेलवे स्टेशन और हवाईअड्डे की ओर जाने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे पर्याप्त समय के साथ सावधानीपूर्वक अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

चाकू से वार कर दिया वारदात को अंजाम

अवैध संबंधों के शक में महिला की जीजा ने कर दी हत्या

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

अलीपुर इलाके के सिंघु गांव में शुक्रवार रात एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतका का नाम रितू (32) बताया गया है। पति का नाम खरजू सिंह है। पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया गया। हत्या का आरोप महिला के जीजा पर है। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस उसे पकड़ने का प्रयास कर रही है।

पुलिस के अनुसार राजा हरिश्चंद्र अस्पताल, नरेला से सूचना मिली कि रितू निवासी जय गुरु धर्म कांटा, गांव सिंघु को चाकू लगने पर अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के साथ उसका पति खरजू और बहन मोनी भी आई थी। खरजू ने पुलिस को बताया कि मोनी के पति पूरन को उसके अवैध संबंधों का शक था। शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे रितू और मोनी कुंडली से काम करके घर पहुंची। पूरन भी चाकू लेकर सिंघु गांव स्थित उनके घर पहुंच गया। वह काफी नशे में था और उसने रितू और मोनी दोनों का चाकू लेकर पीछा किया। मोनी भागने में सफल रही लेकिन पूरन ने रितू की पीठ में चाकू घोंप दिया। इसके बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी पूरन को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी है।

बिजनेसमैन को मिठाई के डिब्बे में भेजा धमकी भरा पत्र व कारतूस

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

वसंत विहार इलाके में एक शख्स के घर मिठाई के डिब्बे में दो कारतूस और धमकी भरा पत्र भेजे जाने का मामला सामने आया है। पत्र में व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई है। शिकायत पुलिस से की गई है। घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही पीड़ति से बातचीत कर पता लगाया जा रहा है कि उनकी किसी से पुरानी रंजिश तो नहीं चल रही। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार दोपहर 3 बजकर 38 मिनट पर वसंत विहार थाने को एक पीसीआर कॉल के जरिए सूचना दी गई। बताया गया कि वसंत विहार डी ब्लॉक में मिठाई के डिब्बे में दो कारतूस और एक धमकी भरा पत्र भेजा गया है। पुलिस बिजनेसमैन के घर पहुंची। उनके दिल्ली एनसीआर में कई वेयर हाऊस हैं। उन्हें घर के दरवाजे पर बैग रखा मिला। बैग में मिठाई का डिब्बा था। डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें दो कारतूस और फूल के साथ हाथ से लिखा गया धमकी भरा पत्र था। मामले को लेकर आईपीसी की धारा 506 और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच के दौरान कुछ लोगों को शक की बिनाह पर हिरासत में भी लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।

पट्टा रूपांतरण योजना के दायरे में औद्योगिक भूखंडों को लाया गया

एजेंसी:नई दिल्ली

दिल्ली में छोटी और मझोली औद्योगिक इकाइयों को राहत देने के लिए उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने रूपांतरण योजना 2005 के दायरे में औद्योगिक भूखंडों को भी शामिल किया है। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि उपराज्यपाल ने कई शर्तों के साथ विस्तार के प्रस्ताव को 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी। इसमें कहा गया कि इस कदम से 1998 की पुनर्वास योजना के तहत डीएसआईआईडीसी द्वारा आवंटित किए गए औद्योगिक भूखंडों को 'लीजहोल्ड' से 'फ्रीहोल्ड' में बदलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस फैसले से लगभग 22,000 औद्योगिक इकाइयों या भूखंडों को सीधे लाभ होगा, जिन्हें 2000-2001 में दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) ने स्थानांतरित किया था। यह फैसला दिल्ली के उन उद्यमियों की मांग को देखकर लिया गया, जिन्हें इन भूखंडों को बेचने या हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं थी। भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति केवल उन औद्योगिक भूखंडों के मामले में दी जाएगी, जो मूल आवंटी के कब्जे में हैं और जहां भवन का निर्माण पूरा हो चुका है।

कार को टक्कर मारने के बाद दो बहनों ने किया हंगामा

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

पटेल नगर इलाके में एक कार को टक्कर मारने के बाद दो बहनों ने जमकर बवाल किया। दोनों बहनें नशे में धुत थी। पुलिस गुरुग्राम निवासी दोनों बहनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रही है। पुलिस को 21 वर्षीय स्नेहिल सचदेवा ने बताया कि वह पटेल नगर एरिया में रहते हैं और बीबीए स्टूडेंट है। रात करीब 11 बजे वह जिम करने के बाद होंडा सिटी कर से घर लौट रहे थे। ईस्ट पटेल नगर पहुंचने पर उनकी कार को बलेनो ने जोरदार टक्कर मार दी। उनकी कार घूमकर सामने से आ रही क्रेटा से टकरा गई। इस घटना के बाद बेलेनो कार चालक फरार होने लगा। स्नेहिल ने कार का पीछा किया। आगे बैरिकेडिंग की वजह से कार आगे नहीं बढ़ सकी तो उसे ओवर टेक कर रूकवाया। कार में दो लड़कियां सवार थी। बाहर निकलकर उन्होंने हंगामा करना शुरु कर दिया। आरोप है कि दोनों नशे की हालत में थी। पीड़ति ने पुलिस को कॉल कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें शांत करने की कोशिश की लेकिन दोनों बहनें कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। इसके बाद पुलिस दोनों पक्षों को पटेल नगर थाने ले गई। थाने के बाहर भी दोनों बहनें शांत नहीं हुई और वे पुलिस के सामने बवाल करती रही। पुलिस ने दोनों कारें जब्त कर ली है। आरोपी लड़कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

■ नशे में थी धुत

अदालत ने ईडी के समन पर पेश न होने से जुड़े मामले में केजरीवाल को जमानत दी

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में समन पर पेश न होने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज करायी दो शिकायतों के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शनिवार को जमानत दे दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने केजरीवाल को अदालत कक्ष से जाने की अनुमति भी दे दी। अदालत ने कहा कि अपराध जमानती होने के कारण आरोपी अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है। अदालत ने ईडी को केजरीवाल को शिकायतों से जुड़े दस्तावेज भी सौंपने का निर्देश दिया।

ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत में दो शिकायतें दर्ज कराते हुए इस मामले में केजरीवाल को जारी कई समन पर पेश होने के लिए उन पर अभियोग चलाने का अनुरोध किया था। ताजा शिकायत धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे समन संख्या 4 से 8 का आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल द्वारा सम्मान न करने जुड़ी है। ईडी ने इससे पहले मजिस्ट्रेट अदालत का रुख करके अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में केजरीवाल को जारी पहले तीन समन पर पेश न होने के लिए उन पर मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था।

केजरीवाल को जमानत लेने से स्थापित हो गया कि समन संवैधानिक व कानूनी रूप से सही थे : सचदेवा

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने शनिवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के समन की अवहेलना के मामले में न्यायालय में दायर धारा 174 की याचिका में जमानत लेनी पड़ी जिसका मतलब है कि केजरीवाल का पेश होना जरूरी था और अब ईडी के अगले समन पर पेश होना जरूरी होगा। ईडी समन अवहेलना मामले में जमानत लेना दर्शाता है कि उन्हें पेश होना अनिवार्य था और उन्होंने पेश न हो कर गलत किया। सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल लगातार कहते थे सम्मन गैरकानूनी है पर आज उनके जमानत लेने से स्थापित हो गया की समन संवैधानिक रूप कानूनी रूप से सही थे। सचदेवा ने कहा है न्यायालय के विस्तृत निर्णय से स्थिति और साफ होगी पर प्रथम दृष्टा यह तय है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के नौवें समन के सामने पेश होना होगा, शराब घोटाले की जांच में शामिल होना होगा।

ब्लैकमेल और जबरन वसूली आरोपी को किया गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

शाहदरा पुलिस ने जबरन वसूली करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से अपराध में इस्तेमाल किया गया एक मोबाइल फोन भी बरामद हो गया है। इस पर एक महिला को मेकअप आर्टिस्ट की नौकरी दिलवाने का झांसा देकर नजदीकियां बढ़ाने और बाद में ब्लैकमेल कर जबरन वसूली के प्रयास का आरोप है।

पुलिस के अनुसार घटना 14 मार्च को शाहदरा पुलिस के संज्ञान में आई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे परवीन उर्फ विशु नामक व्यक्ति का फोन आया था। उसने 25 हजार रुपये माह पर मेकअप आर्टिस्ट की नौकरी दिलाने का प्रलोभन दिया। इसके बाद, कथित व्यक्ति ने नियमित आधार पर फोन कॉल और संदेशों के माध्यम से शिकायतकर्ता के साथ संवाद करना शुरू कर दिया। उसका विश्वास हासिल करने के बाद उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। आरोपी ने एक दिन वीडियो कॉल के दौरान उसकी अश्लील तस्वीर का स्क्रीन शॉट ले लिया। बाद में उससे 10 हजार रुपये की मांग करने लगा। रुपये न देने पर सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड की धमकी दी जाने लगी। आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जांच के दौरान 15 मार्च को आरोपी परवीन उर्फ विशु निवासी वीपीओ नागपुर, जिला फतेहाबाद, हरियाणा को अरेस्ट कर लिया गया। आरोपी 10वीं तक पढ़ा है और पेशे से नाई है।

नगर निगम दिल्ली में 3 हजार नई सड़कों का करेगा निर्माण : ओबरॉय

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

महापौर फंड से दिल्ली में 3 हजार सड़कों को निर्माण किया जाएगा। यह बात शनिवार को दिल्ली की महापौर डॉ शैली ओबरॉय ने कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली की कालोनियों में जल्द टूटी सड़कों की समस्या का जल्द समाधान होगा। निगम की ओर से पहली बार बड़े स्तर पर कॉलोनी की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। अभा तक मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत ही कॉलोनियों में सड़कों का निर्माण होता था। लेकिन पहली बार मेयर के फंड से दिल्ली में 3 हजार सड़कों का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली की महापौर डॉ शैली ओबरॉय ने प्रैसवार्ता में कहा कि दिल्ली नगर निगम में काबिज़ आम आदमी पार्टी की सरकार नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। निगम के बजट में एक हज़ार करोड़ रुपये का बजट दिल्ली में सड़कों के निर्माण के लिए नियत किया गया था। मैं इस बात का वादा करती हूं कि इस एक हज़ार करोड़ और 500 करोड़ के मेयर फंड से पूरी दिल्ली में लगभग 3000 सड़कों का निर्माण किया जायेगा। दिल्ली कि तमाम गलियां, फ़्रैंट लेन, बैक लेन बनाई जाएगी और किसी भी सड़क पर गड्ढे नज़र नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी को सत्ता में आए लगभग 1 साल का समय हुआ है। इस एक साल में हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में विकासात्मक कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। हमने नये स्कूल, पार्क, मेटरनिटी सेंटर, पार्किंग स्थल बनाये और कई का शिलान्यास किया। हमने निगम कर्मचारियों को पक्का करने की प्रक्रिया शुरू की साथ ही नए जॉब के अवसर भी शुरू किये।

निगम में भाजपा ने 15 साल तक कुछ नहीं किया

महापौर डॉ शैली ओबरॉय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 सालों से कोई काम नहीं किया। उनकी मंशा आम आदमी पार्टी के काम में रोड़ा अटकाने की ही रही है। दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति का निर्माण नहीं होने दिया और निगम की सदन की बैठक को कभी भी शांतिपूर्ण तरीके से नहीं चलने दिया। भारतीय जनता पार्टी को यह समझना होगा कि आम आदमी पार्टी रुकने वाली नहीं है और विकास के एजेंडे पर लगातार कार्य करती रहेगी।

नगर निगम कितनी भी घोषणा कर ले, लोकसभा चुनाव में तय है आप-कांग्रेस की हार : राजा इकबाल

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम कितनी भी घोषणा ले लेकिन लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस की हार तय है। यह बात शनिवार को दिल्ली नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह ने कही। दिल्ली नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह ने महापौर के उस दावे पर निशाना साधा है जिसमें तीन हजार सड़कों को बनाने की बात कही है। राजा इकबाल सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों की हार देखते हुए आप पार्टी बौखला गई है। क्योंकि जनता का कोई समर्थन आप को नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं जनता टूटी सड़कों, गंदे पानी और पार्कों की बदहाल स्थिति से आप सरकार से नाराज है। निगम में दस गारंटी चुनाव से पहले दी थी एक भी गारंटी एक साल में पूरी नहीं हुई। इसलिए लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले महापौर को सड़कों का निर्माण कराने की घोषणा करनी पड़ी। जबकि यह घोषणा केवल चुनावी है और इसमें कोई फाइलों पर कोई मंजूरी नहीं मिली है। राजा इकबाल सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस के प्रत्याशियों की हार निश्चित हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप सरकार की वादाखिलाफी पर जनता इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट देकर बदला लेगी।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश रामसुब्रमण्यम जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों को लेकर गठित चुनाव समिति की गतिविधियों पर निगरानी रखने के सिलसिले में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश वी. रामसुब्रमण्यम को 'पर्यवेक्षक' नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने एक छात्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार गठित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले चुनाव समिति के गठन से संबंधित शिकायतों की जांच करने और आदेश पारित करने का निर्देश भी दिया। न्यायमूर्ति दत्ता ने शुक्रवार को पारित एक आदेश में कहा, "यदि यह पाया जाता है कि ईसी (चुनाव समिति) का गठन कानून या (उच्चतम न्यायालय से अनुमोदित) लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप नहीं है, तो शिकायत निवारण कक्ष विवादित चुनावों के संबंध में उचित परिणामी आदेश भी पारित करे। अदालत ने कहा, पक्षकारों के संबंधित वकील इस बात पर भी सहमत हैं कि इस बीच जारी चुनाव प्रक्रिया के प्रयोजन के लिए, उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को यह अदालत पर्यवेक्षक नियुक्त करे ताकि वह गतिविधियों/कार्यों पर नजर रख सके। इसलिए भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री वी. रामसुब्रमण्यम को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। जेएनयूएसयू चुनाव 22 मार्च को होने हैं और परिणाम 24 मार्च को घोषित किए जाएंगे।

35 उम्मीदवारों को अध्यक्ष पद के लिए किया पात्र घोषित

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की चुनाव समिति ने 141 पात्र उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जो आगामी छात्र संघ चुनाव में केंद्रीय पैनल के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) के केंद्रीय पैनल में चार पद हैं जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव का पद शामिल है। वर्ष 2023-24 के जेएनयूएसयू चुनावों के लिए चुनाव समिति ने अध्यक्ष पद के लिए 35, उपाध्यक्ष पद के लिए 37, महासचिव पद के लिए 38 और संयुक्त सचिव पद के लिए 31 उम्मीदवारों को पात्र घोषित किया। चुनाव समिति (ईसी) ने उन छात्रों के नाम जारी किए जिनकी उम्मीदवारी जेएनयू छात्र संघ के केंद्रीय पैनल के वास्ते चुनाव लड़ने के लिए वैध पाई गई है। इसके अलावा, चुनाव समिति ने 171 उम्मीदवारों की एक सूची भी जारी की है, जो विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों से काउंसलर पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए पात्र हैं। समिति के आंकड़े के मुताबिक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लगभग 20 स्कूल के छात्र आगामी चुनावों में भाग लेंगे। आज अपराह्न तीन बजे चुनाव समिति अंतिम सूची जारी करेगा।

रिश्तेदार बनकर बुजुर्ग को लगाया चार लाख का चूना

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

नार्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के पीतमपुरा में एक 88 वर्षीय बुजुर्ग से जालसाज ने रिश्तेदार बनकर चार लाख की ठगी कर ली। दरअसल उन्हें 16 लाख भेजने के बहाने यह चपत लगायी। शिकायत पर जिले की साइबर टीम केस दर्ज कर जालसाज के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस को दी शिकायत में बुजुर्ग ने बताया कि 19 फरवरी को उनके पास एक विदेशी नंबर से फोन आया। उन्हें बताया गया कि वह रिश्तेदार बिट्टू बोल रहा है। उसने बुजुर्ग को 16 लाख रुपए ट्रांसफर करने की बात कही। यह रकम एक दिन में मिल जाने का झांसा दिया गया। बुजुर्ग को उस दिन रुपए नहीं मिले लेकिन जालसाज ने वीजा एजेंट को देने के नाम पर उनसे चार लाख रुपए मांग लिए। रिश्तेदार को मुसीबत में फंसा देख पीड़ति बुजुर्ग ने अपने दो बैंक अकाउंट से दो दो लाख रुपए उसे ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद जब जालसाज ने फिर से रुपयों की मांग की तो बुजुर्ग को शक हो गया। इसके बाद पीड़ति बुजुर्ग ने लुधियाना में रहने वाले अपने भाई को कॉल कर बिट्टू के बारे में पूछा। उन्हें बताया गया कि बिट्टू की ओर से उन्हें कोई फोन नहीं किया गया है। धोखे का पता चलने पर पीड़ति बुजुर्ग ने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि रकम गौरव कुमार नामक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में गई थी।

■ साइबर पुलिस टीम केस की जांच में जुटी

केजरीवाल ने की दिल्ली में रेहड़ी-पटरी वालों का सर्वेक्षण कराने की घोषणा

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों को दुकान के लिए जगह देने के लिए दिल्ली नगर निगम से सर्वे कराने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक एवं सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवालों को यह खुशखबरी देते हुए बताया कि पूरी दिल्ली में सभी रेहड़ी-पटरी पर दुकान लगाने वालों का सर्वे कराया जाएगा और उनको दुकान लगाने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। ये लोग भी हमारे भाई-बहन हैं और उनको अच्छी व्यवस्था देना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि वो लोग भी इज्जत के साथ अपना काम कर सकें। इस सर्वे के बाद ये लोग बिना किसी परेशानी के अपनी दुकान लगा सकेंगे। इसके बाद पुलिस, कमेटी या अफसर उनको परेशान नहीं कर सकेंगे।

सीएम केजरीवाल ने शनिवार को एक वीडियो जारी कर कहा कि

जब से दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हम

- सर्वे के बाद ये लोग बिना परेशानी के अपनी दुकान लगा सकेंगे, फिर पुलिस, कमेटी या अफसर उनको नहीं कर सकेंगे परेशान : सीएम

एक के बाद एक बड़े निर्णय ले रहे हैं। निगम की 'आप' सरकार ने अब तक कई बड़े निर्णय लिए हैं और बहुत सारे काम किए हैं। दिल्ली के रेहड़ी-पटरी वाले सभी भाई-बहनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हम समझते हैं कि सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी लगाकर काम करना कितना मुश्किल होता है। रेहड़ी पटरी वालों को कभी पुलिस परेशान करती है, कभी कमिटी तो कभी अफसर आकर परेशान करते हैं।

हम चाहते हैं कि आपको इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिले और इज्जत की जिंदगी मिले। रेहड़ी पटरी वाले भी इज्जत के साथ अपना काम कर सकें और अपनी दुकान लगा सकें। सीएम केजरीवाल ने कहा कि रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले भी हमारे भाई-बहन हैं और वो बेहद गरीब परिवार से आते हैं। वो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए छोटे-मोटे काम करने के लिए मजबूर हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को भी अच्छी व्यवस्था दें ताकि वो भी अपने परिवार को भरण पोषण अच्छे से कर सकें और इज्जत के साथ अपना काम-धंधा कर सकें। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि सभी रेहड़ी-पटरी की दुकानों का एक सर्वे कराया जाएगा। जहां पर रेहडी पटरी की दुकानें हैं, उनका सर्वे होगा कि कितने दुकानदार किस एरिया में हैं, कौन कहां बैठता है, किस-किस तरह की दुकानें लगती हैं। इसके बाद उनके लिए सम्मान जनक अपनी दुकान लगाने का इंतजाम करेंगे।

सीएम केजरीवाल ने कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों के सर्वे मे कुछ महीने लगेंगे।

केजरीवाल रेहड़ी पटरी वालों को गुमराह करने की कर रहे हैं कोशिश : सचदेवा

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा रेहड़ी पटरी वालों को दुकान के लिए जगह देने की घोषणा पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शनिवार को कहा कि केजरीवाल लोगों और खासकर रेहड़ी पटरी वालों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सचदेवा ने प्रैसवार्ता में रेहड़ी पटरी वालों को गुमराह करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की निंदा की है।

खबर संक्षेप

अदालत ने महरौली में अखूंदजी मस्जिद स्थल पर नमाज की अनुमति देने से किया इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने महरौली में हाल में ध्वस्त की गई 'अखूंदजी मस्जिद' में रमजान के दौरान नमाज की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने मुंतजमिया कमेटी मदरसा बेहरुल उलूम और कब्रिस्तान की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने पिछले महीने शब-ए-बारात के मौके पर श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया था और अब इस संबंध में कोई अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई औचित्य नहीं है। अदालत ने अपने हाल के आदेश में कहा कि गत 23 फरवरी का आदेश के मौजूदा आवेदन के संदर्भ में भी लागू होता है और इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय के लिए अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई औचित्य नहीं है। अदालत ने कहा कि इस प्रकार, यह न्यायालय वर्तमान आवेदन में मांगी गई राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है और परिणामस्वरूप इसे खारिज कर दिया गया है। मान्यताओं के अनुसार लगभग 600 साल प्राचीन 'अखूंदजी मस्जिद' और साथ ही वहां के बेहरुल उलूम मदरसे को संजय वन में अवैध निर्माण घोषित किया गया था और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 30 जनवरी को इसे ध्वस्त करा दिया था।

दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से पांच डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी। मौसम विभाग ने दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक, सुबह साढ़े आठ बजे आर्द्रता 70 प्रतिशत दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सुबह नौ बजे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 147 दर्ज किया गया जो ‍मध्यम‍ श्रेणी में है। शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को 'मध्यम', 201 से 300 के बीच को 'खराब', 301 से 400 के बीच को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है।

'सोलर पैनल लगाने वालों को जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव देगी दिल्ली सरकार'

दिल्ली में सोलर पॉलिसी लागू, सभी परिवारों का बिजली बिल आएगा जीरो : आतिशी

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली में सोलर पॉलिसी 2023 लागू हो गई है। इसकी अधिसूचना शनिवार को दिल्ली सरकार ने जारी कर दी है। इससे दिल्लीवालों के बिजली का बिल जीरो आने का रास्ता साफ हो गया है। यह दावा दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने शनिवार को किया है। आतिशी ने कहा कि अब दिल्ली के लोग पॉलिसी के तहत अपने घर की छतों पर सोलर पैनल लगवाकर अपना बिजली का बिल जीरो कर सकते हैं। साथ ही, इससे हर महीने अच्छी आमदनी भी कर सकते हैं। इसके अलावा, सोलर पैनल लगवाने में आने वाला खर्च अगले चार साल में रिकवर हो जाएगा।

बता दें कि 29 जनवरी को सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सोलर पॉलिसी की घोषणा की थी। सरकार ने इसकी फाइल एलजी को भेजी थी। करीब एक महीने के इंतजार के बाद एलजी से मंजूरी मिली और अब यह पॉलिसी लागू कर दी गई है। दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी का कहना है कि इस पॉलिसी के लागू होने से न केवल दिल्ली वालों को फायदा होगा, बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पॉलिसी के तहत हर यूनिट बिजली उत्पादन करने पर दिल्ली सरकार रूफटॉप सोलर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को पैसे देगी। इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं का बिजली का बिल जीरो आएगा, बल्कि वो अपने छत पर लगे रूफटॉप सोलर पावर प्लांट से पैसे भी कमा सकते है। हमारा लक्ष्य है कि 2027 तक दिल्ली में इस्तेमाल होने वाली कुल बिजली में 50 फीसद बिजली सोलर एनर्जी से आए।

दिल्ली सोलर पॉलिसी 2023 से पहले दिल्ली सरकार ने दिल्ली सोलर पॉलिसी 2016 जारी की थी, जो पूरे देश में सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी मानी गई। एक तरह से सोलर पॉलिसी 2016 ने दिल्ली में सोलर पावर की मजबूत बुनियाद रखी। इसके तहत दिल्लीवालों ने अब तक अपने घर की छतों पर 250 मेगावॉट क्षमता के सोलर पैनल लगवाए हैं। सोलर पॉलिसी 2016 के तहत डिस्कॉम ने 1250 मेगावॉट सोलर पावर बाहर से खरीदी है। इस तरह, सोलर पॉलिसी 2016 के तहत दिल्ली के अंदर अब तक करीब 1500 मेगावॉट सोलर पावर स्थापित हुई है। दिल्ली सोलर पॉलिसी का फायदा आवासीय सेक्टर के अलावा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। इस पॉलिसी के तहत कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ता सोलर पैनल लगवाते हैं तो उनके बिजली का बिल आधा (50 फीसद कम) हो जाएगा। क्योंकि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को भी पांच साल तक एक रुपए प्रति यूनिट जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा, नई पॉलिसी के तहत सोलर पैनल लगवाने पर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन को पांच साल तक 2 रुपए प्रति यूनिट जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। दिल्ली सरकार सोलर पॉलिसी के अंतर्गत 5 तरह के वित्तीय लाभ देगी। अगर कोई उपभोक्ता 3 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगवाता है तो उससे पैदा होने वाली बिजली पर दिल्ली सरकार आपके बैंक खाते में 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से जमा करेगी। अगर कोई उपभोक्ता 3 से 10 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगवाता है तो 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से पैसा जमा कराएगा। दिल्ली सरकार पांच साल तक यह जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव देती रहेगी। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद अगले तीन साल के अंदर (2027 तक) दिल्ली में 4500 मेगावॉट सोलर पावर की क्षमता स्थापित हो जाएगी। इसमें से 750 मेगावॉट क्षमता के सोलर पैनल छत के उपर लगाए जाएंगे, जबकि 3750 मेगावॉट डिस्कॉम बाहर से सोलर पावर खरीदेंगे। आज दिल्ली में 1500 मेगावॉट सोलर पावर की क्षमता है, जिसे अगले तीन साल में तीन गुना तक बढ़ाकर 4500 मेगावॉट तक ले जाएंगे।

दिल्ली सोलर पॉलिसी का लक्ष्य

दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 के मुख्यतः दो लक्ष्य हैं। पहला, दिल्ली को पूरे भारत में सौर ऊर्जा अपनाने के मामले में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। जिससे दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। दूसरा, गैर-सब्सिडी वाले आवासीय उपभोक्ताओं के बिजली बिलों को जीरो और कमर्शियल व औद्योगिक उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 50 फीसद तक कम करना है। इसके अलावा, मार्च 2027 तक दिल्ली की कुल स्थापित सौर क्षमता को मौजूदा क्षमता 1500 मेगावाट से तीन गुना बढ़ाकर 4,500 मेगावाट करना है।

सोलर पॉलिसी से वायु प्रदूषण को कम करने में मिलेगी मदद

आतिशी ने कहा कि सरकार का मानना है कि सोलर पॉलिसी से वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ईवी पॉलिसी भी बनाई है, जो देश की सबसे प्रोग्रेसिव ईवी पॉलिसी है और आज दिल्ली को ईवी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। दिसंबर 2023 में दिल्ली में कुल खरीदे गए वाहनों में से करीब 20 फीसद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है।

'400 यूनिट से अधिक बिजली खपत पर भी बिल आएगा जीरो'

दिल्ली सोलर पॉलिसी 2023 तहत सोलर पैनल लगवाने पर 400 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वालो का भी बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने कई सब्सिडी का प्रावधान भी किया है। अगर आवासीय क्षेत्र में कोई उपभोक्ता 360 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर रहा है, तो वो 201 से 401 यूनिट वाले स्लैब में आता है और उसका बिजली का बिल आधा आ रहा है। अगर वो उपभोक्ता दो किलोवॉट का रूफ टॉप सोलर पैनल लगवाता है तो उसे लगाने में 90 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसके बाद उस उपभोक्ता का बिजली का बिल जीरो आने लगेगा और उसका हर महीने 1370 रुपए बचने लगेंगे। इसके अलावा, दिल्ली सरकार हर महीने 700 रुपए जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव देगी। इससे उस उपभोक्ता की 700 रुपए हर महीने अतिरिक्त आमदनी होने लगेगी। दोनों को मिलाकर उस उपभोक्ता की हर महीने करीब 2000 रुपए की बचत होगी। इस तरह साल भर में 24 हजार रुपए बचेंगे और 4 साल के अंदर 90 हजार रुपए का निवेश रिकवर हो जाएगा।

एलजी ने रोशनआरा बाग के कायाकल्प कार्य के बीच अधिकारियों सहित किया दौरा

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रोशनआरा बाग के कायाकल्प के चल रहे कार्य के बीच अधिकारियों सहित शनिवार को दौरा किया। इस मौके पर एलजी ने बाग के बेहतरीन तरीके से किए जा रहे कायाकल्प के लिए डीडीए की सराहना की। इस मौके पर डीडीए व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। एलजी ने अपने इस दौरे को लेकर अपने अधिकृत सोशल मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी। एलजी ने अपनी पोस्ट में करीब दो साल पहले कायाकल्प से पूर्व के दौरे और वहां की बदहाली और अब कायाकल्प के बाद यानी की वर्तमान की फोटो भी पोस्ट कर फर्क दिखाने की कोशिश की है। एलजी ने लिखा कि मेरी पहली यात्रा18 जून 22 के दौरान ऐतिहासिक रोशनआरा बाग के कायाकल्प की योजना के तहत हो रहे विकास का रोशनआरा बाग में बदलाव दिखाई देने लगा है। दिल्ली जैसे शहर के

मध्य में एक झील, उद्यान, नर्सरी, पैदल मार्ग और सार्वजनिक उपयोगिताओं के साथ 57 एकड़ की इस संपत्ति के जीर्णोद्धार और कायाकल्प के लिए डीडीए का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने लिखा कि बेगम रोशनआरा की विरासत मकबरा को उसकी महिमा में बहाल किया जा रहा है और इसके आसपास के पार्क को फूलों और पौधों से सजाया जाएगा। जलस्रोत धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से वास्तविक स्वरूप वाले जीवन में आ रहा है। उन्होंने लिखा कि उत्तरी दिल्ली को राजधानी के नए गंतव्य का बेसब्री से इंतजार है।

जहां झुग्गी वहीं मकान के तहत जेलर वाला बाग में तीन जेजे क्लस्टरों के 1396 फ्लैट किए गए आवंटित : डीडीए

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना, जहां झुग्गी वहीं मकान स्वस्थाने पुनर्वास स्कीम के तहत अशोक विहार में जेलर वाला बाग में तीन जेजे क्लस्टरों के लोगों को कुल 1675 फ्लैटों में से 1396 फ्लैट आवंटित किए गए है। यह पूरी प्रक्रिया उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अगुवाई में पूरी की गई है। डीडीए द्वारा दी गई जानकारी अनुसार पीएम मोदी का सपना है कि झुग्गीवासियों को आधुनिक फ्लैट और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए उन्हें फ्लैट आवंटित किए जाए। डीडीए ने बताया कि पीएम के इसी सपने को एलजी की अगुवाई में पूरा किया जा रहा है। जिसके तहत जेलर वाला बाग परियोजना के अपने दौरे और उसके बाद की समीक्षा बैठकों के दौरान

एलजी ने पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द फ्लैट आवंटित करने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी किए थे। ऐसे पात्र जेजे निवासियों को 25 लाख रुपये प्रति फ्लैट की निर्माण लागत के स्थान पर लाभार्थी योगदान के रूप में केवल 1.41 लाख रुपये पर ही आवंटन किया जा रहा है। डीडीए की माने तो इन फ्लैटों में सभी आधुनिक सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे, सामुदायिक सुविधाएं, सीवरेज शोधन, साफ और स्वच्छ पेयजल आदि की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इस स्कीम को औपचारिक रूप से उपाध्यक्ष (डीडीए) द्वारा अनुमोदित किया गया है। तदनुसार, एक ड्रा आयोजित किया गया और पात्र जेजे निवासियों को विशेष फ्लैट आवंटित किए गए। डीडीए का कहना है कि इन 1396 फ्लैटों में से 1078 फ्लैट जेलर वाला बाग जेजे क्लस्टर के पात्र झुग्गीवासियों को आवंटित किए गए हैं। जबकि 318 फ्लैट पास के दो जेजे क्लस्टरों अर्थात गोल्डन पार्क रामपुरा और अशोक विहार में माता जय कौर पब्लिक स्कूल के सामने जेजे क्लस्टर के पात्र परिवारों को आवंटित किए गए हैं। जहां झुग्गी वहीं मकान स्कीम के तहत, कालकाजी स्वस्थाने पुनर्वास परियोजना के बाद, ये फ्लैट सबसे गरीब लोगों के सम्मानजनक जीवन के लिए पीएम मोदी के समावेशी विजन को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

मोदी सरकार ने जेलरवाला बाग में गरीबों को फ्लैट आवंटन कर वादा किया पूरा : सचदेवा

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने शनिवार को कहा कि दिल्ली के अंदर जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत मोदी सरकार ने दिल्ली के गरीबों को चांदनी चौक के जेलर वाला बाग में 1078 फ्लैट तैयार करके आज अलॉटमेंट लेटर प्रदान किए। सचदेवा ने कहा कि गोल्डन पार्क, रामपुरा, अशोक विहार इत्यादी मे भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 1500 परिवारों को चिन्हित किया गया है उन्हें फ्लैट का लाभ मिलेगा। आज जो 1078 फ्लैट दिए गए हैं इससे सीधे तौर पर 8500 लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो कहा वह कर के दिखाया और जैसे कालकाजी स्थित झुग्गियों में रहने वालों को मकान दिया गया वैसे ही अब जेलर वाला बाग में भी गरीब भाईयों को फ्लैट दिया जाएगा। सचदेवा ने दिल्ली के उपराज्यपाल का आभार व्यक्त किया जिनके पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के कलन्दर कॉलोनी, दीपक कॉलोनी और दिलशाद कॉलोनी में रहने वाले 4000 लोगों के लिए भी जगह अलॉट कर दी गई है और जल्द ही उनके लिए भी मकान बनाने का काम मोदी सरकार करेगी।

जनता के पास अपनी आवाज उठाने का एकमात्र अवसर बचा है चुनाव : राय

इंडिया गठबंधन चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार : आप

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी (आप) ने केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने का स्वागत करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस संबंध में आप के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि इस बार तानाशाही के खिलाफ वोट करें, गुंडागर्दी के खिलाफ वोट करें। आम आदमी पार्टी लोगों के असल मुद्दों पर काम करती है, जनता को सहूलियत देती है। जहां-जहां आप के उम्मीदवार चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं वहां झाड़ू पर वोट देकर हमारे हाथ

मजबूत करें ताकि हम और अधिक ऊर्जा से आपके लिए काम कर सकें। वहीं लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद आप के दिल्ली प्रदेश संयोजक और मंत्री गोपाल राय ने चुनावों की तारीखें की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि देश की जनता भी इस चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। क्योंकि भाजपा ने पिछले 10 साल में जिस तरह से बहुमत के अहंकार में संविधान की धज्जियां उड़ाईं, जिस तरह से भारतीय लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की गई, जनादेश को नकारते हुए पैसे, ईडी और सीबीआई के दम पर लोगों को धमकाया। यहां तक कि दिल्ली सरकार की शक्तियों और अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले की धज्जियां उड़ा दी गईं और फैसले को पलट दिया गया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सरेआम वोटों की चोरी करके चुनाव जीतने की कोशिश की गई। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला सामने आया है कि किस तरह से कंपनियों को टारगेट कर आईटी, ईडी और सीबीआई की रेड डाल कर पैसों की वसूली की गई। आज सड़कों पर आए किसानों से वादा किया गया कि एमएसपी गारंटी कानून लेकर आएंगे।

व्यापारियों को कांग्रेस के लिए लामबंद करेंगे अरोड़ा, लवली ने बनाया ट्रेडर्स कांग्रेस का अध्यक्ष

नई दिल्ली। लोकसभा चुनावों में व्यापारियों को कांग्रेस पार्टी के लिए लामबंद करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने व्यापारी नेता अजय अरोड़ा को जिम्मेदारी सौंपी है। लवली ने अरोड़ा को दिल्ली स्टेट ट्रेडर्स कांग्रेस का चेयरमैन बनाया है। अरोड़ा लोकसभा चुनावों के मद्देनजर व्यापारियों के बीच ट्रेडर्स के विभिन्न विषयों को उठाएंगे, और भरोसा दिलाएंगे कि कांग्रेस गठबंधन के आते ही उनकी समस्याएं हल की जाएगी। लवली ने कहा कि अरोड़ा व्यापारियों के बीच हमेशा सक्रिय रहने वाले व्यापारी नेता है। इसलिए व्यापारियों की परेशानियों को बेहतरीन तरीके से समझते है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में अजय अरोड़ा पार्टी के लिए अहम भूमिका निभाने वाले है। वहीं अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस द्वारा दी गई जिम्मेदारी व पूरी मेहनत व ईमानदारी से निभाएगें। कोशिश करेंगे कि दिल्ली में कांग्रेसी विचारधारा से जुड़े ट्रेडर्स को एकजुट किया जाए। जानकारी अनुसार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही है और सातों सांसद भी कांग्रेस के थे। दिल्ली में कांग्रेस का अच्छा वोट बैंक है, उनमें व्यापारियों की संख्या भी कम नहीं है। अजय ने बताया कि इंडिया गठबंधन के तहत दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में कांग्रेस को 3 सीटें मिली हैं।

हम ही दिल्ली में चुनाव जीतेंगे : सचदेवा

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लोकसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है और कहा है कि हमारा संगठन ही हमारी ताकत है। हमारे संगठन की ताकत, वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों के विश्वास से हमें आश्वस्त करता है कि भाजपा ही सभी 7 सीटों पर चुनाव जीतेगी। चूंकि दिल्ली में चुनाव छठे चरण में 25 मई को निर्धारित किया गया है, इसलिए हम पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बनाए रखने और अभियान की गति को निरंतर बनाए रखने के लिए अपनी चुनावी रणनीति की समीक्षा करेंगे। अभियान मुख्य रूप से लोगों के बीच दिल्ली के विकास के लिए केन्द्र सरकार की उपलब्धियों और दिल्ली के विकास में योगदान को लेकर सकारात्मक होगा, लेकिन हम मतदाताओं के सामने केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और विकास में विफलता को भी उजागर करेंगे।

दिल्ली की सातों सीटों पर भाजपा फहराएगी जीत का परचम : बिधूड़ी

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद शनिवार को कहा कि अब यह स्पष्ट है कि भाजपा दिल्ली की सातों सीटों पर लगातार तीसरी बार विजय हासिल करने जा रही है और विपक्षी उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होंगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन के हौसले इतने पस्त हैं कि वे अब तक अपने उम्मीदवार तक घोषित नहीं कर पाए जबकि भाजपा के सातों उम्मीदवार पिछले कई दिनों से संपर्क अभियान में लगातार जुटे हुए हैं। आरडब्ल्यूए के सदस्यों के अलावा मार्केट एसोसिएशनों, ट्रेडर्स एसोसिएशनों और विभिन्न सामाजिक संगठनों तथा अन्य गणमान्य लोगों से समूहों में मिल रहे हैं। इन लोगों को बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिल्लीवालों के विकास के लिए कितने नायाब तोहफे दिए हैं और परिवहन व प्रदूषण जैसी समस्या से निपटने के लिए भी केंद्र के प्रयासों से ही दिल्ली को राहत मिल सकी है। उन्होंने बताया कि केंद्र द्वारा दिल्ली के लिए दिए गए प्रोजेक्ट्स में द्वारका एक्सप्रेस, तीसरा रिंग रोड, भारत मंडपम, प्रगति मैदान टनल, दिल्ली मेट्रो के लगातार विस्तार, दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, पीएम स्वनिधि योजना से 2 लाख से ज्यादा लोगों की मदद शामिल है।

खबर संक्षेप

जीडीए के नए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने पदभार संभाला

गाजियाबाद। जीडीए के नवनियुक्त उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाना उनकी प्राथमिकता होगी। कहा कि शासन की प्राथमिकता ही उनकी भी प्राथमिकता होगी। इससे पहले वह सुबह जीडीए कार्यालय पहुंचे और कार्यभार संभाला। इस दौरान जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह व अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

चोरी की स्कूटी खरीदने वाले आरोपी को किया काबू

फरीदाबाद। अपराध शाखा एनआईटी प्रभारी की टीम ने चोरी के वाहन खरीद कर प्रयोग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी साहिल को अपराध शाखा टीम ने गस्त के दौरान गोल चक्कर सूरजकुंड से काबू किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने स्कूटी को किसी व्यक्ति से 15000 में चलाने के लिए खरीदा है। बाद में पता चला कि स्कूटी दिल्ली से चोरी है।

कैब में लिफ्ट देकर युवक से की मारपीट व लूटपाट

गुरुग्राम। सदर थाना एरिया में युवक को कैब में लिफ्ट देकर बंधक बना लूटपाट का मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने बंधक बनाकर मारपीट के बाद उसका मोबाइल व एटीएम कार्ड ले लिया। पासवर्ड पूछकर आरोपियों ने रुपए भी ट्रांसफर किए और उसे सोहना रोड पर उतारकर फरार हो गए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरु कर दी ।

वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत

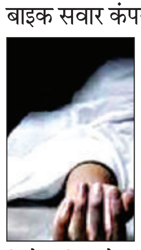

गुरुग्राम। डीएलएफ फेज-3 एरिया में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बाइक सवार कंपनी कर्मी की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया व चालक पर केस दर्ज कर लिया। विवेक सिंह ने कहा कि धर्मेन्द्र सीनियर एडवाइजर के पद पर कार्यरत था। दोनों ही डयूटी के बाद कंपनी से निकले थे। विवेक सिंह अपनी गाड़ी में था, जबकि धर्मेंद्र अपनी बाइक से निकला था।

पार्क से लोहे के टेबल चोरी कर टैम्पो में भर ले गए

गुरुग्राम। सेक्टर-29 स्थित लेजरवैली पार्क में रात को चोर पार्क से लोहे की टेबल चोरी कर ले गए। गार्ड ने शोर मचाकर चोरों को रोकने का प्रयास किया लेकिन चोर कई टेबल टैम्पो में फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एमपी के भिंड निवासी हरिसिंह ने बताया कि वह गुरुग्राम अमनपुरा 12 बिसवा में किराए पर रहता और लेजरवैली पार्क में गार्ड की नौकरी करता है।

औजार से महिला की हत्या आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम। पालम विहार थाना क्षेत्र में तीन दिन पहले महिला के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने सब्जी नहीं बनाने को लेकर हुए झगड़े के बाद वारदात को अंजाम दिया था। महिला व आरोपी दोनों तीन दिन पहले आए थे, जहां अंडे की सब्जी बनाने से मना करने पर महिला के साथ राज मिस्त्री के औजार बसोली से चोट मारी तो उसकी मौत हो गई।

आदर्श आचार संहिता का हो अनुपालन, नजर न आए राजनीतिक तथा अवैध विज्ञापन

- **निगम ने अवैध विज्ञापन के विरुद्ध चलाया अभियान**
- **राजनैतिक होर्डिंग बैनर पोस्टर भी हटे, वॉल पेंटिंग मिटाई**

नगर निगम ने सीमा अवैध होर्डिंग हटाने का अभियान जोरों से चला। जिसमें राजनैतिक, होर्डिंग बैनर पोस्टर भी हटाए गए तथा वॉल पेंटिंग से भी राजनैतिक प्रचार को हटाया गया।

हरिभूमि न्यूज ⏭ गाजियाबाद

नगर निगम ने सीमा अवैध होर्डिंग हटाने का अभियान जोरो से चला। जिसमें राजनैतिक, होर्डिंग बैनर पोस्टर भी हटाए गए तथा वॉल पेंटिंग से भी राजनैतिक प्रचार को हटाया गया।

नगर निगम की टीम जहां निरंतर अवैध विज्ञापन हटाने पर कार्य करती आ रही है वहीं नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देश अनुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद वृहद स्तर पर अभियान चलाते हुए पॉलीटिकल प्रचार प्रसार के लिए लगे होर्डिंग बैनर पोस्टर को भी हटाया गया।

पांचों जोन में जोनल प्रभारी की टीम लगी रही, निर्माण विभाग द्वारा भी वृद्ध स्तर पर कार्यवाही की गई तथा वॉल पेंटिंग पर बने हुए पॉलीटिकल प्रचार को हटाया गया उक्त कार्यवाही के लिए अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव को नोडल बनाया गया है।

जोनल प्रभारी को दी गई जिम्मेदारी

अरुण कुमार यादव अपर नगर आयुक्त ने बताया कि नगर आयुक्त के निर्देश के क्रम में आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत अभियान के रूप में अवैध तथा राजनीतिक होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, वॉल पेंटिंग को हटाए गए। बड़े तथा छोटे सभी प्रकार के विज्ञापन को हटाया गए। नगर आयुक्त द्वारा कार्यवाही के लिए अधिकारियों की टीम भी बनाई है, जिसमें सभी जोन में कार्यवाही के लिए जोनल प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई है तथा सहायक अधिशासी अभियंता निर्माण तथा अवर अभियंता निर्माण को भी दीवारों से पेंटिंग हटाने की जिम्मेदारी दी गई है।

नगर आयुक्त द्वारा चुनावी घोषणा के उपरांत शहर में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के क्रम में सभी संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश भी जारी किए हैं तथा गाजियाबाद नगर निगम सीमा अंतर्गत अभियान के रूप में कार्यवाही हो आदेश भी दिए गए हैं, निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई गाइडलाइन पर कार्य करने के लिए टीम का भी गठन किया गया है।

आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ जिले में हुए सक्रिय चुनाव अधिकारी

जिले में आदर्श आचार संहिता का पालन कराने को गंभीरता से लें सभी अधिकारी

हरिभूमि न्यूज ⏭ फरीदाबाद

जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकारियों को गंभीरता से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना चाहिए।

फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्यों को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश है। ऐसे में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी इन नियमों का अच्छी प्रकार से अध्ययन करें और जिला में आदर्श आचार संहिता का पालन करवाए। साथ ही अवांछनीय गतिविधियों की निगरानी के लिए स ेस टीम भी सक्रिय कर दी जाए जिससे मतदाताओं को प्रलोभन या दबाव बनाने का अंदेशा हो, तो कार्रवाई करें। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा.निर्देशों के तहत गाडिय़ों में निर्धारित सीमा से अधिक नकदी या शराब आदि को भी जब्त करते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित की जाए।

> फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्यों को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश है। ऐसे में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी इन नियमों का अच्छी प्रकार से अध्ययन करें और जिला में आदर्श आचार संहिता का पालन करवाए।

निजी वाहनों पर झंडा-स्टिकर व प्रचार सामग्री की मनाही

सार्वजनिक स्थलों से विभिन्न योजनाओं की प्रचार सामग्री व राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित इश्तिहार हटाने के भी निर्देश दिए। साथ ही निजी वाहनों पर भी बिना अनुमति के राजनीतिक दलों का झंडा, स्टिकर आदि प्रचार सामग्री लगी होने पर मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं में चालान किया जाए। जिला के सभी प्रिंटर्स भी प्रचार सामग्री को लेकर नियमों का पालन करें।

अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के बूथों का करें निरीक्षण

एसडीएम ने सेक्टर आफिसर्स को 18वीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार चुनाव फ्री एण्ड फेयर करवाने के लिए टिप्स देते हुए कहा कि अधिकारी क्षेत्र के बूथों का जरूर निरीक्षण करें। संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों की पूरी जानकारी से अपडेट रहे। वहीं बूथों पर बिजली, पानी, बाथरूम, रैम्प सहित अन्य जरुरी सुविधाएं सुनिश्चित के निर्देश दिए।

एडीसी होंगे स्वीप के नोडल अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आम चुनाव 2024 में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। स्वीप कार्यक्रम के लिए एडीसी डॉ. आनंद शर्मा नोडल अधिकारी होंगे। मतदाता जागरूकता के लिए शिक्षण संस्थानों में रचनात्मक गतिविधियां, सार्वजनिक स्थलों पर विशेष कार्यक्रम तथा एक एंबेसडर को भी नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला के सभी मतदाता फरीदाबाद. जीओवी.इन. सीईओ हरियाणा. जीओवी.इन तथा सीआई. जीओवी. इन आदि वेबसाइट पर अपने बूथ व मत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

गुरुग्राम नगर निगम कराएगा सर्वे

रिहायशी इलाकों में दुकान-दफ्तर चलाने वालों की अब खैर नहीं!

हरिभूमि न्यूज ⏭ गुरुग्राम

गुरुग्राम के नए शहर के रिहायशी क्षेत्रों में दुकान और दफ्तर चलाने वालों की अब खैर नहीं। गुरुग्राम नगर निगम के संयुक्त आयुक्त-4 ने व्यावसायिक गतिविधियां चलने वाले भवनों का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। इन भवनों के खिलाफ निगम की तरफ से सीलिंग अभियान चलाया जाएगा। निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है।

सर्वे का काम संयुक्त आयुक्त ने इन्फोर्समेंट टीम को दिया

निगम के दायरे में शामिल सेक्टरों में चल रही व्यवसायिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए निगम की तरफ से सर्वे करवाया जाएगा। ऐसी इमारतों को चिन्हित करने के लिए सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे का काम संयुक्त आयुक्त ने इन्फोर्समेंट टीम को जिम्मेदारी सौंपी है। इन्फोर्समेंट टीम ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले निगम ने जोन-4 में व्यवसायिक गतिविधियां चलाने वाले मकानों पर कार्रवाई करेगी।

2016 में निगम के दायरे में शामिल हुए थे 50 सेक्टर

वहीं, कॉलोनियों में भी अवैध रूप से चल रहे व्यवसायिक भवनों पर भी निगम कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा। 2016 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के करीब 50 सेक्टर निगम के दायरे में शामिल हुए थे। इन सेक्टरों में सैकड़ों की संख्या में लोग रिहायशी एरिया में व्यवसायिक गतिविधियां की जा रही है। यहां कहीं दुकानें, कोचिंग सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर, कपड़े की दुकानें, ब्यूटी पार्लर आदि संचालित किए जा रहे हैं। इसको लेकर निगम में काफी शिकायतें लोगों द्वारा की जा रही हैं। ऐसे में अब निगम द्वारा यहां कार्रवाई करने को लेकर योजना बनाई जा रही है।

भतीजे ने चाचा को ईंट-पत्थर व डंडे से हमला कर मौत के घाट उतारा, गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ⏭ गाजियाबाद

थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र की सोनिया नगर कॉलोनी में एक 42 वर्षीय व्यक्ति की ईंट-पत्थर व डंडों से हमला कर नृशंस हत्याकर दी गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड को अंजाम देने वाले मृतक के भतीजे हैं। पुलिस ने भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है।

एसीपी भास्कर वर्मा ने बताया कि थाना लोनी बॉर्डर पर नारायण निवासी चौकी क्षेत्र गुलाब वाटिका ने सूचना दी कि उनके भाई मुकेश की उनके भतीजे निखिल पुत्र मांगेलाल से लड़ाई हो गई थी। जिसमें निखिल ने अपने चाचा के सर में पत्थर मार दिया था। जिनको परिजनों द्वारा उपचार के लिए जीटीबी अस्पातल ले जाया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई। सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त निखिल को गिरफ्तार किया गया है ।

उन्होंने मकान की दूसरी मंजिल पर दोस्तों के साथ शराब पी उसके बाद झगड़ा होने पर एक खेत में चले गए और लड़का भी पीछे-पीछे चला गया। जहां उसकी हत्या कर दी।

2000 बच्चों को दी जा रही मुफ्त शिक्षा

इंडियन ऑयल ने दिया शिरडी साई बाबा स्कूल को बस

हरिभूमि न्यूज ⏭ फरीदाबाद

इंडियन ऑयल आर एण्ड डी फरीदाबाद द्वारा शिरडी साई बाबा स्कूल सेक्टर 86 फरीदाबाद को एक बस छात्रों के स्कूल आने-जाने के लिए प्रदान की गई। इंडियन ऑयल डायरेक्टर आलोक शर्मा ने कहा कि मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई शिरडी साई बाबा स्कूल द्वारा 2000 बच्चों को उच्च कोटि की निःशुल्क शिक्षा के साथ भोजन, वर्दी, किताब-कापियां इत्यादि प्रदान की जा रही है और सीबीएसई का 10वीं व 12वीं का परिणाम हर साल 100 प्रतिशत होता है। साई धाम द्वारा छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एकेडमी भी चलाई जा रही है। मेधावी छात्रों को 12वीं के बाद आगे पढ़ने के लिए संभव सहायता व मार्गदर्शन दिया जाता है। साई धाम की गुणवता के लिए छात्रों को इंडियन ऑयल ने बस का अनुदान दिया।

आलोक शर्मा की धर्मपत्नी लक्ष्मी शर्मा ने कहा कि मैं स्वयं साई धाम के संस्था द्वारा चलाई जा रही सामाजिक कार्यों से प्रेरित होकर साइंस के छात्रों को सप्ताह में एक बार आकर पढ़ाया करूंगी।

ग्रेटर फरीदाबाद का चर्चित केस

पलवली हत्याकांड में मुख्य दोषी को उम्रकैद, पीड़ितों ने मांगी फांसी

हरिभूमि न्यूज ⏭ फरीदाबाद

ग्रेटर फरीदाबाद के पलवली गांव में गोली मारकर पांच लोगों की जान ले ली गई थी। 28 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की कोर्ट ने केस के मुख्य दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दो दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। बाकी दोषी अपनी सजा काट चुके हैं। इनमें 6 लोग शामिल हैं। एक को तीन साल और बाकी को एक-एक साल की सजा सुनाई गई। चुनावी रंजिश में पलवली में 58 वर्षीय श्रीचंद, 55 साल के राजेंद्र, 35 वर्षीय ईश्वर, 28 साल के नवीन और 27 वर्षीय पिंट्टू उर्फ देव की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप गांव के ही ज्ञानचंद के परिवार पर था। थाना खेड़ी पुलिस ने ज्ञानचंद परिवार के अलावा उनके समर्थकों सहित 28 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोपियों में तत्कालीन सरपंच दयावती, उसका पति विरेंद्र उर्फ बिल्लू, धर्मेंद्र आदि शामिल थे। आरोपियों में शामिल धर्मेंद्र व प्रमोद हरियाणा पुलिस में एएसआई थे। हमले में श्रीचंद परिवार के कन्हैया और नितेश को भी गोली लगी थी।

आरोपी नंदकिशोर की हो चुकी है मौत

आरोपियों में नंदकिशोर की मौत हो चुकी है। मामले में कोर्ट ने गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर 19 फरवरी 2024 को कमल किशोर को हत्या के मामले में दोषी करार दिया था, जबकि धर्मेंद्र और नरेंद्र को हत्या के प्रयास का दोषी माना था। अमित, रविंद्र, लोकेश, सतीश, और हरीश भी दोषी करार दिए गए थे। लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने शुक्रवार को इन सभी को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई है।

वॉकी टॉकी, मोबाइल, तमंचा व नगद बरामद

एटीएम से फ्रॉड करने वाले दो को पुलिस ने बिहार से किया गिरफ़्तार

हरिभूमि न्यूज ⏭ गाजियाबाद

थाना खोड़ा पुलिस ने एटीएम से फ्रॉड करने वाले दो अपराधियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से कब्जे से घटना में प्रयुक्त 83 प्लेट (लोहे की), 2 वॉकी टॉकी, 6 टेप, 1 लकड़ी का कवर, 1 कैंची टेप काटने वाली, 2 पेचकस, 11 एटीएम कार्ड, 2 आधार कार्ड, 1 पेन कार्ड , 2 मोबाइल फोन, 1 अवैध तमंचा मय जिन्दा कारतूस, 57 हजार रुपए व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की गई।

एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि थाना खोड़ा पर एक महिला ने अज्ञात अभियुक्तों द्वारा एटीएम से छेड़छाड़ कर एकाउंट से 15 हजार रुपए की धन राशि निकालने संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने तत्काल टीमों का गठन कर मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर घटना में संलिप्त आरिफ निवासी नहटौर मौहल्ला नौदहा निकट मदरसा थाना नहटौर जिला बिजनौर व अफरोज आलम बिलादम थाना पाटेपुर जिला मुजफ्फरपुर बिहार को इन्दिरापुरम अंडर पास नहर की पटरी से गिरफ्तार किया। दोनों शातिर बदमाश हैं।

घटना के बाद काफी डरी हुई है दोनों पीड़ित

पहले सरेराह रोककर छेड़छाड़ फिर कुचलने का प्रयास

> वसुंधरा में मालवाहक वाहन सवार दो युवकों ने स्कूटी सवार दो बहनों को सरेराह रोककर छेड़छाड़ की। रिपोर्ट दर्ज कराने पर भी पुलिस दोनों को नहीं पकड़ पाई

हरिभूमि न्यूज ⏭ गाज़ियाबाद

वसुंधरा में मालवाहक वाहन सवार दो युवकों ने स्कूटी सवार दो बहनों को सरेराह रोककर छेड़छाड़ की। रिपोर्ट दर्ज कराने पर भी पुलिस दोनों को नहीं पकड़ पाई। इसके बाद शनिवार शाम को कुचलने का प्रयास किया गया। इस कारण पीड़िता काफी डरी हुई है।

साहिबाबाद क्षेत्र में रहने वाली स्नातक की छात्रा स्कूटी पर बहन के साथ सिद्धार्थ विहार से दूध लेकर लौट रही थी। वसुंधरा में अचानक सामने से छोटा हाथी उनकी स्कूटी के आगे आकर रुका। बमुश्किल उन्होंने ब्रेक लगाए, जिस कारण हादसा होने से बचा। आरोप है कि छोटा हाथी सवार दो युवकों ने अश्लील टिप्पणी की और विरोध पर छेड़छाड़ की। आरोप है कि दोनों नशे में थे। उनके शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने बचाया, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। शनिवार शाम को वह बहन को स्कूटी से कोचिंग छोड़ने जा रही थीं। रास्ते में एक अन्य छोटा हाथी वाहन ने साइड में आकर उनकी स्कूटी में टक्कर मारी। इस कारण बहन गिर गई। पीड़िता का कहना है कि वाहन दूसरा था और चालक को वह देख नहीं पाई। मगर इस घटना के बाद से काफी डरी हुई हैं।

दर्ज है छेड़छाड़ की रिपोर्ट

टक्कर मारने की पुलिस को सूचना नहीं दी गई। छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज है। पहचान कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करेंगे।

स्वतंत्र कुमार सिंह, एसीपी, इंदिरापुरम

कंधे पर सितारे लगाए तो खुशी से भर आईं आंखें, एडीजी ने ली सलामी

मुख्य अतिथि रहे एडीजी ध्रुवकांत सिंह ने परेड की सलामी ली। शपथ ग्रहण के बाद परिजनों ने महिला दरोगाओं के कंधे पर सितारे लगाए तो कई की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं।

एजेंसी ⏭ मेरठ

मेरठ में लोहिया नगर स्थित कोतवाल धनसिंह गुर्जर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में 729 महिला दरोगाओं की पासिंग आउट परेड हुई। इस दौरान मुख्य अतिथि रहे एडीजी ध्रुवकांत सिंह ने परेड की सलामी ली। शपथ ग्रहण के बाद परिजनों ने महिला दरोगाओं के कंधे पर सितारे लगाए तो कई की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। प्रशिक्षण के बाद 729 महिला दरोगा पास आउट हुई हैं। दीक्षांत परेड समारोह के मुख्य अतिथि एडीजी ध्रुवकांत सिंह रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में कमिश्नर सेल्वा कुमार जे मौजूद रहीं। इस दौरान मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित पासिंग आउट परेड कार्यक्रम का बड़ी स्क्रीन पर लाइव प्रसारण किया गया।

प्रदेश को मिलीं 729 महिला दरोगा

इसके बाद प्रशिक्षु दरोगाओं ने मार्च पास्ट कर मुख्य अतिथि को सलामी दी। इसके बाद प्रशिक्षुओं ने संविधान की शपथ ली। विभिन्न गतिविधियों के टॉपर प्रशिक्षुओं को सम्मानित भी किया गया। इसके बाद ट्रेनिंग के बाद परिजनों से मिली महिला दरोगाओं ने जश्न मनाया और उनके साथ अपने प्रशिक्षण के दौरान के अनुभव भी साझा किए। परिजनों ने कंधे पर सितारे लगाकर उन्हें सैल्यूट किया।

एक साथ वर्दी पहनकर बेटियों ने किया मार्च पास्ट, माता-पिता का सीना गर्व से हुआ चौड़ा

मेरठ में बदायूं की तीन सगी बहनों को एक साथ दरोगा पद पर नौकरी मिली है। बीते साल 12 मार्च से तीनों बहनें एक साथ मेरठ में ट्रेनिंग ले रही थीं। जब बेटियां शपथ ले रही थीं तो उनके परिजन इस नजारे को देख कर गौरवान्वित हो रहे थे. पिता ने बताया कि बेटियों की मेहनत से ही ऐसा हो पाया है। उन्होंने बताया कि वह एक छोटी सी मिठाई की दूकान चलाते हैं, लेकिन बेटियां मेहनत करके आगे बढ़ी हैं।

खबर संक्षेप

अटल पथ पर एमएलसी क्वार्टर के पास हंगामा

पटना। आर ब्लॉक से सटे अटल पथ पर बिहार विधान परिषद् के सदस्यों के लिए बने क्वार्टर के पास घंटों हंगामा होता रहा। एमएलसी क्वार्टर में रह रहे नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी गेट में घुसने से रोका गया। यहां निर्माणाधीन एक क्वार्टर में खुले आसमान के नीचे एक युवक की लाश बरामद की गई थी। छत की रेलिंग से लटकाकर और करंट से उसकी हत्या की गई थी। यह हत्या उसके जन्मदिन की रात की गई थी।

डूंगरपुर मामले में आजम समेत 4 दोषी करार

रामपुर। डूंगरपुर बस्ती में घुसकर मारपीट और लूटपाट के एक मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान व पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन समेत चार लोगों को कोर्ट ने दोषी कर दिया है। कोर्ट अब 18 मार्च को इस मामले में सजा सुनाएगी। यह मामला गंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। 2019 में दर्ज इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट नेअपना फैसला सुनाया।

योगी सरकार का बड़ा फैसला

नजूल की जमीनों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, कोई नहीं होगा बेदखल

एजेंसी ⏭ प्रयागराज

उत्तर प्रदेश में नजूल की जमीनों पर मकान बनवाकर रहने वालों के लिए बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। यूपी की योगी सरकार ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में नजूल की जमीनों पर फिलहाल न तो बुलडोजर चलेगा और न ही इससे किसी रहने वाले को बेदखल किया जाएगा। सरकार अभी सिर्फ सर्वे ही कराएगी। इस बात की अंडरटेकिंग उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी है। सरकार की इस अंडरटेकिंग के बाद नजूल की जमीनों पर आशियाना बनाकर यहां रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है।

यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में नजूल की जमीनों पर फिलहाल न तो बुलडोजर चलेगा और न ही इससे किसी को बेदखल किया जाएगा। इसे चुनाव से पहले सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है।

खास बातें

- आशियाना बनाकर रहने वाले लोगों को मिली बड़ी राहत
- आवंटित पट्टों और निर्माण का केवल सर्वे कराएगी सरकार

अध्यादेश को रद्द करने की हाईकोर्ट से की गई है मांग

गौरतलब है कि यूपी में नजूल की जमीनों को लेकर योगी सरकार द्वारा पिछले दिनों लाए गए नए अध्यादेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है। याचिका में अध्यादेश को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से चीफ स्टैंडिंग काउंसिल कुणाल रवि सिंह ने इस बात की अंडरटेकिंग दी कि फिलहाल सर्वे कार्य ही किया जाएगा। नजूल की जमीनों से न तो किसी को बेदखल किया जाएगा और न ही बुलडोजर एक्शन होगा।

5 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से पांच अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। डॉ. अशोक तेहलियानी की याचिका पर इस मामले की सुनवाई जस्टिस एसडी सिंह और जस्टिस सुरेंद्र कुमार की डिवीजन बेंच में हुई। जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार ने पिछले दिनों जारी किए गए अध्यादेश में कहा है कि सरकार अब नजूल भूमि का पट्टा किसी प्राइवेट व्यक्ति या संस्था को नहीं देगी।

पहले कहा था-नजूल भूमि सिर्फ सरकारी संस्थाओं को ही देंगे

सरकार ने कहा था कि नजूल भूमि सिर्फ सरकारी संस्थाओं को ही दी जाएगी। इसके अलावा सरकार नजूल भूमि पर आवंटित पट्टों और निर्माण का सर्वे कर रही है ताकि पता किया जा सके कि किन लोगों के पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी है। अवधि समाप्त होने के बाद सरकार उसका नवीनीकरण भी नहीं करेगी और जमीन वापस ले लेगी। इस अध्यादेश के खिलाफ याचिका दाखिल कर इसे गैरकानूनी बताया गया है। अदालत इस मामले में अगली सुनवाई पांच अप्रैल को करेगी। अंग्रेजों के समय जिस जमीन का मालिक कोई नहीं होता था, उसे नजूल जमीन कहा जाता है। सरकार इसे लीज पर लोगों को आवंटित करती है।

8वीं का विद्यार्थी था प्रिंस

स्कूल में परीक्षा देने आए छात्र पर गिरा छज्जा, दर्दनाक मौत

एजेंसी ⏭ धनबाद

झारखंड के धनबाद में एक बड़ा हादसा हो गया। झरिया केसी गर्ल्स स्कूल के मुख्य गेट पर छज्जा गिरने से परीक्षा देने आए आठवीं कक्षा के छात्र प्रिंस कुमार (13) की मौत हो गई। छज्जा गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के काफी संख्या में लोग जुट गए। आनन-फानन में स्कूल के शिक्षक एवं छात्रों ने प्रिंस को उठाकर झरिया के एक निजी नर्सिंग होम ले गए, जहां स्थिति नाजुक देख डॉक्टर ने उसे धनबाद भेज दिया। धनबाद के जालान अस्पताल में इलाज के दौरान प्रिंस ने दम तोड़ दिया।

जानकारी के मुताबिक, झरिया डीएवी मध्य विद्यालय अंचल झरिया के छात्र प्रिंस कुमार सहित आठवीं छात्रों का शनिवार को सेंटर केसी गर्ल्स स्कूल पड़ा था। टिफिन के समय छात्र बाहर निकल रहे थे। तभी यह घटना घटी। केसी गर्ल्स स्कूल काफी पुराना है। सन 1932 से यह स्कूल चल रहा है। कई बार स्कूल की रिपेयरिंग हो चुकी है।

मुआवजे की मांग को लेकर चक्काजाम

मृतक प्रिंस के पिता प्रदीप साव ने स्कूल के शिक्षक के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि छज्जा जर्जर होने के बाद भी स्कूल के बच्चे आना-जाना करते हैं। इससे पहले भी छज्जा गिरने की घटना घट चुकी है। लेकिन तब किसी को चोट नहीं आई थी। इधर, छात्र का शव झरिया पहुंचते ही लोगों का गुस्सा भड़क उठा। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने झरिया-धनबाद मुख्य सड़क को जाम कर दिया।

बिहार-झारखंड में ईडी का ताबड़तोड़ छापा

250 करोड़ अवैध कारोबार, 4 टीमें तैनात

एजेंसी ⏭ पटना

बालू के अवैध कारोबार को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार की सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार और झारखंड में चार जगहों पर छापेमारी की। बालू सिंडिकेट से जुड़े कारोबारी पुंज सिंह के तीन और कृष्णमोहन सिंह के एक ठिकानों पर ईडी ने दबिश डाली। छापेमारी सुबह छह बजे से शुरू हुई जो देर शाम तक जारी रही। ईडी की यह कार्रवाई मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। छापेमारी में कागज पर दर्ज पैसे के लेन-देन का रिकार्ड मिला है। इसके साथ ही मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, बही खाता, डायरी, रजिस्टर, संपत्ति के कागज, बैंक खाते के रिकार्ड और बैंक लाकर के दस्तावेज आदि जब्त किए गए हैं। ईडी की 24 सदस्यीय चार टीमों ने अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की तीन टीमों ने बालू कारोबारी पुंज सिंह के भोजपुर जिले के कोईलवर थाना क्षेत्र अंतर्गत धनडीहां गांव, धनबाद के झरिया के हेटली बांध स्थित आवा और धैयार स्थित कासा क्लेस में छापेमारी की।

120 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात

इसके अलावा ईडी ने अन्य बालू कारोबारी कृष्ण मोहन सिंह के आरा के आनंद नगर स्थित आवास पर छापेमारी की। ईडी के सहयोग के लिए 120 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात थे। इसके अलावा 40 से अधिक केंद्रीय रिजर्व बल के जवान भी लगाए गए थे। छापेमारी के दौरान मोबाइल पर रोक लगाने के लिए जैमर का इस्तेमाल किया गया था।

धनबाद में 4 घंटे का इंतजार, फिर तोड़ डाला ताला

धनबाद में पुंज सिंह के आवास पर छापेमारी करने पहुंची ईडी की टीम को चार घंटे इंतजार करना पड़ा। शनिवार को सुबह छह बजे जब धनबाद के धैया स्थित कासा क्लेस आवास पर पहुंची, तो परिवार के सदस्य घर में ताला बंद करके फरार हो गए। ईडी की टीम को घर के बाहर करीब चार घंटे इंतजार करना पड़ा। दस बजे ईडी की टीम ने आसपास के लोगों, मंदिर के पुजारी और सुरक्षा गार्ड के सामने ताला तोड़ा और तलाशी शुरू की।

19 मार्च को कोर्ट में पेश करने का है आदेश

मौलाना तौकीर की तलाश में दिल्ली से हैदराबाद तक दबिश

एजेंसी ⏭ बरेली

वर्ष 2010 में हुए बरेली दंगे के लिए कोर्ट से मास्टरमाइंड ठहराए गए मौलाना तौकीर रजा को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मौलाना के खिलाफ दो बार गैरजमानती वारंट जारी हो चुका है। गिरफ्तारी न होने पर कोर्ट ने पुलिस को फटकार भी लगाई है। इसके बाद एसएसपी को जिम्मेदारी सौंपी गई। मौलाना को 19 मार्च को एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश करना है। अब सिर्फ तीन दिन बचे हैं, लेकिन मौलाना का अब तक पता नहीं चला है। ऐसे में मौलाना की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है।

13 मार्च को दोबारा जारी हुआ वारंट

एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट से 13 मार्च को मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ दोबारा से गैर जमानती वारंट जारी किया गया। इस बार वारंट एसएसपी के नाम से संबोधन करके जारी किया गया है, 19 मार्च 2024 को मौलाना को गिरफ्तार कर पेश कराने की जिम्मेदारी एसएसपी को सीधे तौर पर दी गई है। वारंट में मारपीट, हमला, बलवा, सेवन क्रिमनल लॉ एक्ट और साजिश रचने जैसी वह सभी धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें मुकदमे के बाकी आरोपियों पर चार्जशीट लगी है।

यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी सफलता

बॉक्स खोलकर सरगना को पेपर भेजने वाला डॉ. शुभम को किया गिरफ्तार

एजेंसी ⏭ लखनऊ

सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने टीसीआई कम्पनी में रखे ट्रंक बाक्स को खोलकर गैंग सरगना को पेपर भेजने वाले डॉ. शुभम मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। उसे पटना के खगौल से गिरफ्तार किया गया है।

इसके पहले सिपाही पेपर लीक कराने वाले गैंग के तीन सदस्यों को एसटीएफ ने गाजियाबाद से बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया था। तीनों अहमदाबाद से यूपी के जिलों को पेपर भेजने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनी के वर्तमान व पूर्व कर्मचारी हैं। इन लोगों ने इस कांड के मास्टर माइंड राजीव नयन मिश्रा के साथ मिलकर वेयरहाउस से पेपर की फोटो खींची थी। बाद में उसे लाखों रुपयों में बेचा गया। राजीव की तलाश जारी है।

बॉक्स खोलने में माहिर मंडल

राजीव ने बॉक्स खोलने में माहिर पटना निवासी डॉ. शुभम मंडल को बुलाया था। वहीं राजीव ने अपने साथी रवि अत्री के साथ पेपर बिक्रम पहल, मोनू ढाकला, विक्रम दाहिया, महेंद्र शर्मा, गौरव चौधरी, मोनू पंडित, सतीश धनकड (मानेसर के नेचर वेली रिसॉर्ट का मालिक), नीटू, धीरज उर्फ गोल्डी (बॉलीवुड रेस्टोरेंट सोनीपत, हरियाणा का मालिक) आदि को दिए थे।

पेज एक का शेष

अब 'जय' बोलो...

साथ ही सरकार ऐसा कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकेगी, जो मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर सके। कुमार ने बताया कि देशभर में मतदाता लिंगानुपात 948 है और 12 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। कुमार ने कहा कि चुनाव के लिए हमारी तैयारी पूरी है और भारत में होने वाले चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। दो नए निर्वाचन आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं और मैं मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि वे स्याही (मतदान वाली) लगवाएं। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। सीईसी ने राजनीतिक दलों को प्यार से चुनावी अभियान करने की सलाह देते हुए कहा कि वे चुनाव अभियान के दौरान रेड लाइन पार न करें। चुनाव में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमें चुनाव में फ्री बीज पर लगाम लगाना है। उन्होंने यह भी कहा कि गैरजमानती वारंट को पुलिस अमल में ला रही है। गौर हो कि पिछले संसदीय चुनावों में भाजपा ने 303 सीटें जीती थी जबकि कांग्रेस को 52 सीटें मिली थीं।

भारत समृद्ध- आत्मनिर्भर...

है। पिछला दशक सत्तर वर्षों तक शासन करने वालों द्वारा पैदा की गई कमियों को भरने के बारे में था। यह आत्मविश्वास की भावना पैदा करने के बारे में भी था कि हां, भारत समृद्ध और आत्मनिर्भर बन सकता है। हम इसी भावना को आगे बढ़ाएंगे। पीएम ने कहा कि गरीबी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और भी तेज गति से चलेगी। सामाजिक न्याय पर जोर रहेगा। हम भारत को तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम करने जा रहे हैं। हम युवाओं के सपनों को पूरा करने के अपने प्रयास को और मजबूत करेंगे।

लोकसभा चुनाव के...

तीसरा चरण- 25 मई। चौथा चरण- 01 जून। सिक्किम में एक चरण में ही 19 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को मतदान होगा। आंध्र प्रदेश में175 सीटों पर वोटिंग 13 मई को होगी और 4 जून को ही सभी के साथ आंध्र के नतीजे घोषित किए जाएंगे।

सम्राट चौधरी बोले

भाजपा कोटे के 6 मंत्रियों की जगह अभी भी खाली

पटना। बिहार में नीतीश कैबिनेट का एक बार फिर विस्तार हो सकता है। डिप्टी सीएम सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसके संकेत दिए हैं। सम्राट ने कहा कि शुक्रवार को जो कैबिनेट का विस्तार हुआ वो अंतिम नहीं है। जल्द ही एक और मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अभी 6 मंत्रियों की सीटें खाली हैं। आने वाले दिनों में भाजपा से छह और मंत्री बनाए जाएंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि अभी भाजपा से और मंत्री बनाए जाएंगे। नीतीश कैबिनेट में बीजेपी कोटे से 6 पद अभी खाली हैं। जल्द ही पार्टी की बैठक होगी और उनमें नए मंत्रियों के नामों पर मंथन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी जो हुआ वो मंत्रिमंडल का पूर्ण विस्तार नहीं था।

हादसे में घायल श्रमिकों का चल रहा है इलाज

सीतापुर मार्ग पर निर्माणाधीन रिसॉर्ट की छत गिरी, नीचे दबे 8 मजदूर, 2 की मौत

बहराइच के सीतापुर मार्ग पर स्थित एक रिसॉर्ट में निर्माणाधीन छत की बल्ली गिरने से छत भी ढह गई। हादसे में नीचे दबे दो मजदूरों की मौत हो गई जबकि छह को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

एजेंसी ⏭ बहराइच

सीतापुर मार्ग पर स्थित एक रिसॉर्ट में निर्माण के दौरान बल्ली गिरने से छत भी गिर गई जिसके नीचे आठ श्रमिक दब गए। किसी तरह छह श्रमिक बाहर निकाले गए हैं। जबकि दो लोगो की मलबे में दबकर मौत हो गई। गजपतिपुर गांव में बहराइच सीतापुर मार्ग पर एक रिसॉर्ट स्थित है। यह होटल जिले के डॉ. अनिल केडिया का है। होटल में इस समय एक हिस्से में निर्माण कार्य चल रहा है। यहां पर छत ढलान के दौरान एक बल्ली गिरी। इसके बाद छत गिर गई। जिसके नीचे कोतवाली देहात के चेतरा सबलापुर निवासी राहुल वर्मा, श्रावस्ती जिले के उत्तमापुर निवासी राहुल समेत आठ लोग दब गए। किसी तरह श्रमिक बाहर निकाले गए। सभी को अस्पताल पहुंचाकर भर्ती कराया गया।

घटना स्थल पर पहुंचे अधिकारी, जांच की

हादसे में घायल श्रमिकों का इलाज चल रहा है। कोतवाली देहात वीके मिश्रा ने बताया कि मलबे में श्रमिक सलीम और जोगेंद्र की दबकर मौत हो गई। घटना की जानकारी पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर रामानंद कुशवाहा, एसडीएम महसी और सीओ सिटी राजीव सिसोदिया आदि ने पहुंचकर जांच की है।

तभी सुरक्षित रहेगी धरती जब इसे मानेंगे जीवित इंसान

हम में से अधिकांश लोग ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के बारे में जानते हैं लेकिन इसे रोकने के लिए अपने स्तर पर भी पहल नहीं करते। इसका मूल कारण यही है कि हम धरती को निर्जीव मानते हैं, इसीलिए इस पर अत्याचार करते रहते हैं। लेकिन हालात अब ऐसे हो गए हैं कि हम सबको धरती को इंसान मानते हुए पूरी संवेदनशीलता से बर्ताव करना होगा, तभी आने वाले समय में धरती रहने लायक बचेगी।

कवर स्टोरी / नयनतारा

अगर दिनों-दिन गहराती ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से हम सब को निपटना है और दिन पर दिन बेतहाशा बढ़ रही गर्मी पर लगाम लगानी है तो वक्त आ गया है कि पृथ्वी को एक जीवित इंसान की तरह माना जाए और उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाए। बीते 1 मार्च 2024 को केन्या की राजधानी नैरोबी में संपन्न हुई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के छठवें संस्करण में जो एक मंत्री स्तरीय घोषणा पर सहमति हुई है, उसमें मूल सहमति यूं तो 17 संकल्पों और निर्णयों पर हुई है, लेकिन सबका सार यही है कि वक्त आ गया है कि अब हम धरती को जीवित इंसान मानें।

अब लापरवाही होगी खतरनाक

दुनिया भर के पर्यावरणविद इस बात को बड़ी गहराई से समझ रहे हैं कि धरती में चारों तरफ जिस तरह रसायनों और कूड़े-कचरे का साम्राज्य है, अब हमें उसके प्रति बिना देर किए चिंतित होना पड़ेगा। यही नहीं चिंता का विषय जरूरत से ज्यादा खाद्यान्न और चीजों का बेतहाशा उपभोग भी है। अगर धरती के लोग अपनी इस लालची प्रवृत्ति को नहीं छोड़ेंगे तो तमाम कोशिशों के बाद भी धरती के बिगड़ते पर्यावरण को रोक पाना संभव नहीं होगा। इसलिए 182 देशों के 7000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने जिनमें 170 से अधिक मंत्री थे, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अब धरती को जीवित इंसान मानकर बर्ताव किया जाए। इस सभा में शिरकत करने वालों ने साफतौर पर कहा कि टिकाऊ जीवनशैली को बढ़ा देने से लेकर रसायनों और अपशिष्ट पदार्थों, रेत और धूल भरी आंधियों के सक्षम प्रबंधन पर अब बिना देर किए जुट जाना होगा ताकि धरती जो पहले से ही जीने के लायक नहीं रही, उसे और बदहाल होने से बचाया जा सके।

खत्म करना होगा उपभोग असंतुलन

गौरतलब है कि दुनिया में इस समय जितनी आबादी है, उसके लिए आवश्यक उपभोग के कई गुना ज्यादा चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें भी बड़ी विडंबना यह है कि कुछ लोग जरूरत से कई गुना ज्यादा चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी लोग जरूरत से कम चीजें पा रहे हैं। मतलब यह कि इतना ज्यादा उपभोग किया जा रहा है कि एक तरफ धरती का सीना फटा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के दो तिहाई लोग या तो भूखे रहते हैं या अपनी भूख से कम भोजन पा रहे हैं। यह स्थिति अच्छी नहीं है। यह असंतुलन धरती को और ज्यादा नरक बना रहा है। इसलिए एक तरफ जहां पर्यावरणविदों का मानना है कि अत्यधिक खपत पर लगाम लगे, वहीं दूसरी तरफ इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि उपभोग के लिए लोगों के बीच बेहतर वितरण की व्यवस्था हो। कुछ लोगों को कम और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ना मिले। हालांकि उपभोग में संतुलन करना इतना जटिल सवाल है कि इसका समाधान खोजना काफी कठिन है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब तक संसाधनों के उपभोग में संतुलन स्थापित नहीं होगा, तब तक धरती के संरक्षण की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते हैं।

सिर्फ बातों से नहीं होगा समाधान

केन्या में आयोजित यूएनईए-6 में जो विस्तृत और गंभीर विमर्श हुआ है, उससे साबित होता है कि धरती के लोग अब धरती की पीड़ा का वास्तविकता में एहसास करने लगे हैं। लेकिन यह बात सच तब मानी जाएगी, जब दुनिया को इस गहरे संकट से बचाने के लिए लोग वास्तव में काम करते दिखेंगे, सिर्फ बातें नहीं करेंगे। साल 2012 में अपने स्थापना के बाद से यूएनईए-6 ने पहली बार इतने स्पष्ट और निर्णायक बात कही है। हालांकि कोई ऐसा सम्मेलन, कोई ऐसी बैठक नहीं होती, जब धरती के पर्यावरण को लेकर चिंता ना व्यक्त की जाती हो। लेकिन जिस तरह से इस बार पूरी स्पष्टता के साथ चीजों को रखा गया है और आर या पार के अंदाज में लोगों से फैसला करने को कहा गया है, वह इसके पहले कभी नहीं हुआ। अगर अब भी चीजें नहीं बदलती तो बहुत डरावनी स्थिति पैदा हो सकती है।

अमीर देश निभाएं अपनी भूमिका

वास्तव में यूएनईए-6 की जारी रिपोर्ट में इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि धनी देश, कम आय वाले देशों की तुलना में एक, दो नहीं बल्कि 6 गुना से ज्यादा संसाधनों का उपभोग करते हैं और दुनिया में पर्यावरण पर जितना नकारात्मक असर होता है, उसमें गरीब देशों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा भूमिका अमीर देशों की होती है। इसलिए यूएनईए-6 यह मानती है कि रईस देशों और उनके ज्यादा से ज्यादा उपभोगवादी लोगों को पर्यावरण के बचाव में बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन यही वह मोड़ है, जहां सारी बात उलट जाती है, क्योंकि बाकी किसी क्षेत्र में बराबरी का समर्थन ना करने वाले अमीर देश, धरती के बिगड़ते पर्यावरण को बचाने के लिए सभी देशों की बराबर की भूमिका चाहते हैं। इसका स्पष्ट कारण यह है कि कोई भी अमीर देश अपने हितों, प्रगति और विलासिता में ना कमी करना चाहता है और ना उससे कोई समझौता करना चाहता है। इसी वजह से ऊर्जा उपभोग हो या तकनीक का बेशुमार उपयोग विकसित देश कोई कमी नहीं करना चाहते हैं। सवाल यह है कि इस मतभेद का हल कब और कैसे निकलेगा? जब तक इसका हल नहीं निकलेगा, धरती पर संकट बढ़ता रहेगा। *

यूएनईए-6 में किया गया आगाह

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन ने यूएनईए-6 सभा के समापन सत्र को संबोधित करते हुए माना कि बेहतर कल के लिए दुनिया द्वारा की जाने वाली कार्यवाही, उसकी गति, उसकी वास्तविकता और उसके स्थायी परिवर्तन में जरूरी बदलाव की आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि जिन योजनाओं पर बात हो, उन पर वाकई काम भी हो, जिस रफ्तार की जरूरत है, उस रफ्तार से काम हो और हकीकत में यह सब हो ताकि परिवर्तन संभव बने, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन को धीमा करने, प्रकृति और धरती को राहत देने, प्रदूषण मुक्त दुनिया बनाने के लिए तभी हकीकत में कुछ होगा, जब सिर्फ मजबूत इरादे ही ना व्यक्त किए जाएं बल्कि उन पर मजबूत अमल भी किया जाए। संयुक्त राष्ट्र उपमहासचिव आमिना जे. मोहम्मद ने दुनिया से बड़ा सवाल पूछा, 'एक ऐसे समय में जब दुनिया प्रदूषण, जैव विविधता के संकट और जलवायु परिवर्तन के कहर से गुजर रही है, तब भी अगर हम धरती को बचाने के लिए अपने प्रयासों में गति और ईमानदारी नहीं लाएंगे, तो फिर यह सब कब करेंगे?' *

विशेषः विश्व गौरैया दिवस, 20 मार्च

आ री चिरैया...

अब घरों के आंगन में नन्ही गौरैया की चहचहाहट सुनाई नहीं पड़ती। सुबह-सवेरे से देर शाम तक उनकी आवाज से जीवंतता बनी रहती थी। चिरैया की गुंजार से महरूम घर-आंगन वीरान से लगते हैं। कहां खो गई वो चिरैया...

अनुभूति / डॉ. सुधा मौर्य

आज शहर में चारों ओर चर्चा है कि
लुप्त हो गई है गौरैयों की प्रजाति
हां, शहर में कहां आएं और चहकें गौरैयां
न मकानों में आंगन रहे
न आस-पास पेड़-पौधे *(रामदरश मिश्र)*

प्रकृति के प्रत्येक स्पंदन में जीवन है, ललक है, उल्लास है। फिर वह चाहे कल-कल निनादित सरिता हो, पवन की मनभावन लीला, पत्तों की सरसराहट या पक्षियों का उन्मुक्त कलरव। प्रकृति सदैव से ही मानव जीवन को गति, लय प्रदान कर उसे सकर्मक उत्साह से युक्त करती रहती है। इनमें लघुकाय नन्ही गौरैया भी मानव के जीवन में अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। वह हमारे घर-आंगन-मुंडेर पर फुदकती अपनी 'चहचहाती' उजली हंसी से घर को ऊर्जस्वित करती है। फसलों में लगने वाले कीटों का भक्षण करके फसलों के लिए सुरक्षा कवच बनती है। ग्रामों में गृहों की भीतों पर चावल के आटे, सिंदूर, हल्दी से उकेरे गए उनके मनोहर मंजुल चित्र हमारे गृह की शांति, समृद्धि एवं शुभता के प्रतीक रहे हैं। वे अपनी मधुरिम गुंजार स्वर लहरी द्वारा जागरण गीत गाकर हमें सजग करती हैं। *इस घर के आले में रहती है। चिड़िया और उसके दो बच्चे। वे जगाते हैं हमें काम पर जाने के लिए। (ब्रजेश कृष्ण)*

अस्तित्व के लिए संघर्षरत

आज मानव की स्वार्थी प्रवृत्ति ने गौरैया को अपनी ही मातृभूमि से बेदखल कर दिया है। अब शहरों में उग आए कंक्रीट के जंगलों में उनके लिए स्थान ही नहीं बचा है। घर-आंगन में उल्लास बिखेरने वाली वह छोटी-सी गौरैया, आज मानव के पर्यावरण के प्रति असंवेदनशील व्यवहार के कारण अस्तित्व संकट से जूझती हुई कदाचित यही सोचती होगी-

चिड़िया उड़ती हुई कहीं से
आई। बहुत देर तक इधर-उधर
भटकती हुई। अपना घोंसला
खोजती रही। फिर थक कर एक
जली हुई डाल पर बैठ गई। और
सोचने लगी। आज जंगल में
कोई आदमी आया था क्या? (रामदरश मिश्र)

नहीं सुनाई देती उनकी चहक

आज फसलों के अधिकाधिक उत्पादन के लिए कीटनाशकों के अत्यधिक छिड़काव, मोबाइल फोन से निकलने वाली तरंगों के विकिरण और आहार श्रृंखला में छोटे कीटों के नष्ट होने से गौरैया भी विलुप्त हो रही है। इसीलिए अब संकटग्रस्त जंतुओं की श्रेणी में सम्मिलित गौरैया की चहचहाहट बहुधा सुनाई नहीं देती है। हम इंसानों के लिए स्वयं की सुरक्षा के निमित्त भी यह चिंता का विषय ही है, क्योंकि-

इस पृथ्वी की रक्षा मानव का अपना कर्तव्य है। इसकी वनस्पतियां, चिड़िया और जीव-जंतु। उसके सहयात्री हैं, इसी तरह जलवायु और सारा आकाश। अपनी-अपनी रक्षा मानव से चाहते हैं। (त्रिलोचन)

ताकि बची रहे गौरैया

पृथ्वी की उसी झंकृत प्रफुल्लता को पुनः वापस लाने के लिए 20 मार्च को 'विश्व गौरैया दिवस' मनाया जाता है। यह दिवस संकटग्रस्त गौरैया को बचाने के निमित्त है ताकि मानव जीवन, उसका घर-आंगन-द्वार आनंदमय एवं स्वच्छता से परिपूर्ण हो। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं व्यक्तिगत स्तर पर संपूर्ण विश्व में इस संबंध में जागरूकता अभियान चला कर गौरैया को उनके घास-फूस के घोंसले में रक्षित करने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और वह दिन दूर नहीं जब घर-घर की यह 'खुशी' गौरैया पुनः पूर्ण प्राण प्रवेग से चहकेगी। हर ओर उसकी कलरव गूंजेगी।

जैसे बहन 'दा' कहती है। ऐसे किसी बंगले के किसी तरु (अशोक) पर। कोई चिड़िया कुऊकी।
(रघुवीर सहाय)

बस करना यह है कि उनके लिए अपने घर-आंगन के आस-पास पेड़-पौधे लगाएं। मुट्ठी भर अनाज और खाली बर्तन में स्वच्छ पानी देकर उनको बचाने की मुहिम में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। ताकि हमारे घरों में गौरैया की चहक कभी बंद ना हो।

चहचहाती चंद चिड़ियों का। बसर था पेड़ पर। मेरे घर इक पेड़ था और। एक घर था पेड़ पर। (सज्जाद बलूच)

कहने का अर्थ है कि यदि हम चिड़ियों के साथ हिल-मिल जाएं तो वे हमारी सहचर बनकर हमारे घर-आंगन में उत्साह-हर्ष की चहचहाहट गुंजारित करेंगी और गौरैया के लिए मानव की यही लघुत्तम संवेदनशीलता ही विश्व गौरैया दिवस के प्रति उनकी सच्ची संकल्पशक्ति का बोधक है। अंततः कामना यही है-

अरे चिड़िया, तुम बोलो बारंबार गांव में
घर में घाट में वन में।
पत्थर हो चुके
आदमी के मन में। (एकांत श्रीवास्तव) *

कविता / पावनी पांडे

मिली-जुली महक

इक उलझन
आन खड़ी हुई
बगीचे से होकर
गुजरती
तितली
के मन में
यह महक
गुलाब की
वह चंपा
और चमेली की
किसको आगोश में लूं
किसको छोड़ दूं?
इसी बीच बगीचे से
गुजरती हवा
हर सोच-विचार
का झंझट छोड़कर,
सभी खुशबुओं को
अपने आंचल में
समेट लेती है
दूर एक कैक्टस को
भेंट कर आती है
बगीचे की
मिली-जुली महक।

लघुकथाएं

मॉडर्न महिला

उसके परिधान बेहद खूबसूरत, लेटेस्ट डिजाइन के थे। गले का नेकलेस और कान में झुमके भी कीमती थे। उसकी केश-सज्जा बहुत अलग अंदाज की थी। हाथ में किसी बड़े ब्रांड का हैंडबैग था। ये सभी बातें उसे एक अमीर और मॉडर्न महिला बता रही थीं। इस शादी में वह बतौर मेहमान आमंत्रित थी। शादी को खूब एंज्वॉय करके समारोह स्थल से बाहर आकर उसने घर लौटने के लिए अपने कार ड्राइवर को फोन किया और सड़क पर खड़े होकर इंतजार करने लगी।

तभी कोई मांगने वाली गुजरी। उसकी तीन साल की बेटी ने कौतुहल से उसके परिधान को स्पर्श भर कर लिया, उस मॉडर्न महिला ने तुरंत बच्ची को आग्नेय नेत्रों से देखा। बच्ची सहम कर अपनी मां के पीछे दौड़ी। एकाएक कुछ मेहमान सामने से आ गए। एक उस जैसी मॉडर्न महिला के महाजिद्दी बच्चे ने पहले अपने हाथ से उस महिला का पल्लू खींचा फिर अपने दांतों में दबाया। उसकी सैंडल पर पैर भी मारा। इतना ही नहीं, जाते-जाते उसको चिढ़ाता भी गया। उस मॉडर्न महिला ने तुरंत अपना रंग बदला, बोली, 'लवली बेबी..! क्यूट बेबी...! ओहो... बाय-बाय!' *

– हरीशचंद्र पांडे

घोंसला

मैं शाम को दफ्तर से लौटकर आऊं, यह चिड़िया का घोंसला मुझे नहीं दिखना चाहिए, समझे।' रवि बाबू अपने बेटे पर बरसे।

'पापा चिड़िया के घोंसले में छोटे-छोटे अंडे हैं। अभी कैसे घोंसले को बाहर फेंक सकते हैं। कुछ दिन इंतजार कर लेते हैं। बच्चे उड़ने लायक हो जाएंगे तो घोंसले को हटा देंगे।' बेटे ने विनती की। उसी समय सामने वाले पड़ोसी निर्मल जी आ गए, बोले, 'अरे रवि बाबू, कैसे बच्चे पर गुस्सा रहे हैं?' 'कुछ नहीं, निर्मल भाई। आप बताओ थैला लेकर कहां जा रहे हैं?' रवि बाबू ने बात बदलते हुए पूछा। 'बस अगले चौराहे तक जा रहा हूं। कुछ दाना-पानी की व्यवस्था करने।' निर्मल जी ने जवाब दिया। रवि बाबू ने उत्सुकता से पूछा, 'दाना-पानी?' 'हां भाई दाना-पानी। दरअसल, एक चिड़िया ने घर में घोंसला बना लिया है। उसमें उसके दो-चार बच्चे भी हैं। बस उनके दाने के लिए एक मिट्टी का बर्तन और पानी के लिए परिंडा लेने जा रहा हूं। बेचारी नन्ही-सी जान कहां दाना-पानी के लिए भटकती फिरेगी?' निर्मल जी ने बताया। रवि बाबू बेटे की तरफ देखते हुए तुरंत बोले, 'बेटा आज तुम भी दाने-पानी के लिए बर्तन ले आना।' 'जी पापा..!' बेटा मुस्कुराते हुए बोला। *

–गोविंद भारद्वाज

फर्क

क्यों जी, आजकल अपने शहर में सफाई अभियान कुछ ज्यादा नहीं चल रहा है? मधु अपने पति प्रभाकर से बोली। 'तुम्हें पता नहीं है क्या? पेपर नहीं पढ़तीं? अपने शहर में प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन होने वाला है। इससे अपने प्रदेश और शहर में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। ये लोग यहां इंवेस्ट जो करेंगे।' प्रभाकर हर्ष के साथ बोले। 'पता है मुझे। देश-दुनिया की जानकारी मैं भी रखती हूं। ऐसी भी क्या साफ-सफाई, जिसमें गरीबों को परेशान किया जाए, उनका सफाया कर दिया जाए। जगह-जगह झुग्गी-झोपड़ियां और गुमटियां-ठेले हटा दिए जाएं। पता नहीं गरीबों के घर उजाड़कर, रोजी-रोटी छीनकर कौन-सा नया रोजगार लाया जा रहा है?' मधु आक्रोश के साथ बोली। 'वो क्या है ना भाग्यवान, हमारे घर जब मेहमान आते हैं तो उन पर अपना प्रभाव जमाने के लिए हम अपने घर की साफ-सफाई करते हैं, उसे अच्छी तरह सजाते हैं। इस दौरान हमें जो भी फालतू और गंदी चीजें दिखती हैं, उसे हम हटा देते हैं। बस वही समझ लो, प्रवासी भारतीयों के सामने अपनी छवि अच्छी रहे, इसलिए शहर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इस काम में जो भी बीच में आएगा, उसे हटाया ही जाएगा।' प्रभाकर ऐंठे स्वर में बोले। 'तो क्या सामान और इंसान में कोई फर्क नहीं?' मधु ने प्रभाकर से तुरंत सवाल किया। उनके पास कोई जवाब नहीं था। *

-शीला श्रीवास्तव

पुस्तक चर्चा / विज्ञान भूषण

हिंदी की चिंता

वरिष्ठ कवि, आलोचक ओम निश्चल गंभीर भाषाविद् भी हैं। हिंदी भाषा की सामाजिक स्थिति और उसकी स्वीकार्यता को लेकर वे निरंतर विचारशील लेख लिखते रहते हैं। ऐसे ही कुछ निबंधों का संकलन 'हिंदी का समाज-समाज की संस्कृति' पुस्तक के रूप में कुछ समय पूर्व आया है। वे अगर लिखते हैं, 'हमारा समाज लगभग भाषाहीन समाज है।' तो इसमें हिंदी भाषा को लेकर उनकी पीड़ा और चिंता दोनों झलकती है। खास बात यह है कि वे केवल चिंता नहीं करते, पुस्तक के कई लेखों में वे स्वाधीनता से पूर्व और उसके बाद के भारतीय समाज की मानसिकता की पड़ताल करते हैं, जिसने हमें हिंदी भाषा के प्रति इतना उदासीन बना दिया। वे उन कारणों की भी शिनाख्त करते हैं, जिनकी वजह से हिंदी देश की राजभाषा तो बन गई पर राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। केवल कारण ही नहीं लेखक ने कुछ लेखों में ऐसे सुझाव भी दिए हैं, जिन पर अमल करके हिंदी को उसके गौरवमयी स्थान पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है। महात्मा गांधी और प्रख्यात आलोचक रामविलास शर्मा के हिंदी भाषा, भारतीय संस्कृति से प्रेम पर भी लेखक ने विस्तार से चर्चा की है। कहना न होगा कि पुस्तक के सभी लेख न केवल पठनीय बल्कि विचारणीय भी हैं। *

पुस्तकः हिंदी का समाज-समाज की संस्कृति (निबंध संग्रह), **लेखकः** ओम निश्चल, **मूल्यः** 450 रुपए, **प्रकाशकः** सर्वभाषा प्रकाशन, नई दिल्ली

अरविंद विहार बागमुगलिया पुरानी बस्ती का मामला
गैस सिलेंडरों में रिफलिंग के दौरान भीषण हादसा

गैस एजेंसी की मिलीभगत से चल रहा था कारोबार, 247 कॉमर्शियल सिलेंडर जब्त

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

अरविंद बिहार बागमुगालिया पुरानी बस्ती में आगजनी की घटना की जद में आए नर्मदा केटरर्स और गैस एजेंसी के गोदाम और अन्य जगह से खाद्य अमले से 247 खाली-भरे कॉमर्शियल सिलेंडर जब्त किए हैं। ये सभी अवैध थे। कैटरर्स, शिवा गैस एजेंसी से ये सिलेंडर बुलवाता था। विभाग ने एजेंसी और उसके गोदामों की भी जांच शुरू कर दी।

आग की सूचना मिलने पर आपूति नियंत्रक भोपाल कार्यालय का अमला भी सुबह पहुंच गया था। कोलार एसडीएम रविशंकर राय, जिला आपूर्ति नियंत्रक मीना मालाकार, तहसीलदार कुणाल राउत और नायब तहसीलदार अतुल शर्मा मौके पर मौजूद रहे। घटना के बाद राय ने बस्ती में अवैध रूप से रखे सिलेंडरों की जांच भी करवाई। अमले ने आगजनी की घटना स्थल से 61 कॉमर्शियल सिलेडर जब्त किए गए। मंदिर के बगल में बाग मुगलिया किचन (कारखाना) नर्मदा कैटर्स से 2 भरे एवं 11 आंशिक भरे एवं 91 खाली गैस सिलेंडर जब्त किए गए। कैटरर्स के किचन के सामने स्थित गोदाम में 82 कॉमर्शिलय गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। जानकारी के अनुसार, तीनों जगहों से अवैध रूप से कुल 247 सिलेंडर जब्त किए गए। इनमें दो भरे, 11 आंशिक भरे एवं 234 खाली थे। गैस सिलेंडर के अलावा 11 चूल्हा भट्टी जब्त किए गए।

एजेंसी और संबंधित लोगों पर होगा एक्शन

आग की घटना के दौरान बस्ती और उसके आसपास अवैध रूप से रखे गए सिलेंडरों की जांच कराई गई। इसमें 247 सिलेंडर जब्त किए गए। एजेंसी और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- रविशंकर राय, एसडीएम कोलार

प्रारंभिक जानकारी में यह बात सामने आई है कि नर्मदा कैटरर्स, शिवा गैस एजेंसी से सिलेंडर बुलवाता था। एजेंसी के आउटलेट और गोदामों की जांच कराई गई है।
- **मीना मालाकार**, जिला आपूर्ति नियंत्रक, भोपाल

मंत्री गौर ने जताई नाराजगी सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

अधिकारियों को दो टूकः क्षेत्र में हो रहे गैरकानूनी कामों को तुरंत रोका जाए

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर ने शुक्रवार को गोविंदपुरा विधानसभा के बाग मुगालिया इलाके में सुबह करीब 10 बजे टेंट हाउस के गोदाम में आग लगने की घटना के बाद मौके पर पहुंची और उन्होंने गैरकानूनी ढंग से चल रहे गोदाम को देखकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पूरे क्षेत्र में इस तरह के जो भी गैरकानूनी काम चल रहे हैं, उन्हें तुरंत रोका जाए और गोदाम मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि गोदाम के आसपास कई मकान और झुग्गियां बनी हैं। बड़े हादसे की आशंका थी, जिससे आसपास के लोग तीन घंटे तक दहशत में रहे।

रहवासियों के अनुसार...

लोग घर के बाहर आ गए

गोदाम के बास पुरानी बस्ती में विस्फोट की आवाज लगातार आती रही। डर कर घर के सभी लोग बाहर निकल आए और सामान भी निकाल रहे थे। डर के कारण पूरी बस्ती के लोग घर के बाहर आ गए थे।
- योगश अहिरवार, बागमुगालिया

शिकायत पर सुनवाई नहीं

गोदाम में गैरकानूनी तरीके से गैस रिफिलिंग की जा रही थी। इसकी शिकायत भी कई विभागों में की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। सुनवाई अगर हो जाती तो आज की दुर्घटना को रोका जा सकता था।
- राजेश सूर्यवंशी, अरविंद विहार

गोदाम से कुछ लोग भागे

गोदाम में पहले आग दिखाई तो फायर ब्रिगेड को फोन किया, लेकिन बाद में विस्फोट होने से सभी लोग भाग खड़े हुए। गोदाम के अंदर से भी कुछ लोग भागते दिखे, जो फायर ब्रिगेड आने के बाद दिखाई नहीं दिए।
- रितिक कुमार, बागमुगालिया

खबर संक्षेप

बीएमएचआरसी में शुरू बीसीजी वैक्सीनेशन

भोपाल। टीबी से बचाव के लिए लग रही एडल्ट बीसीजी वैक्सीन अब बीएमएचआरसी में भी लगना शुरू हो गई है। इसके लिए अलग से सेंटर बनाया गया है। बीएमचआरसी की निदेशक डॉ. मनीषा श्रीवास्तव ने एनएचएम अधिकारियों के साथ इसकी शुरुआत की है। डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक यहां वैक्सीनेशन के लिए आ सकते हैं। टीकाकरण से पहले व्यक्ति से लिखित सहमति ली जाएगी। यह टीका 18 साल से ज्यादा आयु, टीबी से स्वस्थ हुए मरीज, 60 वर्ष से अधिक उम्र, धूम्रपान करने वाले, टीबी रोगियों के संपर्क में आने वाले, मधुमेह से पीड़ित और जिनका बीएमआई 18 से कम उनको लगाए जा रहे हैं।

महिलाओं को मिल रही स्टांप ड्यूटी में 2 फीसदी की छूट

प्रॉपर्टी में बढ़ी 'लाड़लियों' की भागीदारी 60 प्रतिशत महिलाओं के नाम हुई रजिस्ट्री

शहरी क्षेत्र में 10.50 तो ग्रामीण में 7.5 फीसदी स्टांप शुल्क

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

प्रॉपर्टी के लगातार बढ़ रहे दामों को देखते हुए अब ज्यादातर लोग महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री करा रहे हैं। इस कारण रजिस्ट्री कराने में सीधे दो फीसदी की छूट मिल रही है। अकेले राजधानी में दर्ज की जा रही रजिस्ट्री में महिलाओं का आंकड़ा 60 फीसदी तक आ गया है, जबकि इसके पहले यह भागीदारी 30 से 40 फीसदी थी। इस वित्तीय वर्ष में करीब 87 हजार रजिस्ट्री दर्ज की गई है, जिसमें 60 फीसदी प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम है।

सरकार ने 2021 में किया था आदेश जारी

सरकार ने 6 अप्रैल 2021 को आदेश जारी कर महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी खरीदने पर 2 फीसदी छूट दी थी। यह छूट नगर निगम के साथ ही गांवों में रजिस्ट्री कराने पर भी मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिलाओं को 7.5 फीसदी पंजीयन शुल्क देना होता है, वहीं नगर निगम क्षेत्र में यह 10.50 फीसदी है।

इसके बाद से ही महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने का सिलसिला शुरू हुआ। इसका असर यह हो रहा है कि अब शहर की 10 में 6 प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम पर ही खरीदी जा रही हैं। पुरुषों को शहरी क्षेत्र की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन विभाग 12.5 फीसदी स्टांप ड्यूटी लेता है। वहीं, गांव में ये ड्यूटी 9.5 फीसदी है।

एक लाख रुपए की होती है बचत

शहर की किसी एक लोकेशन पर 1 हजार वर्गफीट के प्लॉट का सरकारी गाइडलाइन का मूल्य 5 हजार रुपए प्रति वर्गफीट के हिसाब से खरीदने पर प्रॉपर्टी की कुल कीमत 50 लाख आएगी। पुरुष के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर 12.5 फीसदी स्टांप ड्यूटी चुकाना पड़ रही है। इसलिए स्टांप ड्यूटी 6 लाख 25 हजार रुपए चुकाना पड़ रही थी। महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टांप ड्यूटी 5 लाख 25 हजार रुपए देना पड़ रहे हैं। यानी पुरुषों की तुलना में सीधे-सीधे एक लाख रुपए स्टांप ड्यूटी में बचत हो रही थी।

ग्राम खोखरा का मामला, सीसीटीवी कैमरे में घटना हुई कैद

मां मनका दाई मंदिर में चोरी, लाखों रुपए लेकर गए बदमाश, वारदात के दौरान सोता रहा चौकीदार

हरिभूमि न्यूज ▶▶ जांजगीर चांपा

जांजगीर चांपा जिले के ग्राम खोखरा में प्रसिद्ध मां मनका दाई मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। मंदिर से पांच नग दान पेटी, चांदी का लोटा, एक नथनी और देवी मां के पहने हुए करधन की चोरी हुई है। चोरों ने अपने चेहरे को कपड़ों से ढका हुआ है। वहीं चोरी करते सीसीटीवी कैमरे में तीन चोर कैद हुए हैं। दानपेटी के बगल में चौकीदार सोया हुआ है, जिसे चोरी का पता नहीं चल पाया। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार, प्रसिद्ध मंदिर मां मंदिर दाई में शुक्रवार की बीती रात अज्ञात चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया है। मंदिर में अब तक 5वीं बार चोरी हुई है। शनिवार की सुबह जब पुजारी मंदिर में पूजा करने पहुंचा तो देखा कि मंदिर में रखे सामान बिखरे हुए थे, वहीं पांच नग दान पेटी नहीं थे। वहीं मंदिर के अंदर देवी मां के पहने हुए एक नथनी, करधान भी नहीं था। मंदिर में चोरी की घटना की जानकारी मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पुलिस टीम पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई है।

'खादी ग्राम स्वराज अभियान' को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए केवीआईसी ने ग्रामीण कारीगरों को बांटे मशीनरी और टूलकिट

नई दिल्ली। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार 'विकसित और आत्मनिर्भर भारत' निर्माण के लिए गांव-गांव तक 'खादी ग्राम स्वराज अभियान' को सशक्त करने लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली के कारीगरों को आधुनिक प्रशिक्षण के बाद उच्च गुणवत्ता के टूलकिट प्रदान किये। वीआईपी पार्क केशवपुरम, त्रिनगर, उत्तर-पश्चिम दिल्ली में आयोजित वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केवीआईसी अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने केवीआईसी के उत्तर क्षेत्र के सदस्य श्री नागेंद्र रघुवंशी की उपस्थिति में ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत कारीगरों को 160 मशीनरी व टूलकिट प्रदान किये। वितरण कार्यक्रम के दौरान केवीआईसी के राज्य कार्यालय दिल्ली के अंतर्गत आनेवाले 11 जिलों के 40 कुम्हारों को कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 40 विद्युत चालित चाक, 10 मधुमक्खी पालकों को हनी मिशन के अंतर्गत 100 मधुमक्खी बॉक्स और 20 कारीगरों को 20 ऑटोमैटिक अगरबत्ती मशीन का वितरण किया गया।

सोमवार से फिर होगी बारिश, दो दिन छाएंगे बादल

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

राजधानी में पिछले कुछ दिन से गर्मी का असर है, लेकिन 16 मार्च से यहां भी मौसम बदल जाएगा। 16, 17 और 18 मार्च को बादल छाए रहेंगे। वहीं, 18 मार्च को कुछ इलाकों में बूंदाबांदी होने का अनुमान है। इससे पहले शुक्रवार को गर्मी का असर बना रहा। प्रदेश में मार्च में तीसरी बार मौसम बदलेगा। 16, 17 और 18 मार्च को हल्की बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। मौसम वैज्ञानिक वेदप्रकाश सिंह का कहना है कि जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में ज्यादा असर रहेगा।

सिस्टम लौटने के बाद फिर गर्मी बढ़ेगी

16, 17 और 18 मार्च को हल्की बारिश के साथ गिर सकते हैं ओले

16 से 18 मार्च के बीच मौसम बदला रहेगा। सिस्टम गुजरने के बाद फिर से प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ेगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत प्रदेश के शहरों का 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो आखिरी दिनों में यहां तेज गर्मी का ट्रेंड है। इससे अनुमान है कि 26 से 31 मार्च के बीच ज्यादातर शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है।

पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

मारपीट करने और रुपए के लिए तंग करने वाले शराबी पति की सब्बल मारकर हत्या

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कोरबा

वृद्ध की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। उसकी पत्नी ने ही सब्बल से वार कर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। श्यामलाल राठिया की रक्त रंजित अवस्था में घर में लाश मिली थी। शार्ट पीएम रिपोर्ट में पुलिस ने हत्या किसी भारी वस्तु से किए जाने की पुष्टि की। मृतक की पत्नी कलश बाई राठिया से पूछताछ किया गया।

पहले तो वह पुलिस को गुमराह करते हुए बताया था कि वह किसी काम से बाहर गई हुई थी। इस दौरान यह घटना हुई वापस लौटी तो उसका पति मृत अवस्था में मिला। पूछताछ किए जाने पर उसने अपराध कबूल करते हुए बताया कि अपने पति की हत्या सब्बल से मारकर उसने की है। उसने बताया कि पति श्यामलाल रोजाना शराब पीता था। वह ग्राम नकटीखार से दारू खरीदकर लाता था। शराब पी लेने के बाद मेरा विवाद करते हुए मारपीट करता था। कहीं काम से बाहर जाती थी तो वह चरित्र पर शंका करता था। 13 मार्च को वह सुबह उठी तो श्यामलाल भी उठकर ब्रश करके मेरे से शराब पीने के लिए 50 रुपए मांगा और शराब घर पर लाकर पीया।

इसके बाद वह सब्जी बेचने के लिए खरमोरा चली गई। वापस लौटी तो पति फिर से दारू पीने के लिए पैसा मांगने लगा। मना करने पर गाली दिया और मारपीट करने लगा। गुस्से में उसने अपने पति को धक्का मारकर अपने से दूर भगाने का कोशिश की। इस बीच श्यामलाल उसे मारने के लिए कैंची उठा लिया। वह बचने की कोशिश की और इस आपाधापी में उसके अंगूठे में चोट लगी। कलश बाई ने बताया कि पास में ही रखा सब्बल उसने उठा लिया और आवेश में पति पर वार कर दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

एम्स के डॉक्टर्स ने जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक दिया अंजाम

नसों और किडनी से चिपकी थी 25 सेंटीमीटर कैंसर की गांठ, चार घंटे सर्जरी कर निकाला

सर्जरी के दौरान पांच बार फटी खून की नस

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

मरीज कई दिनों से पेट की समस्या से था परेशान

रेयर ब्लड ग्रुप वाले 35 साल व्यक्ति के पेट में 25 सेंटीमीटर बड़ी कैंसर की गांठ मौजूद थी। यह गांठ किडनी और सीधे दिल को रक्त की सप्लाई करने वाली मोटी खून की नस से चिपकी हुई थी। चार घंटे चली जटिल सर्जरी के दौरान पांच बार यह नस फटी, जिसे साथ-साथ में रिपेयर किया गया। जिससे रेयर ब्लड ग्रुप वाले मरीज का ज्यादा खून बहने से भी बचाया गया।

बता दें कि मप्र निवासी मरीज कई दिनों से पेट दर्द की समस्या से परेशान था। उसने निजी क्लीनिक में दिखाकर सोनोग्राफी कराई। जिसमें गांठ होने की बात सामने आई। इसके बाद वे इलाज के लिए एम्स भोपाल पहुंचे। जहां सीटी स्कैन और सिटी एंजियोग्राफी जांच में यह कैंसर का एक बड़ा ट्यूमर पाया गया। इसके बाद कैंसर सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने सर्जरी की योजाना बनाई।

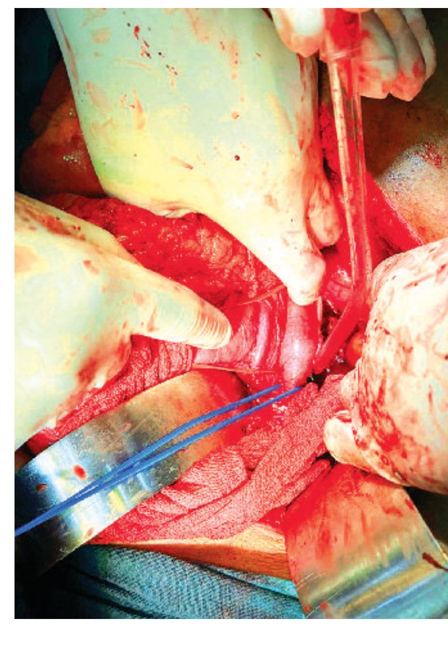

ऑपरेशन के दूसरे दिन ही मरीज ने चलना, फिरना कर दिया शुरू

ये बहुत रेयर केस थाः डॉ. विनय

डॉ. विनय कुमार ने बताया कि इस तरह के कैंसर बहुत ही रेयर होते हैं। सबसे जरूरी था मरीज के खून को बहने से रोकना और उसकी किडनी को बचाना। मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। ऑपरेशन के दूसरे ही दिन मरीज ने चलना, फिरना और खाना, पीना शुरू कर दिया। टीम में ओंको सर्जन डॉ. विनय कुमार, सीटीवीएस सर्जन डॉ. योगेश नेवरिआ और एनेस्थीसिया कंसल्टेंट डॉ. पूजा और एसआर डॉ. सोनवीर गौतम थे।

मरीज के अंगों को बचाना था सबसे बड़ी चुनौती

डॉ. विनय कुमार ने बताया कि सर्जरी के दौरान किडनी को डैमेज होने और मोटी खून की नस के फटने का डर था। वहीं, ब्लड ग्रुप भी रेयर था, ऐसे में सर्जरी से पहले ब्लड बैंक में 3 से 4 ग्रुप रिजर्व किए गए थे। सर्जरी में दिल समेत अन्य अंग की मॉनिटरिंग जरूरी थी, इसलिए इसे कार्डियोलॉजी विभाग की सीटीवीएस ओटी में किया गया। मरीज की स्थिति को देखते हुए आर्टिफिशियल हार्ट लंग मशीन को ओटी में तैयार रखा गया था। जिससे खून ज्यादा बहने पर मरीज के अंगों को बचाया जा सके।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर देश में सियासी संग्राम मचा हुआ है। सीएए को लेकर अधिसूचना जारी होने के दिन से विपक्ष इसकी टेक्निकालिटी को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। दरअसल, सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 2014 के बीच भारत में आए अल्पसंख्यक-हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करता है। विपक्ष का सरकार पर आरोप है कि सीएए में भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे मुस्लिमों को नागरिकता प्रदान करने से वंचित क्यों रखा गया है? इस पर सरकार का तर्क है कि पाक, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, ये इस्लामिक देश हैं, इसलिए इन देशों में मुस्लिम पीड़ित नहीं हैं, ऐसे में अगर वे भारत में शरणार्थी के रूप में हैं तो वे उत्पीड़न के कारण नहीं हैं, बल्कि इसके कारण अन्य हो सकते हैं। सीएए शरणार्थी मुस्लिमों की नागरिकता में बाधक नहीं है। विपक्ष का यह भी तर्क है कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, तो सरकार अपने किसी कानून में धर्म के आधार पर विभेद नहीं कर सकती है। सरकार का कहना है कि सीएए संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों के बीच दो टूक कहा है कि सीएए वापस नहीं होगा, यह नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बज चुका है, ऐसे में सवाल है कि क्या सीएए चुनावी मुद्दा बनेगा? सीएए पर विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है? क्या सचमुच सीएए भारतीय संविधान की भावना के खिलाफ है? नागरिकता संशोधन अधिनियम आखिर भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करेगा, क्या सरकार बैकफुट पर आएगी, या विपक्ष को लाभ मिलेगा? इन्हीं सवालों को लेकर पेश है आजकल का यह अंक...

सीएए 2024 का 'नागरिक शास्त्र'

विश्लेषण
सुशील राजेश
वरिष्ठ पत्रकार

अब एक तरफ सीएए की अधिसूचना जारी की गई है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन और फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस कानून को अपने-अपने राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत में 192 याचिकाएं हैं, जिनमें सीएए का विरोध किया गया है। अदालत 19 मार्च को सुनवाई की शुरुआत करेगी। वैसे किसी भी मुख्यमंत्री को यह क्षेत्राधिकार नहीं है कि संसद द्वारा पारित और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी कानून को लागू करने से स्पष्ट इनकार कर सके। यह परोक्ष रूप से संघीय टकराव की स्थिति है, जिस पर संविधान पीठ को फैसला देना पड़ सकता है।

रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पुराना और बुनियादी एजेंडा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से खदेड़ा जाए। आठवें दशक में खुद मैंने संघ के साहित्य और शाखाओं में इस मुद्दे को लगातार चर्चा में देखा और महसूस किया था। यह आंकड़ा भी बताया जाता था कि भारत में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय आदि राज्यों में बसे हैं और घर-घर में काम कर रहे हैं। अब तो बांग्लादेशी दिल्ली में भी खूब सक्रिय हैं। बहरहाल यह मुद्दा बाद में सामने आया, लेकिन अगस्त, 1955 में लोकसभा में जब नागरिकता, शरणार्थियों और घुसपैठ पर बहस जारी थी, सांसदों की चिन्ताएं और सरोकार उभर रहे थे, तब यह तथ्य भी संसद में गूंजता रहा कि पूर्वी बंगाल में 30-40 लाख हिन्दू शरणार्थी हैं और वे लगातार धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। तब पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा बंगाल ही था, जो 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश बना। नागरिकता पर 1955 में जो कानून बना, उसमें जवाहर लाल नेहरू, गोविन्द वल्लभ पंत, ठाकुर दास भार्गव, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरीखे नेताओं ने चर्चा में भाग लिया था। पाकिस्तान भी हिन्दुओं को लगातार धकेलता रहा था। तब के नागरिकता कानून में 6 संशोधन भी किए गए, लेकिन शरणार्थियों और घुसपैठियों के मुद्दे अनसुलझे ही रहे। तब भी भारत सरकार हिन्दू शरणार्थियों को नागरिकता देने के पक्ष में थी। बीते एक अंतराल से रोहिंग्याओं की घुसपैठ भी संवेदनशील समस्या बनती जा रही है। भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा यथावत है। केंद्र में 6 साल अटलबिहारी वाजपेयी की सरकार रही और मई, 2014 से लगातार मोदी सरकार है। नए लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। बहरहाल पुराने मुद्दे बरकरार हैं, लेकिन मोदी सरकार ने 11 मार्च को 'नागरिकता संशोधन अधिनियम' (सीएए) की अधिसूचना जारी कर बड़ा मुद्दा पैदा कर दिया है।

आम चुनाव से पहले घोषणा

सीएए का बिल 2016 में संसद में पेश किया गया। दिसंबर, 2019 में लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया। जाहिर है कि कानून बनाने की पटकथा को अंतिम रूप दे दिया गया, लेकिन 4 साल 3 माह की लंबी अवधि के बाद कानून की अधिसूचना तब जारी की गई, जब आम चुनाव की घोषणा कुछ दिन बाद होने ही वाली थी। इस संदर्भ में अधिसूचना के समय पर कठोर सवाल किए जाने स्वाभाविक हैं। कानून के नियम, उसकी पात्रता और शर्तें आदि तय करने में इतना लंबा वक्त गुज़ार दिया गया, यह वाकई आश्चर्यजनक स्थिति है। अब एक तरफ सीएए की अधिसूचना जारी की गई है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन और फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस कानून को अपने-अपने राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत में 192 याचिकाएं हैं, जिनमें सीएए का विरोध किया गया है। अदालत 19 मार्च को सुनवाई की शुरुआत करेगी। वैसे किसी भी मुख्यमंत्री को यह क्षेत्राधिकार नहीं है कि संसद द्वारा पारित और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी कानून को लागू करने से स्पष्ट इनकार कर सके। यह परोक्ष रूप से संघीय टकराव की स्थिति है, जिस पर सर्वोच्च अदालत की संविधान पीठ को फैसला देना पड़ सकता है। सीएए को ध्रुवीकरण अथवा मुसलमान-विरोध का नागरिक शास्त्र कहा जा सकता है, जो एक हद तक 2024 के आम चुनाव को प्रभावित करेगा। वैसे इसमें भी 'अर्द्धसत्य' ही है, क्योंकि मुसलमान इस कानून के दायरे में नहीं हैं।

मिल सकता है फायदा

बेशक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के पीड़ित, अत्याचारों को झेलते उन देशों के घोर अल्पसंख्यकों-हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी-को ही भारत की नागरिकता मुहैया कराने की व्यवस्था सीएए में की गई है, लिहाजा भाजपा अपने जनाधार में ध्रुवीकरण करा चुनावी फायदा उठा सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा इसका सफल प्रयोग बंगाल में कर चुकी है। विरोधियों की आशंका, उनके असमंजस और डर बयां किए जा रहे हैं कि सीएए को लिंक एनआरसी से है। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों अलग हैं। सीएए के जरिये मुसलमानों के एक तबके की नागरिकता छीनी जा सकती है। ऐसी दलीलें महज अफवाहें हैं और देश में विभाजनकारी हालात पैदा करने की कोशिशें और सियासतें की जा रही हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा में कुछ संगठन आंदोलित हो चुके हैं। याद रहे कि राजधानी दिल्ली के 'शाहीन बाग' इलाके में इसी मुद्दे पर मुसलमानों ने 100 दिन का आंदोलन चलाया था और बाद में पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगे भी भड़के थे, लिहाजा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने 'फ्लैग मार्च' तक निकाला है। ओवैसी सरीखे मुस्लिमपरस्त नेता ने सीएए को 'गोडसे की सोच' पर आधारित करार दिया है। उनके समेत कांग्रेस, सपा, राजद, महाविकास अघाड़ी, वामदलों, बसपा, द्रमुक आदि वे दल लगातार सीएए के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, जो बुनियादी तौर पर मोदी और भाजपा विरोधी हैं। सीएए ने भारतीय राजनीति को दोफाड़ कर दिया है, लिहाजा यह 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। सिर्फ यही नहीं, कतर के चैनल 'अल जजीरा' ने सीएए को मुस्लिम-विरोधी करार दिया है।

कुछ विशेषज्ञ ऐसी व्याख्या कर रहे हैं कि सीएए के जरिये सरकार यह स्पष्ट कर रही है कि दरअसल सभी मुसलमान 'भारत के नागरिक' नहीं हैं। संविधान के तहत ऐसा कैसे संभव है? कोई भी सरकार, किसी भी नागरिक की, नागरिकता छीन नहीं सकती, यह संवैधानिक व्यवस्था है।

करीब 19 लाख आवेदन

फिलहाल 18 लाख 74,000 आवेदन तीनों पड़ोसी देशों से आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 16.39 लाख पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान में हिन्दू आदि अल्पसंख्यक 1.18 फीसदी हैं, जबकि बांग्लादेश में 8.5 फीसदी और अफगानिस्तान में मात्र 0.04 फीसदी हैं। बताया जाता है कि बांग्लादेश से 2.21 लाख शरणार्थी और अफगानिस्तान से करीब 14,000 शरणार्थी भारत में आए हैं। ये आंकड़े कम-ज्यादा भी हो सकते हैं। इन शरणार्थियों और नागरिकता के आवेदकों के लिए भारत 'मानवतावादी धार्मिक संरक्षक देश' है। चूंकि ये तीनों देश 'इस्लामी' हैं, लिहाजा कानून में मुसलमानों की नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। इसी संदर्भ में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों को भारत में बसाने को सीएए बनाया गया है। उनका आकलन है कि अब जो पलायन होगा, वह भारत-विभाजन से भी बड़ा और खतरनाक होगा। तीनों देशों से करीब 2.5 करोड़ लोग पलायन करके भारत में आएंगे। भारत सरकार उन्हें कहां रखेगी? कहां घर देगी? कितनी नौकरियां, रोज़गार उन्हें दिए जा सकेंगे? देश के आर्थिक संसाधन तो सीमित हैं। हमारे नौजवानों के लिए नौकरी, रोज़गार के पर्याप्त अवसर नहीं हैं और भाजपा ने देश के भीतर एक और पाकिस्तान बसाने का कानून बनाया है। दरअसल सीएए भाजपा का वोट बैंक बनाने की एक और रणनीति है। केजरीवाल के बयान भावोत्तेजक जरूर हैं, वे एक नया मुद्दा गढ़ने की फिराक में हैं, क्योंकि केजरीवाल सीएए पर छिड़े सांप्रदायिक उन्माद की भीड़ में शामिल नहीं होना चाहते, अलबत्ता उनके आरोप कुतर्क ही हैं।

अंतरराष्ट्रीय समझौता

संयुक्त राष्ट्र नागरिकता को व्यक्तिपरक सुरक्षा का बुनियादी तत्त्व मानता है और प्रताड़ित, शोषित, मानवाधिकार कुचलन के शिकार लोगों को 'शरणार्थी' के तौर पर किसी भी देश में प्रवेश करने या कराने को 'मानवीय कर्म' मानता है। संयुक्त राष्ट्र में ऐसा अंतरराष्ट्रीय समझौता भी पारित किया जा चुका है, जो शरणार्थी को नागरिकता देने को बाध्य करता है। सीएए पर बहस के दौरान और अधिसूचना जारी होने के बाद देश के गृहमंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया है कि सीएए का किसी भी तरह का जुड़ाव एनआरसी से नहीं है। यह नागरिकता देने वाला कानून है, तो देश को उनके कथन पर भरोसा करना चाहिए। यदि वह देश को छलने वाले साबित होते हैं, तो अभी देश में सर्वोच्च अदालत का न्याय जिंदा है। मोदी सरकार ने सीएए के जरिये नागरिकता और घुसपैठ को साफ किया है और मुद्दों को व्यापकता दी है। पात्र शरणार्थी एक निश्चित वेबपॉर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। सरकार ने ऐप भी बनाई है। एक अधिकार प्राप्त समिति इस पर अंतिम निर्णय लेगी। समिति के प्रमुख निदेशक होंगे और 7 अन्य सदस्य भी समिति में होंगे। प्रक्रिया की शुरूआत जिला स्तर पर की जाएगी। कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि मुसलमानों से कोई काग़ज़ात मांगे जाएंगे। मुसलमान पात्र शरणार्थी है ही नहीं। फिर सीएए के खिलाफ जो राजनीतिक प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वे हिन्दू-मुसलमान की सियासत ही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरे जा सकें।

भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतिबिंब

सीएए
डॉ. भारत
कानून प्रवक्ता, पीयू, चंडीगढ़

भारतीय संविधान में भाग-2 के तहत अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता को पारिभाषित करते है। इसमें अनुच्छेद 5 से 10 नागरिकता की पात्रता के बारे में बताते है, वहीं अनुच्छेद 11 नागरिकता के मसले पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। धर्मनिरपेक्ष भारत में नागरिकता के अधिग्रहण और निर्धारण के लिए संविधान के अंतर्गत "नागरिक अधिनियम, 1955" है। जहां एक तरफ इस कानून के अनुसार, एक व्यक्ति जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण, क्षेत्र के समावेश द्वारा या असम समझौते के विशेष प्रावधानों के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है; वही दूसरी तरफ यह कानून अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने से रोकता है। चूंकि कानूनों को समय-समय पर स्थितियों और आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए संशोधित किया जाता है; इसी तर्ज पर नागरिक अधिनियम को भी वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और अंततः 2019 में संशोधित किया गया था।

कोरोना के कारण देरी

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 9 व 11 दिसंबर 2019 को क्रमशः लोकसभा व राज्यसभा मे पारित हुआ। बाद में इसे राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया था परन्तु कोरोना के कारण इसे लागू करने में देरी हुई। अब चार साल से अधिक समय के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन नियम, 2024 को अधिसूचित किया जो नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के कार्यान्वयन को सक्षम करेगा और इसके तहत उपरोक्त शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी।

अवैध प्रवासी नहीं

2019 के नागरिकता (संशोधन) अधिनियम ने यह प्रावधान किया था कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित कोई भी व्यक्ति जो की अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में दाखिल हुआ, उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और निर्दिष्ट कानूनी शर्तों की पूर्ति पर, ऐसे व्यक्तियों को भारतीय नागरिक माना जाएगा। नई व्यवस्था के चलते ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त करने के लिए अब ग्यारह वर्ष की बजाय न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए भारत में रहने की आवश्यकता होगी।

कोई असर नहीं

ध्यान देने योग्य बात यह है कि 2019 का नवीनतम संशोधन भारतीय मुसलमानों या उनके अधिकारों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता। अपितु इस संशोधित अधिनियम की अंतर्निहित व्याख्या के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आने वाले मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी और यही गर्भित वाक्यांश भारत में इसके विरोध की जड़ रही है। जो यह सोचने के

लिए मजबूर करता है कि क्या मुस्लिम बहुल व शासकीय मुस्लिम मज़हब वाले देशों में मुसलमान खुश नहीं हैं? यदि ऐसा है, तो इसके कारण भी निश्चित रूप से गम्भीर ही होंगे।

सबसे बड़ा सवाल

संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष खुफिया विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, भारत में इन अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े 31,313 लोग वीज़ा पर हैं; जिनमें से 25,447 हिंदू, 5,807 सिख, 55 ईसाई, 2 बौद्ध और 2 पारसी हैं। निःसंदेह सत्तारूढ़ दल इस अधिनियम से आगामी चुनावों मे लाभान्वित होगा लेकिन नागरिकता के इस एकमुश्त-लाभ से प्रभाव डालने के लिए लाभार्थियों की निर्दिष्ट संख्या नगण्य ही है। सवाल उठता है की अगर यह संशोधन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी भारतीय व्यक्ति को, चाहे वह भारतीय नागरिक है या नही, प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं कर रहा है, तो देश में धरना-प्रदर्शन क्यों हो? जब यह संशोधन "नागरिकता" लेने के लिए नहीं – देने के लिए है फिर दर्द क्यों है? क्या यह देश में आंतरिक शांति और अमन को बिगाड़ने की गहरी साजिश तो नहीं? कही यह गुस्सा राजनीतिक लाभ के लिए तो नहीं भड़काया जा रहा? इसके विरोध का तर्क क्या है? इस विरोध का औचित्य क्या है? इस संशोधन की देश-विदेश में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। मगर सवाल उठता है कि 'क़ानून के शासन' वाले देश में यह कितना न्यायसंगत है? जब संसद में चर्चा और बहस के बाद पूर्ण-बहुमत वाली सरकार द्वारा पारित अधिनियम जनादेश के खिलाफ नहीं हो सकता... तो क्या इसके विरोध का एकमात्र कारण यह है की इस संशोधन से राष्ट्र विरोधी ताकतों के निहित स्वार्थ की इच्छा प्रतिबिंबित नहीं हो रही है और इसने उनके अमांगलिक सपनों पर पानी फेर दिया हैं।

सुरक्षित रहेंगे अधिकार

यह संशोधन किसी भी तरह से किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों को समाप्त या कम नहीं करता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के जीवन में एक नई आशा और रोशनी लाना है जो कल तक पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न सहन कर रहे थे। इसका पहला प्रमाण यह है की 2019 के संशोधन ने 1955 के अधिनियम के मूल प्रावधानों को संशोधित नहीं किया है, कोई भी विदेशी, जिसमें मुस्लिम भी शामिल हैं, कभी भी प्राकृतिककरण की सामान्य प्रक्रिया के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता हैं। दूसरा प्रमाण यह है कि इन देशों ने प्रगतिशील और उदारवादी विचारधारा को त्याग कर इस्लाम को अपना राज्य-धर्म घोषित कर लिया है तथा 'नेहरू-लियाकत संधि' के अनुरूप वह अपने देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहे हैं, व इन देशों में अल्पसंख्यकों के धार्मिक उत्पीड़न अपने चरम पर हैं जिसकी वजह से इन देशों में अल्पसंख्यक आबादी दिन प्रति दिन घटती जा रही है और वहाँ उनका जीवन नर्क हो गया हैं। अंततः, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव के लिए यह एक उचित कदम है और इसलिए इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, जो समानता के अधिकार की बात करता है, के खिलाफ कहना तर्कसंगत नहीं है।

सुनवाई करेगा कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने संशोधन पर रोक लगाने की मांग को स्वीकार करते हुए 19 मार्च 2024 को सुनवाई रखी है। न्यायालय का फ़ैसला कुछ भी हो, लेकिन इस संशोधन ने यह साबित कर दिया है की धर्मनिरपेक्ष भारत एक संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य है और शायद यही कारण है कि शासकीय रूप से धार्मिकता से आबाद व ओत-प्रोत देशों के नागरिक अपने देश की नागरिकता को त्याग कर भारतीय नागरिकता पाने को आतुर हैं, जो भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतिबिंब है।

पीड़ितों को नागरिकता देने का सार्थक प्रयास

विवेचना
प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के नियम अधिसूचित कर दिए हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल इस कानून का इसलिए दुष्प्रचार करते रहे हैं कि इससे मुसलमानों की नागरिकता संकट में पड़ जाएगी, जबकि इसमें देश के किसी भी धर्म से जुड़े नागरिक की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है, हां घुसपैठियों को जरूर नागरिकता सिद्ध नहीं होने पर बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। संसद और उसके बाहर ऐसे अनेक बौद्धिक आलोचक थे, जो यह प्रमाणित करने में लगे थे कि यह कानून 'आइडिया ऑफ इंडिया' अर्थात संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है, लेकिन यह संदेह जम्मू-कश्मीर से हटाई गई धारा-370 और 35-ए की तरह ही संवैधानिक है।

भेदभाव से जुड़ा नहीं

इस कानून से भारत में आकर शरणार्थी जीवन जी रहे इन समुदायों के लोगों को अब देश की नागरिकता मिलनी आसान हो जाएगी। नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन भी ऑनलाइन जारी कर दिया है। इसे शरणार्थी जरूरी दस्तावेजों के साथ भरकर नागरिकता की मांग कर सकते हैं। आवेदन करने वालों को 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश का वीजा और अप्रवासी होने के प्रमाण देने होंगे। धारा 5 के अंतर्गत अप्रवासी मुस्लिम या कोई भी विदेशी नागरिक आवेदन कर सकते हैं। पहले भी इन तीनों देशों के मुसलमानों को भारतीय नागरिकता दी जा चुकी है। यह व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। जाहिर है, यह कानून किसी धर्म या संप्रदाय के आधार पर भेदभाव से नहीं जुड़ा है। साफ है, यह कानून किसी की नागरिकता छीनने का नहीं, बल्कि देने का कानून है।

पाक में अल्पसंख्यक प्रताड़ित

यह विधेयक मूल रूप में 1955 के नागरिकता विधेयक में ही कुछ परिवर्तन करके अस्तित्व में लाया गया है। 1955 में यह कानून देश में दुखद विभाजन के कारण बनाया गया था। इस समय बड़ी संख्या में अलग-अलग धर्मों के लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। कुछ लोग भारत से पाकिस्तान भी गए थे। इस आवागमन में सांप्रदायिक दंगे भी हुए। बावजूद भारत ने धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश बनाने का निर्णय लिया। लेकिन पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। पाक के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के प्रजातांत्रिक सिद्धांत तत्काल नेस्तनाबूद कर दिए गए। 1948 में जिन्ना की मौत के बाद पाकिस्तान पूरी तरह कट्टर मुस्लिम राष्ट्र में बदलता चला गया। नतीजतन जो भी गैर-मुस्लिम समुदाय थे, उन्हें प्रताड़ित करने के साथ उनकी स्त्रियों के साथ दुराचार व धर्म परिवर्तन का सिलसिला तेज हो गया। ऐसे में ये पलायन कर भारत आने लगे। दरअसल इन गैर-मुस्लिमों का भारत के अलावा कोई दूसरा ठिकाना इसलिए नहीं था, क्योंकि पड़ोसी अफगानिस्तान भी कट्टर इस्लामिक देश बन गया था। 1955 तक ही करीब 45 लाख हिंदू और सिख भागकर भारत आ गए थे। इनको ही दृष्टिगत रखते हुए नागरिकता निर्धारण विधेयक 1955 बनाया गया था। 1971 में जब

पाकिस्तान से अलग होकर नया बांग्लादेश बना तो इस दौरान हिंदू समेत अन्य गैर-मुस्लिमों पर विकट अत्याचार हुए। फलतः इनके पलायन और धर्मस्थलों को तोड़ने का सिलसिला और तेज हो गया। नतीजतन बड़ी संख्या में हिंदुओं के साथ बांग्लादेशी एवं पाकिस्तानी मुस्लिम भी बेहतर भविष्य के लिए भारत चले आए, जबकि वे धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं थे। ये घुसपैठिए बनाम शरणार्थी पूर्वोत्तर के सातों राज्यों समेत पश्चिम बंगाल में भी घुस आए। इनकी संख्या तीन करोड़ तक बताई जाती है। शरणार्थियों की तो सूची है, लेकिन घुसपैठिए केवल अनुमान के आधार पर हैं। इन घुसपैठियों और शरणार्थियों की सही पहचान करने की दृष्टि से ही यह नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया है।

अमल नहीं हुआ

दरअसल मुस्लिम घुसपैठियों को बाहर करने की बात इनकी भारत में दस्तक शुरू होने के साथ ही हो गई थी। 26 सितंबर 1947 को एक प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान में जो हिंदू एवं सिख प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनकी मदद हम करेंगे। 1985 में केंद्र में जब राजीव गांधी की सरकार थी, तब असम में घुसपैठिओं के विरुद्ध जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। नतीजतन राजीव गांधी और आंदोलनकारियों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें घुसपैठियों को क्रमबद्ध खदेड़ने की शर्त रखी गई, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। डॉ मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए सदन में कहा था कि यदि पाकिस्तान व बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यक प्रताड़ित किए जा रहे हैं और वे पलायन को मजबूर हुए हैं, तो उन्हें भारतीय नागरिकता दी जानी चाहिए। किंतु मनमोहन सिंह ने लगातार दस साल प्रधानमंत्री बने रहने के बावजूद इस दिशा में कोई स्थाई कानूनी पहल नहीं की, जबकि असम में इस दौरान कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह यहीं से राज्यसभा सदस्य थे। यदि नेहरू और लियाकत अली के बीच हुए समझौते का पालन पाक ने किया होता तो भारत को इस विधेयक की न तो 1955 में बनाने की जरूरत पड़ती और न ही इसमें अब संशोधन किया गया होता।

बदतर जीवन गुजार रहे

अफगानिस्तान में 2 लाख हिंदू और सिख थे। जो निरंतर प्रताड़ना के चलते महज 500 रह गए हैं। पाक ने दोगली मंशा के चलते बंटवारे के समय दलित हिंदुओं को केवल इसलिए रोक कर रखा, जिससे वे वहां गंदगी और मल-मूत्र साफ करते रहें। इन्हें आज भी न तो वोट का अधिकार प्राप्त है और न ही ये वहां चल रही लोक-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले पाते हैं। इन्हें किसी भी तरह का चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं है। नतीजतन ये 1947 से भी ज्यादा बदतर जीवन ये वर्तमान में गुजार रहे हैं। जब बांग्लादेश वजूद में आया, तब वहां, बांग्लादेष की आजादी की लड़ाई लड़ रहे मुक्ति संग्राम के जवानों ने गैर-मुस्लिम स्त्री व पुरुषों के साथ ऐसे दुराचार व अत्याचार किए कि वे भारत की ओर पलायन करने को मजबूर हुए। इन लोगों की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा थी। बांग्लादेश के समाज के मिजाज पर निगाहें रखने वाले समाजशास्त्री इस्माइल सादिक, रॉबिन डिसूजा व पुरंदर देवरॉय बहुत पहले लिख चुके हैं कि 'वहां के समाज का बड़ा हिस्सा धार्मिक अल्पसंख्यकों की आजादी को पसंद नहीं करता है।

शर्तों में छूट

मूल नागरिकता कानून में किसी को भी भारत का नागरिक बनने के लिए लगातार 11 वर्षों तक भारत में रहने की शर्त पूरी करनी होती है। नए विधेयक में इसे घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। जो घुसपैठिए मुस्लिम हैं, वे तो किसी भी मुस्लिम देश में शरण ले सकते हैं, इसलिए इस ऐतिहासिक कानून के वजूद में आने के बाद न तो भारत की पंथ या धर्मरिपेक्षता प्रभावित होती है और न ही उसके उदार व सहिष्णु चरित्र को हानि पहुंचती है। क्योंकि भारत ने तो उदार सहिष्णुता दर्शाते हुए उन लोगों को नागरिकता का अधिकार देने के कानूनी उपाय किए हैं, जिन्हें धर्म के आधार पर इस्लामिक देशों ने प्रताड़ित किया। बहरहाल यह कानून मानवीयता के सरोकारों से जुड़ा अहम कानून है, जिसे दुनिया को एक मिसाल के रूप में देखना चाहिए।

लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व पर देश को गर्व

1.8 करोड़ वोटर्स पहली बार करेंगे मतदान, शतायु के कुल 2.18 लाख

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सबसे पहले कहा कि चुनाव का पर्व, देश का गर्व।उन्होंने बताया कि इस बार 96.8 करोड़ वोटर्स वोट डालने जा रहे हैं। यानी कि करीब 97 करोड़ लोग लोकसभा चुनाव में वोट डालेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में करीब 1.8 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं, जो पहली बार किसी चुनाव में वोट डालने वाले हैं। इसके अलावा 20-29 साल की उम्र के बीच के वोटर्स की संख्या 19.47 करोड़ है। कुल मतदाताओं में 49.7 करोड़ पुरुष, 47.1 करोड़ महिलाएं, 48 हजार ट्रांसजेंडर शामिल हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार, देशभर में मतदाता लिंगानुपात 948 है, 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि हमारी मतदाता सूची में 85 साल से अधिक उम्र के 82 लाख और सौ साल से अधिक उम्र के 2.18 लाख मतदाता शामिल हैं।

लोकसभा चुनाव की राज्यवार कुल सीटें और विभिन्न चरणों की तारीख व सीटें

राज्य	तारीख	सीटें
आंध्रप्रदेश 25	13 मई	25
अरुणाचल प्रदेश 02	19 अप्रैल	02
असम 14	19 अप्रैल	05
	26 अप्रैल	05
	7 मई	04
बिहार 40	19 अप्रैल	04
	26 अप्रैल	05
	7 मई	05
	13 मई	05
	20 मई	05
	25 मई	08
	1 जून	08
छत्तीसगढ़ 11	19 अप्रैल	01
	26 अप्रैल	03
	7 मई	07
गोवा 02	7 मई	02
गुजरात 26	7 मई	26
हरियाणा 10	25 मई	10
हिमाचल प्रदेश 04	1 जून	04
झारखंड 14	13 मई	04
	20 मई	03
	25 मई	04
	1 जून	03
कर्नाटक 28	26 अप्रैल	14
	7 मई	14
केरल 20	26 अप्रैल	20
मध्यप्रदेश 29	19 अप्रैल	06
	26 अप्रैल	07
	7 मई	08
	13 मई	08
महाराष्ट्र 48	19 अप्रैल	05
	26 अप्रैल	08
	7 मई	11
	13 मई	11
	20 मई	13
मणिपुर 02*	19 अप्रैल	02
	26 अप्रैल	01
पंजाब 13	1 जून	13
नगालैंड 01	19 अप्रैल	01
ओडिशा 21	13 मई	04
	20 मई	05
	25 मई	06
	1 जून	06
मिजोरम 01	19 अप्रैल	01
राजस्थान 25	19 अप्रैल	12
	26 अप्रैल	13
सिक्किम 01	19 अप्रैल	01
तेलंगाना 17	13 मई	17
त्रिपुरा 02	19 अप्रैल	01
	26 अप्रैल	01
उत्तर प्रदेश 80	19 अप्रैल	08
	26 अप्रैल	08
	7 मई	10
	13 मई	13
	20 मई	14
	25 मई	14
	1 जून	13
उत्तराखंड 05	19 अप्रैल	05
मेघालय 02	19 अप्रैल	02
पश्चिम बंगाल 42	19 अप्रैल	03
	26 अप्रैल	03
	7 मई	04
	13 मई	08
	20 मई	07
	25 मई	08
	1 जून	09
अंडमान और निकोबार 01	19 अप्रैल	01
चंडीगढ़ 01	1 जून	01
दादर नगर हवेली 2	7 मई	02
जम्मू-कश्मीर 5	19 अप्रैल	01
	26 अप्रैल	01
	7 मई	01
	13 मई	01
	20 मई	01
लद्दाख 01	20 मई	01
लक्षदीप 01	19 अप्रैल	01
दिल्ली 07	25 मई	07
पुडुचेरी 01	19 अप्रैल	01

*मणिपुर में एक सीट पर दो चरणों में चुनाव कराए जाएंगे।

खबर संक्षेप

मशहूर गायिका पौडवाल भाजपा में शामिल

नई दिल्ली। मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल शनिवार को भाजपा में शामिल हो गईं। उन्होंने नई दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अपने हिट गानों और भक्ति संगीत के लिए मशहूर गायिका ने पार्टी में शामिल होने पर खुशी भी जताई और कारण का भी खुलासा किया। पौडवाल ने कहा, हम ऐसी सरकार से खुश हैं, जिसका सनातन धर्म से गहरा संबंध है।

सीतापुर मार्ग पर रिसॉर्ट की छत गिरी, 8 दबे

सीतापुर। यहां पर स्थित एक रिसॉर्ट में शुक्रवार देर रात को निर्माण के दौरान बल्ली गिरने से छत भी गिर गई जिसके नीचे 8 श्रमिक दब गए। 6 श्रमिक बाहर निकाले गए हैं। 2 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई गजपतिपुर गांव में बहराइच सीतापुर मार्ग पर एक रिसॉर्ट स्थित है। यह होटल जिले के डॉ. अनिल केडिया का है। होटल में इस समय निर्माण कार्य चल रहा है।

आरएलपी के बेनीवाल ने ज्वॉइन की भाजपा

जयपुर। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से पहले हनुमान बेनीवाल को तगड़े सियासी झटके लगे हैं। बेनीवाल की पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पुखराज गर्ग ने ही साथ छोड़ दिया। गर्ग ने पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। बेनीवाल ने भी इस्तीफा दे दिया था। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ ने इनका स्वागत किया।

पीएम का पहले हैदराबाद फिर कर्नाटक का दौरा, लोकसभा में 370 का लक्ष्य

कांग्रेस चाहे कितने भी कपड़े बदल ले, उसकी 'करतूतें' नहीं बदलेंगी

कलबुर्गी में बोले मोदी-यह जनसैलाब और उत्साह भाजपा की रिकॉर्ड जीत को बता रहे

एजेंसी ⏭ कलबुर्गी

पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दक्षिण के 2 राज्यों का दौरा किया। लोकसभा चुनावों में 370 सीटें जीतने के लक्ष्य के लिए पीएम मोदी जी जान से जुटे हैं। वे लगातार रैलियां कर रहे हैं। पहले पीएम मोदी ने तेलंगाना का दौरा किया। इसके बाद वेकर्नाटक पहुंचे। कर्नाटक के कलबुर्गी में उन्होंने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। आज पूरा कर्नाटक कह रहा है कि अबकी बार 400 पार। उन्होंने कहा कि कलबुर्गी का ये जनसैलाब और आप सबके चेहरों का ये उत्साह, कर्नाटक ने लोकसभा के चुनाव में भाजपा को रिकॉर्ड सीटों पर जिताने का संकल्प ले लिया है आप सभी ने चुनाव की घोषणा पहले ही घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, जो चाहे कितने भी कपड़े बदल ले, उसकी करतूतें नहीं बदलती। इसलिए कर्नाटक में जनता जाग चुकी है, आक्रोश और गुस्से से लाल है। इतने कम समय में ही जनता का मोहभंग हो जाना दिखाता है कि लोगों को कांग्रेस की सच्चाई का पता चल गया है।

पीएम की दक्षिण के राज्यों में रैलियां

परिवारवादियों के लिए भ्रष्टाचार ही ऑक्सीजन

उन्होंने कहा कि एक बार कोयले से कालिख दूर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस से करप्शन दूर नहीं हो सकता। इन परिवारवादियों के लिए भ्रष्टाचार ही ऑक्सीजन है। बिना भ्रष्टाचार के ये लोग सियासत में सांस भी नहीं ले सकते। कर्नाटक को कांग्रेस ने परिवार एटीएम बना लिया है। पार्टी और परिवार के खर्चे पूरे करने के लिए जनता की कमाई यहां से सप्लाई की जा रही है।

स्कॉलरशिप में कटौती कर रहे

पीएम ने कहा कि ये लोग युवाओं से बड़े-बड़े वादे करके सरकार में बैठ गए, लेकिन आज ये उन्हीं युवाओं की स्कॉलरशिप रोक रहे हैं। स्कॉलरशिर में कटौती कर रहे हैं। ये कांग्रेस नौजवानों का हक मारने का पाप कर रही है। कांग्रेस की लूट का हाल ये है कि छोटे-छोटे विकास कार्यों के लिए भी सरकार के पास पैसे ही नहीं है। कोई सरकार ऐसे चल सकती है क्या?

भारत लोकतंत्र की जननी

पीएम मोदी ने कहा कि जब हम कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है तो पूरी दुनिया उसे स्वीकार करती है। दुनिया को कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब ये बात कांग्रेस वाले सुनते हैं तो सुनते ही उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये लोग दुनिया भर में जाकर हमारे देश को, हमारे लोकतंत्र को, हमारी महान परंपराओं को बदनाम करते हैं।'

नगरकुर्नूल में जनसभा में बोले पीएम मोदी

तेलंगाना चक्की के दो हिस्सों में पिसता रहा

हैदराबाद। पीएम मोदी तेलंगाना के नगरकुर्नूल में वह एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में 2024 के चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है। तारीखों के औपचारिक एलान के पहले ही देश की जनता ने, देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है- अबकी बार 400 पार। पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव के दौरान मैं यहां आया था तब मैंने देखा था कि जनता के दिल और दिमाग में बीआरएस के खिलाफ इतना गुस्सा था और उसका नतीजा भी हमने देखा कि उसका क्या हाल हुआ? अब तेलंगाना के लोगों ने मोदी को फिर से वापस लाने का फैसला सुना दिया है।

पहले बीआरएस की महा लूट और अब कांग्रेस की बुरी नजर

पीएम ने कहा कि तेलंगाना को हमारे देश में 'गेटवे ऑफ साउथ' कहा जाता है। यह एनडीए और मोदी की प्राथमिकता रहा है, इन 10 वर्षों में हमने देखा कि कैसे तेलंगाना चक्की के दो हिस्सों में पिसता रहा है जिसमें एक हिस्सा कांग्रेस का और दूसरा हिस्सा बीआरएस का था? कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर तेलंगाना

दशकों तक केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया, भाजपा ने हालात बदले

पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया। लेकिन, गरीब के जीवन में कोई बदलाव आया क्या? कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को वोटबैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। समाज के हालात नहीं सुधरे। जब देश ने मोदी को पूर्ण बहुमत का आशीर्वाद दिया, सारे हालात बदल गए। भाजपा बदलाव की एक ही गारंटी है। मोदी की गारंटी।

केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत

15 हजार के मुचलके व एक लाख राशि पर दी जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में समन की अनदेखी के खिलाफ याचिका दायर की थी। अदालत में केजरीवाल के वकील ने कहा कि सीएम के खिलाफ जिन धाराओं का मामला दर्ज है वे जमानती हैं। केजरीवाल के वकील ने बॉन्ड भरवाकर जमानत की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने 15 हजार के निजी मुचलके पर दी केजरीवाल को जमानत दे दी। जमानत के बाद केजरीवाल कोर्ट परिसर से निकल गए। इस मामले में अब 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 15,000 रुपए के मुचलके और 1 लाख रुपए जमानत राशि पर बेल दे दी है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले के संबंध में ईडी की दो शिकायतों के आधार पर अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के बाद सीएम अदालत में पेश हुए थे।

वकील ने गिरफ्तारी को बताया अवैध

कविता बोलीं- पूरी ताकत से अदालत में लड़ेंगे व जीतेंगे

नई दिल्ली। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर की बेटी के. कविता को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में ये गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने शनिवार को बीआरएस नेता के. कविता को दिल्ली की अदालत में पेश किया। इस दौरान कविता ने कहा कि हम इसके खिलाफ अदालत में लड़ेंगे।कविता के वकील ने ईडी पर उन्हें गिरफ्तार करते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। कविता के वकील ने दिल्ली की अदालत से कहा कि ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवैध है। वहीं ईडी ने कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट समेत किसी भी अदालत में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि कविता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ईडी ने कविता पर सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया।

नायब सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार टला, इस दौरान कुछ विधायक भी राजभवन पहुंच गए थे

दिल्ली में ही हुआ था सब कुछ तय फिर दिल्ली से ही हुई 'ना', राजभवन पहुंची गाड़ियां खाली ही सचिवालय लौटीं

आनंद राणा ⏭ नई दिल्ली

राजभवन में शपथ कार्यक्रम की तैयारियां हो गई थीं। नए बनने वाले मंत्रियों के लिए सरकारी गाड़ियां पहुंच गई थी। दो-तीन विधायक और कार्यवाहक मुख्यसचिव भी राजभवन पहुंच चुके थे। कुछ विधायक राजभवन के रास्ते में थे। लेकिन अचानक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल विस्तार को टाल देने का फैसला दिल्ली में पार्टी हाईकमान ने ले लिया।

शुक्रवार रात को जब दिल्ली में मुख्यमंत्री सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक की तो बातचीत के एजेंडा में मंत्रिमंडल विस्तार, प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष कौन बनाया जाए तथा बाकी बची चार लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करना शामिल था। चारों नेताओं के बीच इन तीनों मुद्दों पर गहन मंथन हुआ। चूंकि शनिवार दोपहर तीन बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होनी है लिहाजा फैसला लिया गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार सुबह 11 बजे करा लिया जाए। राजभवन में शपथ कार्यक्रम को लेकर तैयारियां और जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने की भागदौड़ शनिवार तड़के से ही शुरू हो चुकी थी। दिल्ली की बैठक में नए मंत्रियों के नाम पर मुहर लग चुकी थी। लेकिन एकाएक 10 बजे के करीब खबर आई कि नए मंत्रियों के लिए राजभवन पहुंची गाड़ियां सचिवालय बुला ली गई हैं। मंत्रिमंडल विस्तार टलने की बात सामने आने लगी। कयास लगते रहे कि 11 बजे के बजाए शपथ ग्रहण देर से शुरू होगा लेकिन 12 बजे तक साफ हो गया कि फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार टाल दिया गया है। दिल्ली से फरमान आया कि सीएम सैनी अपने पांच मंत्रियों के साथ ही सरकार चलाएं।

कौन बनेगा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष?

नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद हरियाणा प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष बनाया जाना है। फिलहाल सैनी अध्यक्ष हैं। ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री बनाये जाने के बाद अध्यक्ष को लेकर जातीय समीकरण साधे जा रहे हैं। शाह और नड्डा के साथ हुई सैनी और मनोहर की बैठक में पंजाबी, वैश्य, यादव और जाट के अलावा दलित वर्ग से अध्यक्ष बनाए जाने पर मंथन हुआ। बताया जा रहा है कि सांसद संजय भाटिया और डॉ. कमल गुप्ता का नाम सबसे आगे है।

क्यों टला मंत्रिमंडल विस्तार?

चर्चा है कि पूर्व मंत्री अनिल विज की नाराजगी, राव इंद्रजीत द्वारा अहिरवाल से एक के बजाए दो मंत्री बनाए जाने की जिद्द, जातीय समीकरणों को साधने में पेंच और निर्दलीयों में कौन बने मंत्री जैसे कारणों के आड़े आने की वजह से मंत्रिमंडल विस्तार रोक देना पड़ा। विज को लेकर पार्टी हाईकमान में दो राय हैं। एक, उन्होंने जिस प्रकार से विधायक दल की बैठक से बाहर आकर अनुशासनहीनता दिखाई और नाराजगी खुलेआम जाहिर की उसे हाईकमान ने बहुत गंभीरता से लिया है। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव सिर पर होने की वजह से पार्टी हाईकमान ने नरमी बरती वरना विज के खिलाफ एक्शन तय था। शनिवार को विज ने कहा भी उन्हें मनाने के लिए कोई नहीं आया और न ही किसी बड़े नेता ने फोन किया। मंत्री बनाए जाने को लेकर भी उन्होंने अनभिज्ञता जतायी। इससे साफ है कि दिल्ली में पार्टी हाईकमान अनिल विज को लेकर गुस्सा है और फिलहाल उनको उनके हाल पर छोड़ देने का मन पार्टी ने बना लिया है। विज को लेकर दूसरा मत यह भी है कि वे हरियाणा में पार्टी के सबसे पुराने विधायक हैं। पार्टी को हरियाणा में खड़ा करने में उनका योगदान है। लिहाजा उनको लेकर कोई कड़ा फैसला न लिया जाए। यही वजह है कि विज को पार्टी ने कोई नोटिस नहीं दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि विज का नाम मंत्री बनने वालों की सूची में था पर उन्होंने अंतिम समय में साफ इंकार कर दिया। सूत्रों का कहना है कि दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र से मंत्रिमंडल में एक विधायक को मंत्री बनाए जाने की बात सामने आने पर राव इंद्रजीत ने पार्टी हाईकमान से एतराज जताया। राव का कहना था कि कम से कम दो मंत्री अहिरवाल से बनाए जाने चाहिए। यह भी एक कारण मंत्रिमंडल विस्तार टालने में अहम रहा। इसके अलावा जातीय समीकरणों को ढंग से साधने की जरूरत भी महसूस की गई। सैनी मंत्रिमंडल में पांच मंत्रियों में दो जाट, एक गुर्जर, एक ब्राह्मण, एक अनुसूचित वर्ग से हैं। जजपा के बाद अब निर्दलीय विधायकों की बैसाखी पर सरकार टकी है। एक निर्दलीय रणजीत सिंह को मंत्री बनाया जा चुका है। सरकार को समर्थन दे रहे बाकी निर्दलीय विधायकों में मंत्री बनने की होड़ लगी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के ऐन पहले पार्टी हाईकमान ने कोई विवाद खड़ा करने की बजाए विस्तार टालने का फैसला लिया।

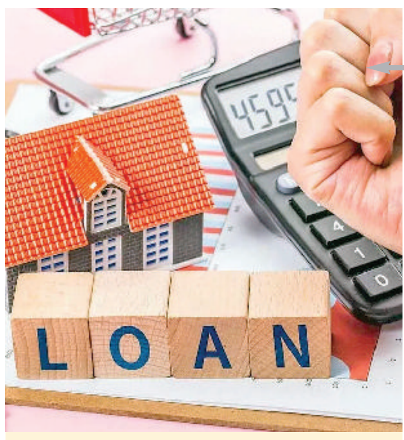

मकान खरीदने के लिए लेना है होम लोन, तो ऐसे कर लें तैयारी

जानकारी | बिजनेस डेस्क

कोई व्यक्ति कभी भी मकान खरीदता या बनवाता है, उस समय उनके हिसाब से प्रॉपर्टी प्राइस बूते से बाहर की होती है। अभी भी संपत्ति की दरें लगभग आसमान छू रही हैं। ऐसे में, होम लोन लेकर मकान खरीदना या बनवाना हमेशा फायदेमंद होता है। इस पर इंटरेस्ट रेट तो कम होता ही है, इनकम टैक्स में छूट मिलती है और सरकार से सब्सिडी भी मिलती है। लेकिन होम लोन की पात्रता या एलिजिबिलिटी हर किसी की नहीं होती। पीरामल फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर जयराम श्रीधरन हमें बता रहे हैं, वे पांच तरीके, जिस पर अमल करके आप होम लोन हासिल करने की पात्रता बढ़ा सकते हैं।

अच्छा रखें क्रेडिट स्कोर

चाहे होम लोन की बात हो या किसी भी अन्य लोन की, सबसे पहले बैंक या एनबीएफसी सामने वाले का क्रेडिट स्कोर जांचता है। किसी भी लोन लेने वाले के लोन अप्रूवल में क्रेडिट स्कोर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। साफ तरीके से कहें तो आपका क्रेडिट स्कोर यह दिखाता है कि आप अपना लोन चुकाने के लिहाज से कितने भरोसेमंद हैं। अच्छा स्कोर अक्सर साख का पर्याय होता है, और यह एक ऐसी चीज है जिस पर ऋणदाता विशेष ध्यान देते हैं। आप समय पर अपने विभिन्न किस्म के बिल और मौजूदा ऋण का समय पर भुगतान कर अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रख सकते हैं।

लंबी अवधि के लिए लें लोन

आप लोन की जो अवधि चुनते हैं, उसका आपके होम लोन के कई फैक्टर्स पर असर हो सकता है। दीर्घकालिक लोन की अवधि चुनने पर सबसे अधिक संभावना यह होती है कि आपकी ईएमआई कम होगी, और इससे होम लोन के लिए आपकी पात्रता बढ़ेगी। हालांकि लोन रिपेमेंट की लंबी अवधि चुनने पर आपको ब्याज भी ज्यादा चुकाना होगा। सीधे-सीधे कहें तो आपको पता होना चाहिए कि दीर्घकालिक ऋण अवधि चुनने पर, आपके ऋण पर भुगतान की जाने वाली कुल ब्याज राशि भी बढ़ जाएगी।

अपना डाउन पेमेंट बढ़ाएं

यदि ज़्यादा डाउन पेमेंट करना संभव हो तो ऐसा करें। क्योंकि यह फायदेमंद होता है। आमतौर पर सलाह दी जाती है कि आपका डाउन पेमेंट संपत्ति के कुल खरीद मूल्य का 10 से 20 प्रतिशत होना चाहिए। अक्सर, ऋणदाता डाउन पेमेंट को तरजीह देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे ऋण की राशि कम हो सकती है और साथ ही ऋण पर चूक की संभावना भी कम होती है।

आपकी आमदनी भी जरूरी फैक्टर

यह कहने की जरूरत नहीं है कि वित्तीय संस्थान उन उधारकर्ताओं को पसंद करते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड, रोज़गार के लिहाज़ से स्थिर हो। इसके अलावा, ज़्यादा आय वाले लोग भी होम लोन के लिए पात्र अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, क्योंकि ज़्यादा आय से उनकी बेहतर भुगतान क्षमता ज़ाहिर होती है। अपनी मौजूदा आय का आकलन करें और देखें कि यह आपकी पात्रता में मदद करती है या नहीं। यदि आपकी आय इसके अनुकूल नहीं लगती है, तो आप ज़्यादा वेतन वाली नौकरी पाने का प्रयास कर सकते हैं, या फ्रीलांस काम करने का विकल्प चुन सकते हैं। साइड बिज़नेस शुरू करना भी एक अन्य विकल्प है।

को-बोरोअर बनाएं

होम लोन लेते समय अपनी पात्रता बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, को-बोरोअर या सह-आवेदक को जोड़ना। ज़्यादातर मामलों में, परिवार का कमाऊ सदस्य जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो वह लोन के लिए अच्छा उम्मीदवार हो सकता है। सह-आवेदक के साथ मिलकर, आप अधिक ऋण राशि के लिए पात्र हो सकते हैं। अक्सर, सह-आवेदक आमतौर पर जीवनसाथी होता है, लेकिन विकल्प के तौर पर माता-पिता और भाई-बहन भी को-बोरोअर बन सकते हैं।

महिलाएं रेगुलर प्लान में कर रही ज्यादा निवेश, गोवा की औरतें सबसे आगे

महिलाओं को भा रहा म्यूचुअल फंड से खूब पैसा कमाने तरीका

निवेश मंत्रा | बिजनेस डेस्क

- न स्टॉक, न एफडी अब एमएफ में लगा रही पैसा
- महिलाओं की हिस्सेदारी 15 से बढ़कर 21% पर
- म्यूचुअल फंड महिलाओं को अपनी तरफ खींच रहा, बढ़ रहा निवेश

क्या कहते हैं आंकड़े

आंकड़ों के अनुसार, म्यूचुअल फंड में महिला निवेशकों की हिस्सेदारी मार्च, 2017 में 15 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर, 2023 में लगभग 21 प्रतिशत हो गई है। इस दौरान वृद्धि की यह गति शहरी केंद्रों की तुलना में दूर-दराज के क्षेत्र में अधिक तेज थी।

पैसा बढ़ाने के लिए हर कोई जतन करता है। हर किसी का सपना होता है कि उसके पास अच्छा पैसा हो, जिससे उसकी जिंदगी आराम से कट सके और बुढ़ापे में वह किसी पर आश्रित नहीं हो। इन दिनों म्युचुअल फंड्स में निवेश पैसार कमाने का बेहतरीन तरीका हो सकता है। म्युचुअल फंड्स में निवेश लगतार बढ़ता जा रहा है। म्यूचुअल फंड में कई निवेशकों का पैसा एक जगह जमा किया जाता है और इस फंड में से फिर बाज़ार में निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड को एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) द्वारा मैनेज किया जाता है। प्रत्येक एएमसी में आमतौर पर कई म्यूचुअल फंड स्कीम होती हैं। इनमें इन्वेस्ट करने का सही तरीका है– सबसे पहले इसका पोर्टफोलियो बनाना। एक पोर्टफोलियो, म्युचुअल फंड का एक समूह होता है। यह आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। आपका सारा रिटर्न् आपके पूरे पोर्टफोलियो पर टिका होता है, ना कि किसी एक विशेष फंड पर। अब देखने में आ रहा है कि महिलाओं को भी म्यूचुअल फंड में निवेश काफी भा रहा है। महिलाएं रेगूलर प्लान में ज्यादा निवेश कर रही हैं और अच्छा पैसा कमा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक म्यूचुअल फंड में महिला निवेशकों की हिस्सेदारी मार्च, 2017 में 15 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर, 2023 में लगभग 21 प्रतिशत हो गई है। उद्योग संगठन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के नवीनतम आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। इस साल फरवरी में म्यूचुअल फंड में प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति (एयूएम) 50 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई। बड़ी संख्या में निवेशक बचत करने और कमाई बढ़ाने के लिए म्यूचुअल फंड की ओर आ रहे हैं।

गोवा की महिलाएं सबसे आगे

एम्फी के लिए क्रिसिल द्वारा तैयार और सेबी चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 50 प्रतिशत महिला निवेशक 25-44 आयु वर्ग में आती हैं, जबकि व्यक्तिगत निवेशकों के कुल समूह में यह आंकड़ा लगभग 45 प्रतिशत है। म्यूचुअल फंड उद्योग में महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक 40 प्रतिशत गोवा में है। इसके बाद पूर्वोत्तर राज्य 30 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर हैं। चंडीगढ़, महाराष्ट्र और नई दिल्ली में भी प्रबंधन के अधीन संपत्तियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से अधिक है।

गांवों की महिलाएं भी कर रही निवेश

एएमएफआई ने कहा, ये गति शहरों की तुलना में अंदरुनी इलाकों में अधिक है, बी-30 शहरों में महिलाओं के फोलियो और संपत्ति की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत और 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई है।
कैसे लगा रहीं पैसा?

कैसे लगा रहीं पैसा?

अधिकतर महिला एमएफ निवेशक रेगुलर प्लान के माध्यम से निवेश करना जारी रखती हैं और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से निवेश करने पर लंबे समय तक निवेश करती हैं। महिला म्यूचुअल फंड वितरकों की संख्या भी बढ़ी है। दिसंबर, 2023 तक यह संख्या 42,000 अंक के करीब थी और उनकी कुल प्रबंधन अधीन संपत्ति एक लाख करोड़ रुपये से अधिक थी।

निवेश जगत में बढ़ा महिलाओं का महत्व

महिलाओं ने समय-समय पर एक बार फिर परीक्षण किया है कि निवेश की दुनिया में सफल होने के लिए उनके पास क्या है। कई शोधों से पता चला है कि जब निवेश विकल्प चुनने की बात आती है तो महिलाएं धैर्यवान, जोखिम के प्रति सचेत और दीर्घकालिक ध्यान केंद्रित करती हैं। जानकारों का कहना है कि 'हम एक आदर्श बदलाव देख रहे हैं।' महिलाएं अब केवल दर्शक नहीं हैं, वे सक्रिय रूप से अपनी निवेश यात्राओं को आकार दे रही हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में रास्ता बना रही हैं। महिलाएं शेयर बाजार विविधीकरण और रियल एस्टेट जैसे निवेश के अवसरों की खोज करके अपनी वित्तीय नियति की जिम्मेदारी ले रही हैं। वे पोर्टफोलियो में विविधता लाने और संभावित रूप से उच्च रिटर्न अर्जित करने के लिए वैकल्पिक निवेश में भी निवेश कर रही हैं।

वैकल्पिक परिसंपत्ति वर्गों के लिए भूख

अब प्रवृत्ति यह है कि जहां पारंपरिक निवेश चैनलों का अभी भी शोषण किया जा रहा है, वहीं महिलाएं अपने निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने के उद्देश्य से अन्य वैकल्पिक निवेश विकल्प भी तलाश रही हैं और इस प्रकार संभवतः उच्च रिटर्न अर्जित कर रही हैं। स्पेसमंत्रा की संस्थापक निधि अग्रवाल विस्तार से बताती हैं: "हालांकि उद्यम पूंजी, निजी इक्विटी और यहां तक कि क्रिप्टोकरेंसी जैसे वैकल्पिक निवेश महिला निवेशकों को आकर्षित करने में सबसे आगे रहे हैं, ऐसा लगता है कि वे उनकी जोखिम लेने की क्षमता और इच्छाओं के साथ काफी अच्छी तरह से संरेखित हैं जिससे उन्हें पहुंच मिलती है। उभरती प्रौद्योगिकियों और नवीनतम अत्याधुनिक क्षेत्रों के लिए।

ये टूल्स आपके काम को कर देंगे काफी आसान, चैट जीपीटी कर सकता है आपके कई सारे काम

स्टार्टअप और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बेस्ट हैं ये मुफ्त एआई टूल्स

तकनीक | बिजनेस डेस्क

- ग्रामरली इंग्लिश कंटेंट की गलतियों को दूर करने में सक्षम
- पिक्सलर फोटो को बेहतरीन बनाने का काम करेगा
- कैनवा फोटो बनाएगा, फोटो में एडिटिंग भी करेगा
- बैकग्राउंड रिमूवर टूल से इमेज के बैकग्राउंड को हटा सकेंगे

अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है, तो अब आपको सभी काम करना जरूरी नहीं है। इसके लिए कुछ ऐसे शानदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स भी मौजूद हैं जो आपके काम को काफी हद तक आसान बना सकते हैं। इनकी मदद से आपको बहुत राहत मिलेगी और काम भी समूथली हो जाएगा। इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप प्रोडक्ट फोटोशूट, कंपनी के वेबसाइट बनाने और क्रिएटिव तस्वीर बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कंटेंट राइटर हैं तो भी इन टूल्स की मदद से बेहतरीन और इनफॉर्मेटिव कंटेंट तैयार कर सकते हैं। ये एप्लीकेशंस खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहतरीन हैं, जो अपना कोई स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं। ये फ्री टूल्स हैं और शुरुआत में आप इन्हें बिना पैसे दिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इनके एडवांस्ड पेड वर्जन भी हैं, जिन्हें आप अपना काम बढ़ने पर खरीद सकते हैं। इस रिपोर्ट के जरिये जानते हैं ऐसे ही कुछ टूल्स जो आपकी लाइफ को आसान बनाने जा रहे हैं।

चैट जीपीटी एक शानदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, जिसकी मदद से आप कई सारे काम कर सकते हैं। अगर आपको स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो इसकी मदद से आपको काफी फायदा हो सकता है। अगर आप अपनी कोई कंपनी या वेबसाइट खोलना चाह रहे हैं और उसके टर्म एंड कंडीशन, पॉलिसी, कंपनी के नियम और कॉन्टैक्ट डीटेल्स लिखना चाहते हैं पर आपको आईडिया नहीं है, तो आप चैट जीपीटी को कमांड देकर ,यह सब काम बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। अगर आप कंटेंट राइटर है तो भी चैट जीपीटी की मदद से आपका काम काफी ज्यादा आसान हो सकता है। हालांकि लिखे गए कंटेंट को एक बार जरूर पढ़ना होगा, ताकि आप उनमें से काम की चीज ले सके और जो आपके काम का नहीं है, उसे हटा सके और गलतियों को भी सही कर सकें।

कैनवा

अगर आपको फोटो बनानी है, कोई इंफोग्राफिक बनानी है या फिर किसी फोटो में एडिटिंग करनी है, तो कैनवा आपके लिए एक बेहतरीन टूल साबित हो सकता है। कैनवा को आमतौर पर अलग-अलग तरह के कार्ड डिजाइन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कैनवा में आपको अलग-अलग स्टाइल से फोटो डिजाइन करने की सहूलियत मिलती है, इसके अलावा इसमें कई और आकर्षक फीचर्स हैं, जिन्हें आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाकी कुछ फीचर्स को उसे करने के लिए आपको पैसे देने होते हैं। अगर आपको कोई फोटो इस्तेमाल करना है और उसका बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा है तो इसके बैकग्राउंड रिमूव ऑप्शन में जाकर आप उस इमेज के बैकग्राउंड को हटा सकते हैं और आप अपनी फोटो को नए बैकग्राउंड के साथ अपने और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूवर टूल की मदद से आप बिना कोई पैसे खर्च की आसानी से किसी भी इमेज का बैकग्राउंड हटा सकते हैं।

ग्रामरली

इंग्लिश कंटेंट लिखते समय अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आमतौर पर हमें यह गलतियां समझ नहीं आती हैं, ऐसी छोटी-मोटी कमियां दूसरों पर हमारा खराब इंप्रेशन डाल सकते हैं। ऐसे में आप ग्रामरली एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके इन सभी गलतियों को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। यह आपके सेंटेंस फॉरमेशन में होने वाली गलतियों को सुधारने की सजेशन देता है साथ ही अगर आपने कुछ गलत स्पेलिंग दी है तो यह उसे भी हाईलाइट करके सही करने के लिए आपको सुझाव देता है। इससे आपका कंटेंट काफी ज्यादा एक्यूरेट और इंप्रेसिव बन जाता है।

पिक्सलर

आजकल कोई भी वेबसाइट या स्टार्टअप हो बिना फोटो के नहीं चलता है। अगर आप कोई भी कांटेक्ट लिख रहे हैं तो उसके लिए अट्रैक्टिव फोटो और कवर इमेज रखना बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर आप आसानी से अट्रैक्टिव फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं, तो पिक्सलर आपके लिए अच्छा विकल्प है। यह आपको एडवांस फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फोटोशॉप वाला एक्सपीरियंस देता है। हालांकि इसके कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं, जिनके लिए कंपनी चार्ज करती है।

कॉरपोरेट बॉन्ड फंडों की ओर आकर्षित होते जा रहे निवेशक

- इस समय दुनिया में महंगाई दर में नरमी के संकेत
- संभावना है कि ब्याज दर में भी कटौती हो सकती है
- इन्हीं परिस्थितियों की वजह से ही कॉरपोरेट बॉन्ड में बढ़ा रिटर्न
- एक साल में कॉरपोरेट बॉन्ड फंडों ने अच्छा परफॉर्म किया
- सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं ये फंड

बिजनेस डेस्क

इस समय दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। इसके साथ ही अब इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय बैंक भी ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं। इसका पहला संकेत अमेरिकी फेडरल रिजर्व से आया है, जो जून की शुरुआत में ब्याज दरों में कटौती शुरू कर सकता है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक भी ऐसा कदम उठा सकते हैं। इसके साथ ही, अपना रिज़र्व बैंक भी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। हो सकता है कि भारत में भी इसी तरह का फैसला हो। इन सभी कारणों को देखते निवेशक अब कॉरपोरेट बॉन्ड फंडों की ओर आकर्षित होते जा रहे निवेशक हैं। बाजार के जानकारों का कहना है कि कॉरपोरेट बॉन्ड फंडों में निवेश इस साल आपको अच्छा रिटर्न दिला सकता है ऐसे में थोड़ी सावधानी के साथ कॉरपोरेट बॉन्ड फंडों में निवेश किया जा सकता है।

कॉरपोरेट बॉन्ड का बढ़ रहा रिटर्न

ब्याज दर में बढ़ोतरी के संकेत को देखते हुए निवेशक अब फिर से कॉरपोरेट बॉन्ड फंडों की ओर दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि गिरते हुए ब्याज दरों की पृष्ठभूमि में कॉरपोरेट बॉन्ड से रिटर्न बढ़ता है। हालांकि, इन फंडों पर लागू इंडेक्सेशन बेनिफिट को समाप्त कर दिया गया है। तब भी ये फंड अभी भी लोकप्रिय इसलिए हैं क्योंकि ब्याज दर में बढ़ोतरी और कम लागत अनुपात के लाभ के साथ आते हैं। इसमें निवेश करने वाले बिना किसी परेशानी और बिना किसी रिस्क के आसानी से अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं।

सरकारी प्रतिभूतियों में होता है निवेश

कॉरपोरेट बॉन्ड फंड डेट फंड हैं जो एए+और उससे ऊपर रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। इसका उदाहरण निप्पॉन इंडिया कॉरपोरेट बॉन्ड फंड है जो 8% से अधिक वार्षिक रिटर्न दे रहा है। इस कैटेगरी के औसत से कहीं अधिक रिटर्न है। कॉरपोरेट बॉन्ड द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरें अन्य ब्याज दर में बदलाव से सीधे प्रभावित होती हैं, क्योंकि बॉन्ड की कीमतें और ब्याज दरें एक दूसरे की उलटी दिशा में होती हैं।

एक साल में अच्छा रिटर्न

जानकारों का कहते हैं कि पिछले एक साल में कॉरपोरेट बॉन्ड फंडों ने अच्छा परफॉर्म किया है। निप्पॉन इंडिया कॉरपोरेट बॉन्ड फंड ने 8.39% का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है, जबकि इस कैटेगरी के कुल फंडों में से लगभग आधे ने 8% से अधिक रिटर्न दिया है। इनमें एक्सिस कॉरपोरेट डेट फंड, एचडीएफसी कॉरपोरेट बॉन्ड फंड और बड़ौदा बीएनपी पारिबा, एचएसबीसी और आदित्य बिड़ला सन लाइफ शामिल हैं।

रिटर्न के साथ सुरक्षा

कॉरपोरेट बॉन्ड म्यूचुअल फंड जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए आदर्श हैं जो निवेश पर उच्च रिटर्न की तलाश में हैं क्योंकि वे डेट इन्स्ट्रूमेंट्स हैं और पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। टॉप कॉरपोरेट बॉन्ड फंड की समयावधि आम तौर पर 1 से 4 साल के बीच होती है, जो निवेशकों को अपनी लिक्विडिटी मेन्टेन करने की अनुमति देती है। हाई रिटर्न की पेशकश के अलावा, कॉरपोरेट बॉन्ड फंड को किसी भी समय खरीदा और बेचा जा सकता है, जिससे निवेशकों को पैसे की आवश्यकता होने पर नकदी निकालने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा, अधिकांश फाइनेंसियल एडवाइजर एक विविध, संतुलित पोर्टफोलियो बनाने के लिए इन फंडों की सलाह देते हैं।

बिजनेस आइडिया
लगातार बढ़ रही इन ईंटों की डिमांड

करोड़पति बना सकती हैं सीमेंट व राख से बनी ईंटें

बहुत ही मामूली निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं काम ▸▸ 100 गज जमीन पर दो लाख के निवेश शुरू करें

बिजनेस डेस्क

अगर आपका इरादा कम लागत से ज्यादा पैसा कमाने का है तो आप सीमेंट और राख से बनी हुई ईंट बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसकी डिमांड इस समय काफी ज्यादा बढ़ गई है। लोग बताते हैं कि इस बिजनेस को आप बहुत ही मामूली निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं। सीमेंट से बनी हुई नेट यानी फ्लाई ऐश ब्रिक का मार्केट फिलहाल धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जो आगे आने वाले समय में आपको जबरदस्त फायदा दे सकता है। जानकारी के लिए बताते चलें कि इस समय देश में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से चल रहा है और ऐसे में घर और बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटों की काफी जरूरत पड़ती है।

जबरदस्त इस्तेमाल

इस समय कंस्ट्रक्शन के तहत बनने वाली बिल्डिंग में सीमेंट की ईंटों का जबरदस्त इस्तेमाल किया जा रहा है। राख से बनी हुई किस ईंटों को बनाने के लिए कई सारे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी ये मिट्टी की बनी ईंटों से काफी हल्की होती हैं और इसे बनाने में पैसे भी काफी कम लगते हैं। घर बनाने वाले बताते हैं कि मिट्टी के बजाय अगर सीमेंट व राख से बनी ईंटों का इस्तेमाल किया जाए तो कई फायदे होते हैं। इससे आपके घर को अंदर से और बाहर से काफी जबरदस्त फिनिशिंग मिलती है। इसके साथ ही इसमें आपको प्लास्टर पर भी ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं और इस पर प्लास्टर बड़ी आसानी से किया जा सकता है।

ऐसे होंगी तैयार

अगर आपको इसका बिजनेस शुरू करना है तो आपके पास राख, फ्लाई ऐश, सीमेंट और रेट की जरूरत होती है। इसके अलावा अगर आप चाहे तो इस ईट को बनाने के लिए चूना और जिप्सम के मिक्सर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बनाने के लिए आपके पास काम से कम 100 गज जमीन होनी चाहिए और आपको मात्र 20,00,00 रुपये तक का निवेश करना होगा। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप जो मशीन खरीदने वाले हैं सबसे ज्यादा पैसे उसी में लगते हैं। उसके अलावा मशीन के जरिए ईंट बनाने के लिए आपको 5 से 6 लोगों की जरूरत पड़ती है।

ऐसे होगी मोटी कमाई

इस बिजनेस को अगर आप थोड़े बड़े लेवल पर शुरू कर रहे हैं तो बढ़िया आसानी से 1 महीने के अंदर एक लाख ईंट तैयार कर सकते हैं। हालांकि इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको काफी धैर्य की जरूरत होगी, क्योंकि एक बार ईंट को पूरी तरह बन कर तैयार और मजबूत होने में एक महीने का समय लग जाता है। अगर आप महीने में एक लाख ईंट बेचते हैं, तो काफी ज्यादा आसानी के साथ महीने का 1 लाख रुपये भी कमा सकते हैं।

5 से 6 रुपये कीमत

सीमेंट व राख से बनी हुई ये ईंटें 5 से 6 रुपये प्रति ईंट के हिसाब से बिकती हैं। यही कारण है कि आज के समय में लोगों के द्वारा इन्हें मिट्टी की ईंटों के मुकाबले इन्हें ज्यादा पसंद किया जा रहा है। ऐसे में अगर आपका बिजनेस बढ़ जाता है और आप 1 महीने में 1 लाख ईंट बेच लेते हैं तो आपको 5 से 6 लाख रुपये मिलेंगे। बिजनेस ठीक से चलने लगा तो आप सारे खर्च निकालने के बाद भी एक से डेढ़ लाख रुपये मासिक कमाई आसानी से कर सकते हैं। बड़े लेवल पर काम किया जाए तो कमाई और ज्याद भी हो सकती है।

फॉर्म में चल रही दिल्ली की नजरें पहले डब्लूपीएल खिताब पर, बेंगलोर देगी चुनौती

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

फॉर्म में चल रही दिल्ली कैपिटल्स पिछले साल चूक गई थी लेकिन अब रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ दूसरे महिला प्रीमियर लीग फाइनल में उसकी नजरें खिताब अपने नाम करने पर लगी होंगी। पिछले साल पहले सत्र के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को मुंबई इंडियंस ने सात विकेट से हराया था। इस बार दिल्ली की टीम शानदार फॉर्म में है और आठ मैचों में 12 अंक लेकर पांच टीमों की लीग में शीर्ष पर है। मेग लानिंग ने मोर्चे से अगुवाई करते हुए आठ पारियों में 308 रन बनाए हैं जबकि दक्षिण अफ्रीका की हरफनमौला मारियाने कैप और आस्ट्रेलिया की बाएं हाथ की स्पिनर जेस जोनासेन ने 11-11 विकेट लिए हैं।

महिला प्रीमियर लीग : मैच का प्रसारण आज शाम 7.30 बजे

लीग मैचों में सिर्फ दो हार

इस सत्र में दिल्ली को दो बार ही पराजय का सामना करना पड़ा जब उसे मुंबई इंडियंस और यूपी वारियर्स ने हराया। इसके अलावा उसका अभियान बेदाग रहा है। आरसीबी के खिलाफ अब तक खेले गए चारों मुकाबले उसने जीते हैं। लेकिन फाइनल में पिछला प्रदर्शन मायने नहीं रखेगा।

ओपनिंग जोड़ी से उम्मीद

यह नया दिन और नया मैच है जिसमें दबाव झेलने में कामयाब रहने वाली टीम को ही ट्रॉफी मिलेगी। दिल्ली को लैनिंग और शेफाली वर्मा से अच्छी शुरुआत मिलने की उम्मीद होगी। जेमिमा रौड्रिग्स भी मध्यक्रम में फॉर्म में है लेकिन हरफनमौला एलिसे कैप्सी और कैप से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी । गेंदबाजी में जोनासेन, कैप और शिखा पांडे ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बाएं हाथ की स्पिनर राधा यादव ने भी दस विकेट चटकाए हैं और कोटला की धीमी पिच पर उनकी भूमिका अहम होगी।

बेंगलोर वापसी करने में माहिर

आरसीबी लीग चरण में तीसरे स्थान पर रही थी लेकिन शुक्रवार को रोमांचक एलिमिनेटर में कम स्कोर बनाने के बावजूद मुंबई को पांच विकेट से हरा दिया। हरफनमौला एलिसे पैरी पर बल्लेबाजी का जिम्मा होगा जो अब तक 312 रन बना चुकी है। उन्होंने सात विकेट भी चटकाए हैं। मुंबई के खिलाफ पैरी का हरफनमौला प्रदर्शन नहीं होता तो आरसीबी नहीं जीत पाती। उन्हें हालांकि कप्तान स्मृति मंधाना, सोफी डेवाइन, रिचा घोष और सोफी मोलिनू से और सहयोगी की उम्मीद होगी। आरसीबी के गेंदबाजों खासकर रेणुका सिंह, श्रेयांका पाटिल और जॉजिया वेयरहेम को भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

डब्लूपीएल टीमें

दिल्ली कैपिटल्स : मेग लैनिंग (कप्तान) , लौरा हैरिस, तान्या भाटिया, जेमिमा रौड्रग्स, शेफाली वर्मा, एलिसे कैप्सी, मरियाने काप, शिखा पांडे, अनाबेल सदरलैंड, जेस जोनासेन, मिन्नु मनी, पूनम यादव, अरूंधति रेड्डी, टिटास साधु, राधा यादव, अश्विनी कुमारी, अपर्णा मंडल, वी स्नेहा दीप्ति।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर : स्मृति मंधाना (कप्तान), रिचा घोष , दिशा कासात, एस मेघना, इंद्राणी रॉय, सतीश शुभा, हीदर नाइट, सिमरन बहादुर, एन डि क्लर्क, सोफी डेवाइन, श्रेयांका पाटिल, एलिसे पैरी, आशा शोभना, एकता बिष्ट, केट क्रॉस, सोफी मोलिनू, श्रद्धा पोखरकर, रेणुका सिंह, जॉर्जिया वेयरहैम।

खबर संक्षेप

भारोत्तोलक अचिंत राष्ट्रीय शिविर से बाहर

नई दिल्ली। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता भारोत्तोलक अचिंत शिउली को एनआईएस पटियाला में रात में महिला होस्टल में प्रवेश करते पकड़ा गया जिसके बाद उन्हें पेरिस ओलंपिक की तैयारी के लिए लगाए गए शिविर से बाहर कर दिया गया है। यह घटना गुरुवार रात की है। पुरुषों के 73 किलो वर्ग में उतरने वाले 22 वर्ष के अचिंत को सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ा और उनका वीडियो भी बनाया। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एक अधिकारी ने कहा, 'इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अचिंत को तुरंत शिविर से जाने के लिए कहा गया।'

स्वियाटेक और सक्कारी में होगा खिताबी भिड़ंत

इंडियन वेल्स। शीर्ष रैंकिंग वाली इगा स्वियाटेक ने मार्ता कोस्तियुक को 6-2, 6-1 से हराकर बीएनपी परीबस ओपन टेनिस के फाइनल में प्रवेश कर लिया जहां उनका सामना मारिया सक्कारी से होगा। स्वियाटेक का इस साल जीत हार का रिकॉर्ड 19-2 का हो गया। वहीं सक्कारी ने वर्षाबाधित मैच में कोको गॉ को 6-4, 6-7, 6-2 से हराया। स्वियाटेक ने सक्कारी के खिलाफ पांच में से तीन मुकाबले जीते हैं। पुरुष युगल फाइनल में क्रोएशिया के निकोलो मेकटिच और नीदरलैंड के वेसले कूलहोफ ने पांचवीं वरीयता प्राप्त स्पेन के मार्शल ग्रानोलेर्स और अर्जेंटीना के होराशियो जेबालोस को 7-6, 7-6 से हराया।

मुख्य कोचों के लिए क्रूस की कार्यशाला

पुणे। हॉकी इंडिया के हाई परफॉर्मेंस निदेशक हर्मन क्रूस ने घरेलू कोचों के लिए कार्यशाला का संचालन किया जिसमें कोचिंग के आधुनिक तरीकों और जमीनी स्तर पर हॉकी के विकास पर फोकस था।

आल इंग्लैंड चैंपियनशिप : नौवें नंबर के खिलाड़ी क्रिस्टी ने 21-12, 10-21, 15-21 से हराया

सेन इतिहास रचने से चूके, आल इंग्लैंड चैम्पियनशिप के सेमीफाइनल में हारे

एजेंसी ⏭ बर्मिंघम

भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन शनिवार को यहां तीन गेम तक चले आल इंग्लैंड चैम्पियनशिप पुरूष एकल सेमीफाइनल में इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से हार गये। इससे भारत का आल इंग्लैंड चैम्पियनशिप ट्राफी जीतने का इंतजार फिर बढ़ गया। बाईस बरस के सेन 2022 में यहां उपविजेता रहे थे । वह सेमीफाइनल में 2019 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और दुनिया के नौवें नंबर के खिलाड़ी क्रिस्टी से 21-12, 10-21, 15-21 से पराजित हो गये। सेन पिछले हफ्ते भी फ्रेंच ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे थे और लगातार दूसरे हफ्ते सेमीफाइनल में उनका सफर खत्म हो गया। विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान पर काबिज सेन ने शुक्रवार को आक्रामक और विविधतापूर्ण खेल दिखाते हुए करीब 71 मिनट तक चले क्वार्टर फाइनल में जबर्दस्त प्रदर्शन करते हुए पूर्व चैम्पियन मलेशिया के ली जी जिया पर 20-22, 21-16, 21-19 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। इंडोनेशिया के नौवीं रैंकिंग वाले क्रिस्टी रविवार को होने वाले फाइनल में हमवतन एंथोनी सिनिसुका से भिड़ेंगे।

ली को हराकर किया था सेमीफाइनल में प्रवेश

लक्ष्य सेन ने जबर्दस्त प्रदर्शन करते हुए पूर्व चैंपियन मलेशिया के ली जी जिया को हराकर आल इंग्लैंड चैंपियनशिप पुरुष एकल सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। बाईस बरस के सेन 2022 में यहां उपविजेता रहे थे। उन्होंने आक्रामक और विविधतापूर्ण खेल दिखाते हुए करीब 71 मिनट तक चले क्वार्टर फाइनल में 20-22, 21-16, 21-19 से जीत दर्ज की। जीत के बाद उन्होंने कहा, 'यह अच्छा मैच था और मुझे खुशी है कि मैं जीत सका। यह दबाव को झेलने की बात थी। मुझे पता था कि उसमें वापसी करने और कड़ी चुनौती देने की क्षमता है। जब मैं 18-14 से आगे था, तब भी मुझे पता था कि थोड़ी भी कोताही बरतने पर वह मौका नहीं छोड़ेंगे। मैं उसे कोई मौका नहीं देना चाहता था।

कृष्ण-प्रतीक की जोड़ी बाहर, चुनौती समाप्त

एजेंसी ⏭ ओरलियंस

कृष्ण प्रसाद गरागा और साई प्रतीक की भारतीय जोड़ी को यहां ओरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन के पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल में सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा जिससे इस सुपर 300 टूर्नामेंट में भारतीय अभियान भी समाप्त हो गया।

दुनिया की 70वें नंबर की इस भारतीय जोड़ी को शुक्रवार रात डेनमार्क के आंद्रियास सोंडरगार्ड और जेस्पर टोफ्ट की सातवीं वरीयता प्राप्त जोड़ी से 40 मिनट में 17-21, 16-21 से हार मिली। देश की एकमात्र यह भारतीय जोड़ी लुकास रेनोयर और माएल काटोएन पर 21-14, 21-9 की जीत से अंतिम आठ में पहुंची थी। शुरूआती मैच में कृष्ण और प्रतीक की जोड़ी ने बुल्गारिया के इवान रूसेव और लियोयान स्टोयनोव को हराया था।

महिला एकल में आठवीं वरीयता प्राप्त मालविका बंसोड, तान्या हेमंत और इमाद फारूखी सामिया टूर्नामेंट के शुरू में ही बाहर हो गई थी। पुरुष एकल में तीसरे वरीय किरण जॉर्ज, मिथुन मंजूनाथ और एस शंकर मुथुसैमी सुब्रमण्यम भी शुरुआती दौर में ही बाहर गए।

समय से पहले हुई पंत की रिकवरी जिम्नास्टिक से मिला ज्यादा फायदा

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

ऋषभ पंत की मानसिक दृढ़ता और जिम्नास्टिक खेलने का अनुभव होने से इस विकेटकीपर बल्लेबाज को जल्दी रिकवरी करने में मदद मिल। दिल्ली देहरादून हाइवे पर दिसंबर 2022 में हुए भयावह कार हादसे के बाद पंत को 22 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल में खेलने की अनुमति मिल गई है। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में फिजियोथेरेपिस्ट तुलसी युवराज ने 'बीसीसीआई टीवी' से कहा, 'उसके भीतर की मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास से उसने रिहैब के दौरान हमें शत प्रतिशत देने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टरों को लगता था

कि उसे दो साल लगेंगे। एक बार एनसीए आने के बाद वह तेजी से रिकवर करता गया।' एनसीए में स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच निशांता बारदोलोइ ने कहा, 'ऋषभ की जिम्नास्टिक की पृष्ठभूमि होने से हमें काफी मदद मिली। कई चीजों में यह बड़ा काम आया मसलन जब उसे लगता कि वह आगे नहीं बढ़ सकता है तो वह दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो पाता था।'

भारत से बाहर हो सकता है आईपीएल का दूसरा चरण

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड लोकसभा चुनाव को देखते हुए आईपीएल 2024 के दूसरे चरण का आयोजन भारत से बाहर करने पर विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई के अधिकारी यूएई में हैं और आईपीएल का दूसरा चरण गल्फ देश में कराने की संभावना तलाश रहे हैं। यह फैसला इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीख आईपीएल के दूसरे चरण से टकरा सकती रही हैं। चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद अब बीसीसीआई आईपीएल का अगला चरण देश के बाहर कराने पर कोई अंतिम निर्णय ले सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई के अधिकारी ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल बोर्ड के कुछ शीर्ष अधिकारी दुबई में हैं और आईपीएल का दूसरा चरण दुबई में कराने की संभावनाओं को देख रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ फ्रेंचाइजी ने खिलाड़ियों से उनके पासपोर्ट जमा करने के लिए भी कह दिया है।

लिवरपूल ने स्पार्टा को 6-1 से रौंद क्वार्टर में बनाई जगह ...

लंदन। लिवरपूल ने यूरोपा लीग में शानदार प्रदर्शन का क्रम जारी रखते हुए स्पार्टा को 6-1 से रौंदकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अंतिम-16 के पहले चरण में लिवरपूल ने स्पार्टा पर 5-1 से जीत हासिल की थी। गुरुवार की रात मिली जीत में लिवरपूल के लिए कोडी गाक्पो (14, 55 मिनट) ने दो गोल किए। स्टार स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने भी 10वें मिनट में एक गोल दागा।

हरिभूमि क्लासीफाइड विज्ञापन

ज्योतिष

इंडिया के नं 1 तांत्रिक गुरु भवानी जी
खुला चैलेंज 2 घंटो में घर बैठे फोन पर गारंटिड लाभ

7 इल्मों के माहिर
आपके विश्वास का एक ही नाम
21 सालों से एक ही स्थान पर
स्पे. महावशीकरण, मुठकरनी
लवमैरिज, मनचाहा प्यार, वशीकरण ग्रहक्लेश, जादू-टोना, शादी कारोबार रुकावट, रुठे मनाना, किया-कराया पति-पत्नी अनबन, सौतन-दुश्मन छुटकारा, कोर्ट कचहरी आदि
9988289203

सूचना

सभी पाठकों से अनुरोध है कि हरिभूमि समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापनों (डिस्पले/क्लासीफाईड) में दिए गए तथ्यों/दावों के बारे में अपने विवेक से निर्णय लें और विज्ञापन के दावों की विश्वसनीयता को परखें। हरिभूमि समूह के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की विज्ञापनों के तथ्यों से सम्बन्धित कोई जिम्मेवारी नही होगी।

ज्योतिष

मात्र 5 घंटे में घर बैठे समाधान
21 सालो के तर्जुबेकार
लाखो-करोड़ो लोगो का कार्य करने वाले
तंत्र-मंत्र के सम्राट
मिया मूसा जी
Gold Medalist
प्यार एवं कारोबार में चोट खाये तुरन्त फोन करें।
स्पे. महावशीकरण, मुठकरनी
प्रेम विवाह, ग्रहक्लेश, मनचाहा प्यार, किया कराया, कारोबार रूकावट, तलाक, सौतन-दुश्मन से छुटकारा, शादी में रुकावट, लवमैरिज A to Z समाधान।
अगर किसी का पति, प्रेमी या बेटा-बेटी किसी के वश में हो तो अवश्य फोन करें।
9878685639

जॉब

☞ भारतीय वनविभाग ने निकाला वामपर ऑफर, वनविभाग में 5070 सीट पर सीधी पक्की भर्ती, परमानेंट वैसेस पर (10th, 12th पास) लड़का लड़कियां आवेदन करें, पद- फॉरेस्टगार्ड क्लर्क, चपरासी, माली, सैलरी-(28670 से 35670), कॉल या व्हाट्सअप करे-9046968782

टी 20 विश्व कप में रोहित से बेहतर है कोहली का रिकॉर्ड

नई दिल्ली। देश में भले ही आईपीएल 2024 को लेकर रोमांच चरम पर पहुंच चुका है, लेकिन क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें आईपीएल के ठीक बाद होने वाले टी20 विश्व कप पर भी टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि आईपीएल में किए गए प्रदर्शन के आधार पर ही अजित अगरकर की अगुआई वाली चयनसमिति इस वैश्विक टूर्नामेंट के लिए टीम का चयन करेगी। युवा सहित कई अनुभवी खिलाड़ी अमेरिका और वेस्टइंडीज की संयुक्त मेजबानी में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो लंबे समय से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इन दोनों पर एक बार फिर जिम्मेदारी रहेगी। रोहित और कोहली अलग शैली के बल्लेबाज हैं। रोहित 2007 में खेले गए पहले टी20 विश्व कप टीम का भी हिस्सा रहे थे और कोहली से पहले ही इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन पूर्व कप्तान कोहली का बल्ला टी20 विश्व कप में जमकर आग उगलता है और आंकड़ों पर नजर डालें तो कोहली इस टूर्नामेंट में रन बनाने के मामले में रोहित से काफी आगे हैं।भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अब तक कुल आठ टी20 विश्व कप खेल चुके हैं, जबकि कोहली पांच बार इस वैश्विक टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कोहली को पहली बार 2012 में टी20 विश्व कप टीम में शामिल किया गया था और उस समय रोहित अपने करियर का चौथा टी20 विश्व कप खेलने उतरे थे।

रोहित का प्रदर्शन

साल	रन	औसत	स्ट्राइक	अर्धशतक
2007	88	-	144.3	01
2009	131	32.75	122.4	01
2010	84	84	155.6	01
2012	82	41	130.2	01
2014	200	40	123.5	02
2016	88	17.6	107.3	00
2021	174	34.8	151.3	02
2022	116	19.33	106.4	01

कोहली का प्रदर्शन

साल	रन	औसत	स्ट्राइक	अर्धशतक
2012	185	46.25	122.5	02
2014	319	106.33	129.2	04
2016	273	136.5	146.8	03
2021	68	34	100	01
2022	296	98.67	136.4	04

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 Cr. P.C देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त व्यक्ति **मुकुंद किशोर कोटनाला** पुत्र सुरेश आनंद कोटनाला निवासी मकान नं. एस–5/793, गायत्री भवन के सामने, शालीमार गार्डन, साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश ने **प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 347/2014 धारा 354D/506/509 भा.द.सं.** जगतपुरी, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **मुकुंद किशोर कोटनाला** मिल नहीं रहा है और समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **मुकुंद किशोर कोटनाला** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा करते हुए अभियुक्त **मुकुंद किशोर कोटनाला** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष या (मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए **दिनांक 16.04.2024** को या उसके पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
सुश्री श्रुति शर्मा,
मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट (महिला कोर्ट)–01,
शाहदरा, कमरा नं 55,
कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली

DP/2680/SHD/2024
(Court Notice)

हरिभूमि कम्यूनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक देवेन्द्र सिंह बाल्यान द्वारा हरिभूमि पब्लिकेशंस, चुलियाना मोड़, दिल्ली रोड, रोहतक-124517 से मुद्रित एवं हरिभूमि कार्यालय, 129, ट्रांसपोर्ट सैंटर, पंजाबी बाग, पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली-110035 से प्रकाशित। सम्पादक : डॉ.हिमांशु द्विवेदी। आरएनआई नं 69631/1998, फोन : 011-40451115/16, 40451109

सीडीएस चौहान ने पाक को लेकर बताई चौंकाने वाली बात

पाक भले ही आर्थिक रूप से कमजोर फिर भी...वह हमारे लिए है बड़ा खतरा

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि पाकिस्तान भले ही आर्थिक रूप से कमजोर चल रहा है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान हमारे लिए खतरा है।

साथ ही सीडीएस ने चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को लेकर भी चिंता जाहिर की। एक कार्यक्रम में सीडीएस ने कहा कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम हैं। सीडीएस ने कहा कि पाकिस्तान सैन्य तौर पर अभी भी काफी मजबूत है और हम इससे वाकिफ हैं।

सबसे बड़ी चुनौती: चीन का उभार और सीमा विवाद

कार्यक्रम के दौरान सीडीएस अनिल चौहान से पूछा गया था कि 21वीं सदी में भारत के सामने सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती क्या है? इसके जवाब में सीडीएस ने कहा कि 'जहां तक सुरक्षा बलों की बात है, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन का उभार और चीन के साथ जारी सीमा विवाद है। हमारे दो पड़ोसी हैं, जिनके साथ हमारे मतभेद हैं। दोनों देश हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी दोस्ती का दावा करते हैं और दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश भी हैं।

लड़ाई की बदलती परिभाषा भी बड़ी चुनौती

सीडीएस ने सेना के सामने जो सबसे बड़ी एक और चुनौती बताई वो है लड़ाई की बदलती परिभाषा। उन्होंने कहा कि हमें नए हथियारों, तकनीक और रणनीति की जरूरत है, साथ ही संगठन के स्तर पर भी बड़े बदलाव करने पड़ेंगे।

पोखरण सैन्य अभ्यास

सीडीएस चौहान का यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब सेना भारत शक्ति नाम से अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक पोखरण में सैन्य अभ्यास कर रही है। उन्होंने कहा कि सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं और हमारे पास सीमाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं।

लंबी लड़ाई बड़ी चुनौती

सीडीएस से पूछा गया कि क्या आर्थिक रूप से कमजोर पाक अभी भी भारत के लिए खतरा है? सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि पाक भले ही आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और राजनीतिक रूस से भी अस्थिर है, लेकिन सैन्य तौर पर उनकी क्षमताओं के बारे में हमें कोई शक नहीं है। हमें इसके लिए विरोधी देश को पूरे अंक भी देने चाहिए। उन्होंने अपने आप को काफी मजबूत किया है। ऐसे में पाक अभी भी भारत के लिए खतरा बना हुआ है।

भारत से रेस में मिली पटखनी

'चीनी चंद्र मिशन' को झटका अंतरिक्ष में गायब 2 सैटेलाइट

एजेंसी ▶▶ बीजिंग

भारत के साथ 'मिशन मून' को लेकर मुकाबले में उतरे चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है और उसका चंद्रमा मिशन फेल हो गया है। उसके 2 सैटेलाइट अंतरिक्ष में गायब हो गए हैं। चीन के 2 रॉकेट चंद्रमा मिशन पर थे, वो टेक्निकल वजहों से अपने रास्ते से भटक गया और अंतरिक्ष में गायब होने के बाद नियोजित कक्षा में पहुंचने से नाकाम हो गया है। डीआरओ-ए और डीआरओ-बी के नाम वाले इन दोनों उपग्रहों को 13 मार्च को सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था।

डीआरओ-ए और डीआरओ-बी सैटेलाइट्स किए थे लांच

डीआरओ-ए और डीआरओ-बी के नाम इन दोनों सैटेलाइट्स को युआनझेंग-1एस अपर स्टेज एयरक्राफ्ट से अंतरिक्ष में ले जाया गया था, जिसमें लॉन्ग मार्च-2सी कैरियर रॉकेट जुड़ा हुआ था। रॉकेट का पहला और दूसरा चरण सामान्य रूप से संचालित हुआ, जबकि ऊपरी चरण में उड़ान के दौरान एक असामान्यता का सामना करना पड़ा, जिससे उपग्रह, पूर्व निर्धारित कक्षा में सटीक रूप से प्रवेश करने में नाकाम हो गए।

यूएन में 'इस्लामोफोबिया' प्रस्ताव

पाक का यूएन में राम मंदिर का जिक्र भारत ने धो डाला, इस्लाम पर पढ़ाया पाठ

एजेंसी ▶▶ वॉशिंगटन

पाकिस्तान की ओर से संयुक्त राष्ट्र में 'इस्लामोफोबिया' पर प्रस्ताव लाने के मुद्दे पर भारत ने समेत कई देशों ने दूरी बना ली। मगर पाक ने जब अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र किया तो भारत आग बबूला हो गया। भारत ने ऐसा जवाब दिया कि पाक की पूरी दुनिया के सामने बोलती बंद हो गई। भारत ने 'इस्लामोफोबिया' को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाक की ओर से पेश और चीन द्वारा सह-प्रायोजित प्रस्ताव से दूरी बनाते हुए कहा कि केवल एक धर्म के बजाय हिंदू, बौद्ध, सिख और हिंसा व भेदभाव का सामना करने वाले अन्य धर्मों के खिलाफ 'धार्मिक भय' की व्यापकता को भी स्वीकार किया जाना चाहिए।

अन्य धर्मों के साथ भी न हो भेदभाव

कंबोज ने कहा कि इस्लामोफोबिया का मुद्दा निस्संदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वीकार करना चाहिए कि अन्य धर्म हिंसा का सामना कर रहे हैं। अन्य धर्मों के सामने आने वाली समान चुनौतियों की उपेक्षा करके इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए संसाधनों का आवंटन अनजाने में असमानता की भावना को कायम रख सकता है। दुनिया में 1.2 अरब हिंदू धर्म, 53.5 करोड़ बौद्ध धर्म और 3 करोड़ सिख धर्म, सभी धार्मिक पूर्वाग्रह की चुनौती का सामना कर रहे हैं। समय आ गया है कि सभी धर्मों के प्रति पूर्वाग्रह की व्यापकता को स्वीकार करें।